# चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 03 फरवरी –09 फरवरी 2014 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467


# मोदी को कौन चुनौती देगा




सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

**देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ? कयासों और दावों के बीच नाम तो कई हैं, लेकिन सभी नामों के साथ उम्मीद और नाउम्मीद का संशय जुड़ा हुआ है. राहुल बनाम मोदी का एक आकलन ज़रूर है, लेकिन चुनाव नजदीक आने तक जाहिर तौर पर राजनीतिक परिदृश्य बदलेंगे, तब उसमें नए खिलाड़ी भी होंगे और नए मोहरे भी. हालांकि नरेंद्र मोदी की तस्वीर जिस तरह राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आई, उससे संभावनाओं का एक प्रश्न प्रबल होता जा रहा है कि उन्हें कौन चुनौती देगा ?**

मनीष कुमार

अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने की पहली बार सहमति दी, उसी दिन कांग्रेस के लिए सबसे बुरी ख़बर मीडिया की सुर्ख़ियां बनीं. 23 जनवरी को राहुल गांधी अमेठी में थे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पहली बार यह कुबूला कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है, तो वह प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. शाम का वक्त था, टीवी पर दनादन ब्रेकिंग न्यूज चलनी शुरू हो गई कि राहुल प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए हैं. लेकिन ठीक एक घंटे बाद चार–पांच बड़े न्यूज चैनलों पर चुनावी सर्वे का दौर शुरू हुआ. सर्वे रिपोर्टों का नतीजा एक ही था, कांग्रेस का सफाया. इन नतीजों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा में 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी. हालांकि सर्वे रिपोर्ट गलत साबित होती हैं, लेकिन जब सभी सर्वे रिपोर्टों का नतीजा एक जैसा हो, तो इससे देश का मूड समझ में आ ही जाता है. हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजे इस बात के संकेत हैं कि देश में कांग्रेस के ख़िलाफ लहर ज़रूर है. वैसे भी, जिस तरह से लोग यूपीए सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार, घोटालों और सबसे अहम महंगाई से इतने परेशान हो चुके हैं कि यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद चुनाव आते–आते यह कांग्रेस विरोधी लहर किसी सुनामी का रूप धारण कर ले और कांग्रेस पार्टी 60–70 सीटों में सिमट कर रह जाए.

इन सर्वे रिपोर्टों के मुताबिक, देश में प्रधानमंत्री पद के सबसे चहेते उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं. इसमें भी कोई शक नहीं है कि देश में नरेंद्र मोदी ने खुद को सबसे सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया है. मोदी विरोधियों और कांग्रेस पार्टी की यह दलील गलत साबित हुई है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ़ गुजरात के नेता हैं और गुजरात के बाहर उनका कोई करिश्मा नहीं है. हर चुनावी सर्वे में देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद हैं. कांग्रेस पार्टी को यह सबक लेना चाहिए कि कोर्ट में केस डालकर राजनीति करना उसके लिए महंगा पड़ा है. एनजीओ के जरिए राजनीति करने की वजह से कांग्रेस पार्टी न तो गुजरात में मोदी का विजय रथ रोक सकी और न ही केंद्र की सत्ता में आने से रोकने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में बची है. तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि 2014 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी बिना किसी चुनौती के आसानी से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? राजनीति अगर साधारण प्रक्रिया होती तो यह माना जा सकता था, लेकिन भारत की राजनीति में एक सप्ताह का समय भी काफी होता है और बाजी पलट जाती है. तो सवाल यह है कि मोदी को चुनौती कौन देगा या मोदी को चुनौती देने की क्षमता किसमें है?

भारत की राजनीति में पिछले दो–तीन सालों में एक जबरदस्त बदलाव आया है. इस बदलाव के कई कारण हैं. यूपीए सरकार की दिमाग हिलाने वाली घोटालों की शृंखला, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता, सरकार एवं निजी कंपनियों की मदद से जल–जंगल–जमीन की लूट, आर्थिक नीतियों की विफलताओं की वजह से जन्मी बेरोज़गारी, पिछले हर रिकॉर्ड को तोड़ने वाली महंगाई और सरकारी तंत्र के हर क्षेत्र में विफल होने की वजह से लोगों का न सिर्फ़ भरोसा टूटा, बल्कि उनमें राजनीति, नेताओं एवं राजनीतिक दलों के प्रति घृणा पैदा हो गई. दूसरी तरफ़, कालेधन को लेकर बाबा रामदेव का जनजागरण और फिर अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार के ख़िलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तो लोगों में ऊर्जा का संचार हुआ. जल–जंगल–जमीन के मुद्दों को लेकर किसानों, मज़दूरों एवं वनवासियों ने भी भारत के कोने–कोने में आंदोलन किया. सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रजातंत्र को बचाने में एक अहम रोल अदा किया है. मंत्री हो या प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार के मामलों में कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाकर जनता का विश्वास कायम रखा. बड़े–बड़े नेताओं के जेल जाने से लोगों को लगा कि अब पहले की तरह नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही, अख़बारों एवं टेलीविजन चैनलों ने भी लोगों का आक्रोश जमकर दिखाया और एक के बाद एक खुलासे करके देश में मूलभूत बदलाव की भावना लोगों में जगाई. इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की राजनीति के तर्क और संवाद में काफी बदलाव आया है. आज देश में यह माहौल बना है कि शायद अब भ्रष्ट, अपराधी एवं दागी किस्म के लोग राजनीति में टिक नहीं पाएंगे. धनबल और बाहुबल के जोर पर चुनाव जीतने के दिन ख़त्म हो गए हैं. पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं ने पिछले तीन–चार सालों में यह साबित किया है कि उनका वोट जाति, धर्म और भावनाओं पर आधारित राजनीति करने वालों के लिए नहीं है. यही वजह है कि राजनीति में अब साफ छवि, ईमानदारी और चरित्र की भूमिका का फिर से संचार हुआ है. तो अब सवाल यही है कि इस बदले हुए माहौल में क्या कोई ऐसा है, जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है?

> **मोदी को चुनौती देने वालों में एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी लिया जा रहा है. दरअसल, दिल्ली में कांग्रेस की मदद से सरकार बनाने, फिर एक ही महीने में धरना देने और मीडिया के कैमरे के सामने जिस तरह उनके नेता पेश आए, उससे आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों का भ्रम टूटा है. अरविंद केजरीवाल की राजनीति क्या है, विचारधारा क्या है, एजेंडा क्या है और भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्लान क्या है, यह सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं और कोई नहीं जानता.**

जबसे मीडिया में नरेंद्र मोदी नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चला है, तबसे यह बहस जारी है कि 2014 का चुनाव मोदी बनाम राहुल होगा. कार्यप्रणाली के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में काफी अंतर है, क्योंकि दोनों पार्टियों का स्वरूप अलग–अलग है. भाजपा में अपने ही नेताओं को नीचा दिखाने की प्रथा है और वह भरपूर अंतर्कलह से ग्रसित है. फिर इन सबके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दखलअंदाजी भी है. यही वजह है कि मोदी ने अपने नाम की घोषणा से पहले ही तैयारी शुरू कर दी. विरोधी राजनीतिक दलों से निपटने के पहले उन्हें अपनी ही पार्टी के बड़े–बड़े षड्यंत्रकारियों से निपटना था. इसका फायदा यह हुआ कि मोदी न सिर्फ़ पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने देश के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

यह राजनीति नहीं गुंडागर्दी है 03

वामपंथी नेताओं पर तरस आता है : वरवर राव 04

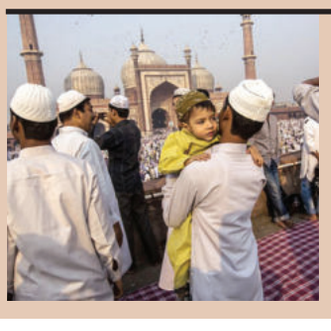



73 नहीं, सिर्फ़ 31 पर अमल 06

साई की महिमा 12

# नरेंद्र मोदी को कौन चुनौती देगा

पृष्ठ एक का शेष

युवा वर्ग में भी अपनी पैठ बना ली. दूसरी तरफ़, राहुल गांधी ने भी बड़ी मेहनत की, संगठन में जान फूंकने की कोशिश की. कांग्रेस का लक्ष्य राहुल गांधी को युवाओं के एकमात्र नेता के रूप में खड़ा करना था. शुरुआत में इसमें सफलता भी मिली, लेकिन नौसिखिए सलाहकारों की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा. कर्नाटक और हिमाचल छोड़कर कांग्रेस पार्टी हर जगह चुनाव हार गई. पार्टी न सिर्फ़ कमजोर हुई, बल्कि कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास भी टूट गया. कार्यकर्ताओं की यह चाहत थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हुई. देश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यही संदेश गया कि राहुल गांधी ने मोदी के सामने हथियार डाल दिए हैं. कांग्रेस पार्टी राहुल का मुकाबला सीधे-सीधे मोदी के साथ नहीं कराना चाहती है. युद्ध हो या राजनीति, अगर सेनापति ही पीछे रहकर लड़े, तो सेना का मनोबल टूट जाता है. कांग्रेस पार्टी ने ही यह मान लिया है कि राहुल गांधी मोदी के विकल्प नहीं हैं.

अगला नाम है नीतीश कुमार का. नीतीश कुमार की छवि अच्छे मुख्यमंत्री के साथ-साथ देश के सबसे बड़े मोदी विरोधी नेता की है. इस वजह से उन्होंने राजनीतिक परिणामों की परवाह किए बगैर भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया और अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया. नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं. वह जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़े रहे और हमेशा से समाजवाद के अनुयायी रहे हैं. उन्हें प्रशासन का अच्छा अनुभव है. भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए उन्होंने बिहार में न सिर्फ़ लोकायुक्त क़ानून बनाया, बल्कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जहां भ्रष्ट अधिकारियों के घरों में स्कूल खोले गए. उन्होंने बिहार में क़ानून-व्यवस्था को कायम किया और रेलमंत्री के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया. उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं योजनाओं पर यूपीए-1 का पूरा कार्यकाल बीता और लालू यादव ने जमकर उनके द्वारा किए कामों को अपना बताकर अपनी पीठ थपथपाई. मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश बिहार को विकास की राह पर ले आए. यह भी समझना ज़रूरी है कि लालू यादव के कुशासन की वजह से बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़ चुका था. यहां का सरकारी तंत्र पूरी तरह से सड़-गल चुका था. क़ानून-व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी. दिनदहाड़े लूटमार, अपहरण और हत्या की घटनाएं आम हो गई थीं. ऐसे राज्य में क़ानून- व्यवस्था को पुन: कायम करना और राज्य को विकास की राह पर लाकर खड़ा कर देना वाकई में नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है. यही वजह है कि कई लोग नीतीश कुमार में एक सफल प्रधानमंत्री देखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने अभी चुनौतियों का पहाड़ है. भाजपा से अलग होने के बाद उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं है. 2014 का चुनाव उन्हें अकेले ही लड़ना है. बिहार की राजनीति में कई तरह के सामाजिक और राजनीतिक कारक चुनाव में काम करते हैं. बिहार का चुनाव हमेशा एक जटिल परीक्षा होता है. गठबंधन की अलग चिंताएं हैं. यही वजह है कि नीतीश कुमार की प्राथमिकता बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना है. अगर ज़्यादा सीटें नहीं होंगी, तो न सिर्फ़ केंद्र की राजनीति से बाहर होने का, बल्कि बिहार सरकार पर भी ख़तरा मंडरा सकता है. इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खुद आगे आएं और मोदी को चुनौती दें, फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं देता है. वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है. आगे आने वाले दिनों में अगर राजनीति ने करवट ली और नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में मजबूत हुई, तो इसमें कोई शक नहीं कि वह मोदी के ख़िलाफ एक प्रबल दावेदार होंगे.

मोदी को चुनौती देने वालों में एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी लिया जा रहा है. दरअसल, दिल्ली में कांग्रेस की मदद से सरकार बनाने, फिर एक ही महीने में धरना देने और मीडिया के कैमरे के सामने जिस तरह उनके नेता पेश आए, उससे आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों का भ्रम टूटा है. अरविंद केजरीवाल की राजनीति क्या है, विचारधारा क्या है, एजेंडा क्या है और भारत के उज्जवल भविष्य का प्लान क्या है, यह सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं और कोई नहीं जानता. आम आदमी पार्टी ने देश भर में चुनाव लड़ने की तो जल्दबाजी दिखा दी, लेकिन सरकार चलाने का कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया. हास्यास्पद बात तो यह है कि पूछे जाने पर वह कहते हैं, अभी हमारी पार्टी नई है, इसलिए नीतियां तैयार की जा रही हैं.

हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मौक़ा देकर अराजकता को प्रोत्साहन दिया है. वैसे भी कांग्रेस पार्टी को भस्मासुर पैदा करने की पुरानी आदत है. कई राज्यों में अपने मुख्य विरोधी को हराने के लिए छोटी पार्टी का सहारा लेना कांग्रेस को महंगा पड़ा है. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि राज्यों में जहां कांग्रेस कभी सबसे बड़ी पार्टी होती थी, आज वहां यह अपने दम पर सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है. कुछ राज्यों में तो यह वोटकटुआ पार्टी में तब्दील हो चुकी है. अरविंद केजरीवाल को सरकार बनाने का मौक़ा देकर कांग्रेस ने दिल्ली राज्य में खुद को तीसरे नंबर की पार्टी बना लिया है. दिल्ली मीडिया का केंद्र है, इसलिए यहां की छोटी ख़बरें भी राष्ट्रीय बन जाती हैं. यही वजह है कि आम आदमी पार्टी मीडिया में छाई हुई है. एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, जिसकी वजह से इस बहस की शुरुआत हुई कि क्या अरविंद केजरीवाल मोदी का विजय रथ रोक लेंगे. यहां समझने वाली बात यही है कि इस सर्वे के मुताबिक भी अरविंद केजरीवाल फिलहाल मोदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है.

जरा इस सर्वे को समझने की कोशिश करते हैं. यह सिर्फ़ 8 बड़े-बड़े शहरों में किया गया है. इस सर्वे में सिर्फ़ 2015 लोगों की राय ली गई है. ये शहर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद. इन शहरों में क़रीब 33 लोकसभा सीटें हैं. मतलब यह कि हर लोकसभा सीट के सिर्फ़ 61 लोगों से राय ली गई, जबकि इन सीटों में औसतन 20 लाख वोटर हैं. वैसे भी यह सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है. समझने वाली बात यह है कि इन 33 सीटों में सिर्फ़ 3 सीटें भाजपा के पास हैं. इसके अलावा बाकी सभी 30 सीटें दूसरी पार्टियों के पास हैं, जो भाजपा के एनडीए में भी नहीं हैं. इस सर्वे में जो आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिलने वाली बात बताई जा रही है, वह भी भ्रामक है. यह

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

कोई सर्वे का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि 2015 लोगों की राय है कि देश भर में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी. जबसे आम आदमी पार्टी राजनीति में कूदी है, सर्वे चुनावी प्रोपेगेंडा का एक सटीक हथियार बनकर उभरा है. कौन किस तरह से, कहां और किस उद्देश्य से सर्वे कर रहा है, उसका पता करना बड़ा मुश्किल है. जमीनी हकीकत यह है कि दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी एक्का-दुक्का सीट ही जीत पाएगी. और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टियों के लिए करते हैं, उससे यह भी साफ़ है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन लेने या देने में कई पार्टियों को मुश्किल होगी. इसलिए वह मोदी को चुनौती देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है. तो फिर सवाल यह है कि मोदी को चुनौती कौन देगा?

देश की बदलती राजनीति और नए आदर्श के मापदंड पर एक नेता का नाम साफ़ उभरता है, ममता बनर्जी. देह पर नीले बॉर्डर वाली उजली साड़ी और पैर में हवाई चप्पल. बंगाल की तीन दशकों की वाम राजनीति के कुरुक्षेत्र में ममता का चेहरा हर जगह मौजूद रहा है. आज जिस ईमानदारी एवं सादगी की बात हो रही है, उस सादगी, संयम और परिश्रम को ममता बनर्जी ने न सिर्फ़ माना है, बल्कि जिया है. वह किसी की सहायता से अल्पमत की सरकार नहीं, बल्कि अपने संघर्ष की बदौलत और जनता की राजनीति करके बहुमत की सरकार चला रही हैं. राजनीति में उन्होंने सबसे पहला कारनामा 1984 के लोकसभा चुनाव में दिखाया, जब उन्होंने जादवपुर सीट पर माकपा नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया था. ममता का राजनीतिक जीवन निरंतर संघर्ष का जीवन रहा है. वह एक ग़रीब परिवार से आती हैं, लेकिन शुरू से ही समाज के दबे-कुचले लोगों की आवाज़ बनकर वामपंथी सरकार से लड़ती रहीं. आज बड़े जोर-शोर से राजनीति में शुचिता की बात हो रही है. पार्टियां किसी भ्रष्ट या अपराधी को टिकट न दें, उसका बिगुल फूंका जा रहा है और मीडिया में इसे एक क्रांतिकारी क़दम बताया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने 1996 के विधानसभा चुनावों में आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने के ख़िलाफ आवाज़ बुलंद की थी. जब पार्टी में उनकी बातों को दरकिनार किया गया, तो ममता ने गले में शॉल का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता ने जगह-जगह जाकर खुद पार्टी को तैयार किया, कैडर तैयार किया, मूल्यों की राजनीति का नया अध्याय लिखा, कई घोटालों का खुलासा किया और जब भिखारी पासवान की मौत पर ममता ने आंदोलन किया, तो पहली बार उनके आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनी गई.

राजनीति की शुरुआत से ही ममता आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं. ममता की राजनीति की खासियत यह है कि वह विरोधियों पर आरोप लगाकर मुद्दे को भुलाती नहीं. ममता बनर्जी उन चंद नेताओं में से हैं, जिन्होंने न सिर्फ़ आंदोलन किया, बल्कि आंदोलन को सफल भी बनाया. सिंगुर में टाटा के नैनो कारखाने के ख़िलाफ किसानों का मामला जब ममता ने उठाया, तो उन्होंने उसे पूरे दक्षिण बंगाल में फैलाया और तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं किया, जब तक टाटा ने कारखाना नहीं हटाया. तृणमूल के गठन के बाद 1998 में उन्होंने राजग का दामन थामा, मगर ईंधन की क़ीमतें बढ़ाने के विरोध में उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया. ममता बनर्जी की राजनीति मूल्यों की राजनीति है, संघर्ष की राजनीति है. ममता बनर्जी की लोकप्रियता बंगाल में चरम पर है. सभी सर्वे यही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी आराम से 30 सीटों से ज़्यादा अकेले बंगाल में जीत जाएंगी. इसलिए वह दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से बेहतर स्थिति में हैं. अगर वह बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस को लेकर जाती हैं और साफ़ छवि वाले ईमानदार लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो देश भर में वह 20 और सीटों पर जीत दर्ज करा सकती हैं. इसकी वजह यह है कि चाहे ईमानदारी हो, संघर्ष हो, आर्थिक एजेंडा हो या फिर राजनीति में शुचिता का मसला हो, ममता बनर्जी इन सभी मापदंडों पर मोदी, राहुल और केजरीवाल से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं.

कई लोग तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरा मोर्चा अगर सिर्फ़ चुनाव के लिए गठबंधन मात्र होगा, तो यह देश की जनता को स्वीकार नहीं होगा. असल मसला विकल्प का है. विकल्प का मतलब सिर्फ़ अलग पार्टी या अलग चेहरा नहीं होता, बल्कि असली विकल्प वह होता है, जो वैकल्पिक एजेंडा देता है. मोदी का विकल्प देने का मतलब है कि आपकी आर्थिक नीति, बेरोज़गारी से निपटने की नीतियां, महंगाई रोकने के उपाय और देश के शोषित वर्ग के लिए योजना भाजपा से किस तरह से अलग है. यहां समझने वाली बात यही है कि भाजपा और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है और दूसरी सभी पार्टियों के पास तो कोई नीतियां ही नहीं हैं. तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भारत की राजनीति में पूरब से कोई सितारा उठेगा? जिसने अब तक आंधी-पानी, जलती दोपहर और धूल भरे रास्तों की परवाह किए बिना जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष किया है और जिसने जीवन के 30 सालों तक राजनीतिक तपस्या की है. क्या ममता बनर्जी का मां, माटी, मानुष का नारा सचमुच पूरे देश में चमत्कार करने वाला है? ■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 48
दिल्ली, 03 फरवरी –09 फरवरी 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

## दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

### शक्ति पाने की कोशिश

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब इस कोशिश में है कि वह अपनी कैद तोते वाली छवि से बाहर निकल सके. इस दौरान कहीं और नौकरशाही के गलियारों में एक अन्य प्रयास भी चल रहा है, जो इतना सुर्खियों में नहीं है. सूत्रों के अनुसार, विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों के महानिदेशक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वे गृह मंत्रालय की बेड़ियों से मुक्त हो जाएं. उनका ऐसा मानना है कि अर्द्धसैनिक बलों की कार्यप्रणाली को लेकर समीक्षा तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है. सूत्र बताते हैं कि इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) एवं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) के महानिदेशकों ने इस मुद्दे पर गृह सचिव अनिल गोस्वामी के साथ एक बैठक की. इन अर्द्धसैनिक बलों के महानिदेशकों (सुभाष गोस्वामी, अरुण चौधरी और अरविंद रंजन) ने बजट आवंटन, तैनाती और स्थानांतरण करने के अधिकारों की मांग की है, जिससे उन्हें मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता न पड़े. आख़िर इसका अंत कहां होगा, यह तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्रालय और अर्द्धसैनिक बलों के बीच एक दिलचस्प प्रतियोगिता चल रही है. ■

### चहेते नौकरशाह

सेवानिवृत्त और कार्यरत नौकरशाहों का राजनीति की ओर रुख करना पुरानी बात हो गई, लेकिन ऐसा विरले ही होता है कि एक ही नौकरशाह को दो पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए अपना टिकट देना चाहें. बिहार के मुख्य सचिव के पी रमैया कुछ इसी तरह की मुश्किल या कहें खुशी वाली अवस्था से गुजर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमैया को आगामी लोकसभा चुनाव में मीरा कुमार के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए चुना है. मीरा कुमार सासाराम लोकसभा सीट से लगातार दो बार चुनाव जीत चुकी हैं. निश्चित रूप से नीतीश कुमार का ऐसा मानना है कि मीरा कुमार को उनके गढ़ में पटकनी देने के लिए रमैया सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं. लेकिन, अकेले नीतीश कुमार ही नहीं हैं, जो रमैया की राजनीतिक काबिलियत का मूल्य लगा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि वाई एस जगनमोहन रेड्डी भी इस बात के इच्छुक हैं कि रमैया को आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए. रमैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका जुड़ना पार्टी के लिए लाभकारी होगा. हालांकि उन्होंने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वह किस पार्टी से जुड़ सकते हैं. जानकारी के अनुसार, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति की मांग की है. ■

### कितने स्थानांतरण!

नौकरशाही में कार्यरत मेरे कई बैचमेट स्थानांतरण के बारे में इस तरह चर्चा करते हैं, जैसे वह कोई सम्मान हो. दु:खद रूप से यह सेवा आजकल ख़तरनाक और हानिकारक होने से ज़्यादा मैनेजेरियल हो गई है. हरियाणा के आईएएस अधिकारी खेमका भारत के सबसे ज़्यादा स्थानांतरित होने वाले अधिकारी बनने की वजह से अख़बारी सुर्खियां बना चुके हैं. इसका कारण यह है कि उन्होंने मजबूत राजनेताओं के ख़िलाफ भी कड़े क़दम उठाए. लेकिन, अधिकारियों के लगातार स्थानांतरण अकेले हरियाणा में नहीं हो रहे हैं. दु:खद यह है कि देश के लगभग सभी हिस्सों में ऐसा हो रहा है. हालांकि हरियाणा आईएएस अधिकारियों की तैनाती के लिहाज से देश के खराब राज्यों में बना हुआ है. एक हालिया अध्ययन के अनुसार, देश के 68 प्रतिशत उच्च नौकरशाहों की एक जगह तैनाती लगभग 18 महीने से भी कम रहती है. इसी अध्ययन में यह भी जानकारी मिलती है कि खेमका के अलावा भी कई ऐसे अधिकारी हैं, जो 40 से अधिक बार स्थानांतरित होने वालों में शामिल हैं. इन अधिकारियों में हिमाचल प्रदेश कैडर एवं 1982 बैच के एक अधिकारी का आश्चर्यजनक रूप से 52 बार स्थानांतरण हो चुका है. उनके पीछे असम-मेघालय कैडर के डब्ल्यू एम एस पैरियत हैं, जिनका 50 बार स्थानांतरण हो चुका है. इसके अलावा भी अन्य अधिकारी हैं, जो पंजाब, झारखंड और निश्चित रूप से हरियाणा से भी हैं. राज्य में खेमका के अलावा 6 ऐसे अधिकारी हैं, जिनका चालीस से अधिक बार स्थानांतरण किया जा चुका है. इन राज्यों में गुड गवर्नेंस की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है. ■

dilipcherian@gmail..com

## साउथ ब्लॉक

### मधुकर, सुभाशीष और मनीष निदेशक बने

1997 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी आनंद मधुकर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. वह 1995 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी सी पी जैन का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल में कर्मचारी चयन आयोग के निदेशक के रूप में स्थानांतरित किया गया है. इसी तरह 1997 बैच एवं हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी सुभाशीष पांडा को पेट्रोलियम मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. उन्हें 1999 बैच एवं महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी अतुल पाटनी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें हाल में मंत्री का निजी सचिव बनाया गया है. इसी तरह 1995 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मनीष गुप्ता को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. यह पद 1994 बैच एवं राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी श्रेया गुहा के पिछले साल नवंबर में संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त होने से रिक्त हुआ था.

### राम सिंह स्थानांतरित

1994 बैच एवं पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी राम सिंह कपड़ा मंत्रालय में निदेशक का कार्यभार संभालेंगे. यह पद 1992 बैच की भारतीय डाक सेवा अधिकारी मनीषा सिन्हा को हाल में संस्कृति मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किए जाने से रिक्त हुआ था.

### कुमार संयुक्त सचिव बनेंगे

1985 बैच एवं असम-मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी कुमार संजय कृष्णा का चयन विनिवेश विभाग में संयुक्त सचिव पद के लिए किया गया है. वह वर्तमान में असम सरकार के अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

2004 में भारती की दिल्ली स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी मैडगेन सोल्यूशन पर आरोप लगा कि उसने एक क्लाइंट टॉपसाइट्स एलएलसी के नाम पर भारी संख्या में मेल भेजे थे. अमेरिकी एंटी–स्पैम कार्यकर्ता और डेनियल बालसम ने भारती और कंपनी पर कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा दायर किया था. कंप्यूटर तकनीक जैसे विषयों पर आधारित पत्रिका पीसी क्वेस्ट के अनुसार, अदालत की सहमति से हुए समझौते के तहत भारती ने बालसम को 5000 डॉलर (करीब 3,00,000 रुपये) का भुगतान किया था.

# यह राजनीति नहीं गुंडागर्दी है

**नीरज सिंह**

विधानसभा चुनावों के पहले दिल्ली की गलियों में लगे कुछ पोस्टर आपके जेहन में अभी भी होंगे. दिल्ली को रेप कैपिटल घोषित करते और शीला दीक्षित को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से जारी उन पोस्टरों में लिखा था कि इस बार भी दिया बेईमानों को वोट, तो महिलाओं का होता रहेगा बलात्कार. पोस्टर में शीला दीक्षित को बेईमान दिखाया गया था और अरविंद केजरीवाल को ईमानदार. दामिनी प्रकरण के बाद जिस तरह की जनभावनाएं ऐसे संदर्भों को लेकर उभरी थीं, उससे शीला सरकार के ख़िलाफ माहौल तो था ही, अरविंद केजरीवाल ने बलात्कार पर राजनीति करते हुए उन जनभावनाओं को भुनाने की कोशिश की. अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया कि 2012 की तुलना में 2013 में दिल्ली में बलात्कार के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई. बहरहाल, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं वैसे ही बदस्तूर जारी रहीं. आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि सरकार अभी तक जिस भी मुद्दे पर सामने आई, मसलन बिजली, पानी, जनता दरबार आदि, हर बार उसे आलोचनाएं ही झेलनी पड़ीं. दिल्ली में बलात्कार के मामले एक बार फिर तेजी से सामने आने लगे और सरकार इस मसले पर भी घेरी जाने लगी. इसलिए एक रणनीति के तहत खिड़की एक्सटेंशन मामले को सामने लाया गया.

खिड़की एक्सटेंशन एरिया क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती के विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर में आता है. ग़ौरतलब है कि इस इलाके में बड़ी संख्या में अफ्रीकी मूल के नागरिक रहते हैं, जिन्हें लेकर क्षेत्र में एक पूर्वाग्रह है कि वे ड्रग्स और देह व्यापार में लिप्त हैं. यह भ्रांति केवल खिड़की एक्सटेंशन में ही नहीं, समूची दिल्ली में जहां भी विदेशी मूल के नागरिक रह रहे हैं, उन इलाकों को लेकर है. दिल्ली के भीतर विदेशी तो छोड़ दीजिए, पूर्वोत्तर के इलाकों के भी जो लोग रह रहे हैं, वे खुद को अलग–थलग ही रखते हैं और आम तौर पर कोर्ट–कचहरी, पुलिस से बचना चाहते हैं. सोमनाथ भारती के लिए ये लोग सॉफ्ट टार्गेट लगे. क़ानून मंत्री जब इस तथाकथित संदेहास्पद इलाके में रेड डालने चले, तो अपने साथ मीडिया को भी ले गए. बाकायदा फोन करके उन्हें बुलाया, कैमरे के सामने पुलिस से झड़प की. एसीपी से कहा कि हमें आपका काम करना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरिए.

जाहिर–सी बात है कि दिल्ली पुलिस की छवि को इस तरह से जनता के सामने पेश करना था कि वह तो सरकार की सुनती ही नहीं. इसके पीछे सोच यह थी कि चूंकि दिल्ली पुलिस तो सरकार की सुनती ही नहीं, इसलिए अगर हम दिल्ली के भीतर हो रही बलात्कार की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसके लिए सरकार नहीं, पुलिस ज़िम्मेदार है. लेकिन, क़ानून मंत्री अति–उत्साह में अपनी हदों को इस कदर पार गए कि पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया और उसने इतना तूल पकड़ लिया कि विदेश मंत्रालय को 20 अफ्रीकी देशों के राजदूतों को बुलाकर यह सुनिश्चित करना पड़ा कि दिल्ली के क़ानून मंत्री एवं उनके समर्थकों ने युगांडा की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उस पर हम कड़ी और निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे. जिन दो महिलाओं को क़ानून मंत्री ने अपराधी घोषित किया था, जब उनके ब्लड सैंपल आए और यह साबित हो गया कि उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, तब केंद्र ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट देने और दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को क़ानून मंत्री एवं उनके समर्थकों के ख़िलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा.

हिंदी में एक कहावत है, आए थे हरि–भजन को, ओटन लगे कपास. अब यह कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके क़ानून मंत्री के ऊपर पूरी तरह से लागू होने लगी. चूंकि दिल्ली सरकार हर तरफ़ से घिरने लगी, इसलिए आनन–फानन में पूरी कैबिनेट इस बात को लेकर धरने पर बैठ गई कि इस प्रकरण से संबंधित दो एसएचओ और एक एसीपी को सस्पेंड किया जाए. धरने की शुरुआत तो यहां से हुई और फिर सोची–समझी रणनीति के तहत दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाने की बात की जाने लगी. बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की मंशा इस पूरे प्रकरण के माध्यम से दिल्ली की जनता को बरगलाने की थी, चौतरफ़ा हो रहे हमले से लोगों का ध्यान हटाने की थी. क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती के अतीत की ओर देखें, तो जाहिर होता है कि वह इस विधा के विशेषज्ञ हैं. सोमनाथ भारती के क़रीबी मानते हैं कि वह अति महत्वाकांक्षी और भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले शख्स हैं. सोमनाथ भारती के बिजनेस सहयोगी रहे रामकुमार अत्री बताते हैं कि सोमनाथ भारती बेहद महत्वाकांक्षी और आक्रामक रहे हैं. वह चर्चा में रहना पसंद करते हैं. शायद कई बार यही महत्वाकांक्षा और विवादों में रहने की प्रवृत्ति उन्हें मुश्किल में भी डाल देती है.

साल 2004 में भारती की दिल्ली स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी मैडगेन सॉल्यूशंस पर आरोप लगा कि उसने एक क्लाइंट टॉपसाइट्स एलएलसी के नाम पर बड़ी संख्या में मेल भेजे थे. अमेरिकी एंटी–स्पैम कार्यकर्ता डेनियल बालसम ने भारती और उनकी कंपनी पर कैलिफोर्निया की अदालत में मुकदमा दायर किया था. कंप्यूटर तकनीकी विषयों पर आधारित पत्रिका पीसी क्वेस्ट के अनुसार, अदालत की सहमति से हुए समझौते के तहत भारती ने बालसम को 5000 डॉलर (करीब 3,00,000 रुपये) का भुगतान किया था. इस घटना को हुए एक वर्ष ही बीते थे कि स्पैमिंग पर नज़र रखने वाली वेबसाइट स्पैमहॉज डॉट ऑआरजी ने 2005 में स्पैम करने वालों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें भारती के अलावा दो अन्य भारतीय भी शामिल थे. वर्ष 2005 में ही रोकसो (रजिस्टर ऑफ नोन स्पैमिंग ऑपरेशंस) की लिस्ट में 200 स्पैम करने वालों को शामिल किया गया था, जो दुनिया भर में भेजे जाने वाले 80 फ़ीसद स्पैम के लिए ज़िम्मेदार थे. लंदन और जिनेवा स्थित स्पैमहॉज संगठन हर साल यह लिस्ट तैयार करता है. यह संगठन स्पैम के ख़िलाफ़ जागरूकता फैलाता है. इस लिस्ट में सोमनाथ भारती को स्पैम करने वाले के तौर पर शामिल किया गया था. कहा जाता है कि उन दिनों सोमनाथ भारती दिल्ली से एक आईटी कंपनी मैडगेन सॉल्यूशंस चलाते थे. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह कंपनी क्या काम करती थी.

भारत के आईटी एक्ट 2000 के अनुसार, स्पैमिंग एक ग़ैर–क़ानूनी और दंडनीय अपराध है, जिसमें तीन वर्ष तक कैद की सजा का प्रावधान है. जाहिर–सी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से क़ानून की डिग्री हासिल कर चुके सोमनाथ भारती को यह जानकारी तो रही ही होगी. मैडगेन सॉल्यूशंस कंपनी का दफ्तर दक्षिणी दिल्ली में मौजूद है. कंपनी के निदेशकों में मनोरमा रानी भारती और दिव्या स्तुति कुमारी का नाम है, जो कथित तौर पर भारती के रिश्तेदार बताए जाते हैं. पत्रिका पीसी क्वेस्ट ने अपने 2005 के अगस्त अंक में रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि भारती ने कैलिफोर्निया अदालत के मुकदमे में समझौता करने का रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि अमेरिका में मुकदमा लड़ना ज़्यादा खर्चीला होता. हालांकि सोमनाथ भारती की ओर से इस मसले पर जो सफाई दी जाती है कि वह गले नहीं उतरती. उनकी तरफ़ से दी गई सफाई में कहा गया है कि वर्ष 2000 के शुरुआती महीनों में उन्होंने मैडगेन सॉल्यूशंस को एक सहयोगी के हवाले कर दिया था, जिसने बिना जानकारी दिए ही ग़लत इस्तेमाल किया. जब मामला सामने आया, तो भारती को पता चला कि उनके सहयोगी ने बड़े पैमाने पर मेल भेजे और उनके नाम का कई मौकों पर इस्तेमाल किया. उनके सहयोगी ही कंपनी चला रहे थे. सवाल यह है कि जब वर्ष 2000 में उन्होंने कंपनी सहयोगी को दे दी, तो क्या पांच साल तक हो रहे इस खेल का उन्हें पता ही नहीं चला? दूसरे, जब उन्हें पता चला, तो वह इस मसले को लेकर अदालत में क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने जुर्माना देकर मामला रफा–दफा किया? हालांकि क़ानून मंत्री कहते हैं कि अब उनका इस कंपनी से कोई लेना–देना नहीं है. बिल्कुल वैसे ही, जैसे फोर्ड फाउंडेशन से मिले पैसों का हिसाब–किताब जानने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि उनके एनजीओ दो साल पहले ही बंद हो चुके हैं.

कुछ दिन पहले ही क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती पर एक ऐसा आरोप लगा, जो उनके क़ानून के अल्पज्ञान को सामने लाता है. उन पर एक मामले में सुबूतों से छेड़छाड़ और अभियोजन पक्ष के गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगा. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में हुए फर्जीवाड़े के एक मामले में उनके मुवक्किल पवन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप का मुकदमा चल रहा था. अगस्त 2013 में सीबीआई की विशेष जज पूनम ए बांबा ने कहा था कि आरोपी पवन कुमार और उनके वकील सोमनाथ भारती ने गवाह बी एस दिवाकर से फोन पर बात की. कोर्ट ने कहा कि भारती और उनके मुवक्किल का यह व्यवहार बेहद आपत्तिजनक और अनैतिक है. उन्होंने यह भी कहा कि भारती एवं पवन ने सुबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है. इसी आधार पर अदालत ने पवन की जमानत निरस्त कर दी थी. बाद में इस आदेश को वरिष्ठ वकील एवं आम आदमी पार्टी के सदस्य प्रशांत भूषण और सोमनाथ भारती ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, मगर दोनों अदालतों ने इस संदर्भ में कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया था. हालांकि क़ानून मंत्री इस मसले में खुद को निर्दोष बताते हैं. उनके मुताबिक, अदालत में चल रहे मामले के दौरान वह सुबूत जुटाने की कोशिश कर रहे थे और उन पर ही आरोप लगा दिया गया. सोमनाथ भारती ने कहा कि अदालत की टिप्पणी गलत थी.

विवादों का यह सिलसिला यहीं नहीं थमता. भारती पिछले दिनों क़ानून मंत्रालय के सचिव ए एस यादव के जरिये सभी जजों की मीटिंग बुलाने की कोशिश के मामले में भी विवाद में आए. सूत्रों के मुताबिक, क़ानून मंत्री सोमनाथ भारती ने सचिव ए एस यादव से कहा कि वह दिल्ली के सभी जजों की एक बैठक बुलाएं, जिसे वह स्वयं (भारती) संबोधित करेंगे. इस पर सचिव यादव ने कहा कि दिल्ली का न्यायिक तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और जजों की बैठक बुलाने का अधिकार उनके पास नहीं है. जजों की बैठक बुलाने का अधिकार केवल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को है. इस पर क़ानून मंत्री ने उन्हें डांट लगाते हुए उन पर पूर्ववर्ती सरकार का पक्षधर होने का आरोप लगाया और कहा कि वह इसीलिए आप सरकार द्वारा तेजी से न्याय प्रणाली लागू करने के रास्ते में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, नाराज सचिव ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपने तबादले की मांग की, जिससे यह विवाद गहरा गया. उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि उन्हें वापस न्यायिक प्रणाली में बुला लिया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि क़ानून मंत्री उन पर कार्रवाई कर सकते हैं. ए एस यादव दिल्ली में जिला जज के तौर पर कार्यरत थे, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर क़ानून सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था. इस पूरे मसले पर सफाई देते हुए क़ानून मंत्री ने कहा, हमारी सरकार त्वरित न्याय दिलाने की प्रक्रिया लागू करने के अपने वायदे पर अडिग है. मैं जजों की बैठक बुलाना चाहता हूं, ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले और इस मार्ग में आने वाली बाधाओं के संबंध में जजों से बात करके सुधार किया जा सके, लेकिन यह कहना गलत है कि मैंने क़ानून सचिव से कोई दुर्व्यवहार किया.

विवादों की इस कड़ी में क़ानून मंत्री ने युगांडा की महिलाओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार का नया मसला अपने साथ जोड़ा है. एक वर्ग कह रहा है कि यहां पर क़ानून मंत्री की मंशा गलत नहीं थी, तरीका गलत था. जाहिर–सी बात है कि अगर मंशा गलत नहीं थी, तरीका गलत था, तो क़ानून मंत्री अपने इस कृत्य के लिए माफी मांग लेते और मामला रफा–दफा हो जाता. लेकिन चूंकि क़ानून मंत्री को इसे पर्दा बनाकर अपनी सरकार की असफलताएं छिपानी थीं, इसलिए उन्होंने इस प्रकरण को हवा दे दी. यहां भी क़ानून मंत्री ने चालाकी से काम लिया. चूंकि उक्त महिलाएं बार–बार कह रही थीं कि जिस आदमी ने उन्हें मारा–पीटा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसे वे पहचान लेंगी, इसलिए जब महिला आयोग ने इस मामले में मंत्री को हाजिर होने और अपनी बात रखने का नोटिस जारी किया, तो मंत्री ने खुद न जाकर अपने वकील को भेज दिया. आयोग की प्रमुख बरखा सिंह ने वकील की बात सुनने से इंकार कर दिया. उनके मुताबिक, दिल्ली महिला आयोग में वकीलों का इस तरह आना स्वीकार्य नहीं है. इस पर क़ानून मंत्री के वकील महिला आयोग के सदस्यों के साथ ही दुर्व्यवहार पर उतर आए. आयोग के सदस्यों और क़ानून मंत्री के वकील के बीच इस मुद्दे पर हुई बहस की तस्वीरें मीडिया में भी आईं. आयोग की सदस्य सुधा टोकस के मुताबिक, युगांडा की महिलाओं ने उन्हें बताया कि इस मामले में वे सिर्फ़ एक ही व्यक्ति को पहचान सकती हैं, जिन्हें उन्होंने टीवी पर देखा था. टोकस के मुताबिक़, वे उस व्यक्ति का नाम सोम–सोम बता रही थीं और उस वक्त टीवी चल रहा था, तो उन्होंने सोमनाथ भारती को पहचाना भी. यह सवाल इसलिए गंभीर है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल खुद को ही पाक–साफ़ कहती है, बाकी सब उसकी निगाह में अपराधी हैं. ऐसे में, जब उसके सदस्य ही अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो वह मौन क्यों है? दिल्ली की जनता भी अब इस खेल को समझने लगी है. हालिया धरने के प्रति उसके अनमनेपन ने आम आदमी पार्टी से उसके मोहभंग की झलक दिखा भी दी है.■

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

feedback@chauthiduniya.com

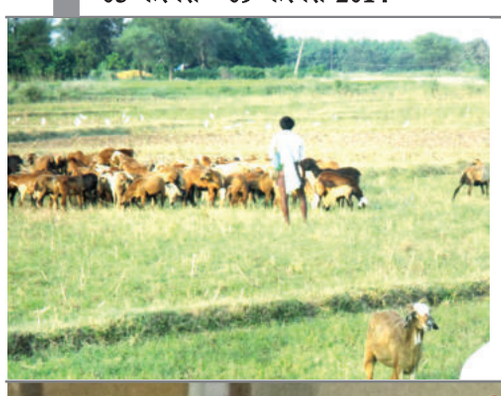

आम आदमी पार्टी के संदर्भ में प्रकाश करात का यह बयान वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे वामपंथी नेताओं की बुद्धि पर तरस आता है. वामदलों को कभी तीसरे मोर्चे में संभावना दिखती है, तो कभी आम आदमी पार्टी में. दरअसल, संसद में बैठकर राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों को अपनी क्षमताओं पर यकीन नहीं रह गया है. आज देश भर में सैकड़ों जनांदोलन चल रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति करने वाली वामपंथी पार्टियों की भागीदारी उसमें नगण्य है, जबकि साठ और सत्तर के दशक में उनकी ऐसी हालत नहीं थी.

# वामपंथी नेताओं पर तरस आता है : वरवर राव

**दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर हों, लेकिन माकपा के महासचिव प्रकाश करात अरविंद केजरीवाल की राजनीति से इन दिनों ख़ासे प्रभावित हैं. केजरीवाल की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए करात ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी आम आदमी पार्टी से सीख लेने की सलाह दे डाली. हालांकि, प्रकाश करात के इस बयान को निजी बताते हुए वामदलों ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन नक्सली गुटों ने उनके इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. इन्हीं तमाम मसलों पर नक्सल समर्थक एवं क्रांतिकारी कवि *वरवर राव* से बातचीत की चौथी दुनिया संवाददाता *अभिषेक रंजन सिंह* ने. प्रस्तुत हैं, उसके मुख्य अंश...**

*दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लोग कह रहे हैं कि देश की राजनीति बदल रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है?*

नेताओं की नज़र में उनकी पार्टी अन्य पार्टियों के मुक़ाबले सबसे अलग और बेहतर होती है. यही किस्सा आम आदमी पार्टी के साथ भी है. अरविंद केजरीवाल शहरी मध्यम वर्ग के लोगों के सहारे राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने आम आदमी को एक प्रोडक्ट के तौर पर भुनाया है. केजरीवाल और उनके समर्थक जिस तरह आम आदमी की बात कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आम आदमी की बात इससे पहले कभी नहीं हुई. केजरीवाल की नज़रों में आम आदमी वे लोग हैं, जो बिजली और पानी की दरों में बढ़ोत्तरी से परेशान हैं. उनकी नज़रों में आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार से परेशान हैं. मेरे ख्याल से इसे देश की राजनीति में बदलाव कहना ठीक नहीं है, बल्कि यह मध्यमवर्गीय जनता की भावनाओं को वोटों में तब्दील करना है. उनके पास न तो कोई विजन है और न ही दूरगामी उद्देश्य.

*अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि उनका मकसद सत्ता की राजनीति करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है. उनकी इस बात से क्या आप सहमत हैं?*

वर्ष 1947 से आज तक सभी सरकारों ने इसी तरह का दावा किया है, लेकिन आज़ादी मिलने के साढ़े छह दशकों बाद भी देश की जनता अपने वाजिब अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है. दिल्ली में रहकर आंदोलन करने, राजनीतिक पार्टी बनाने और अंतत: वहीं से राजनीति करने वाले

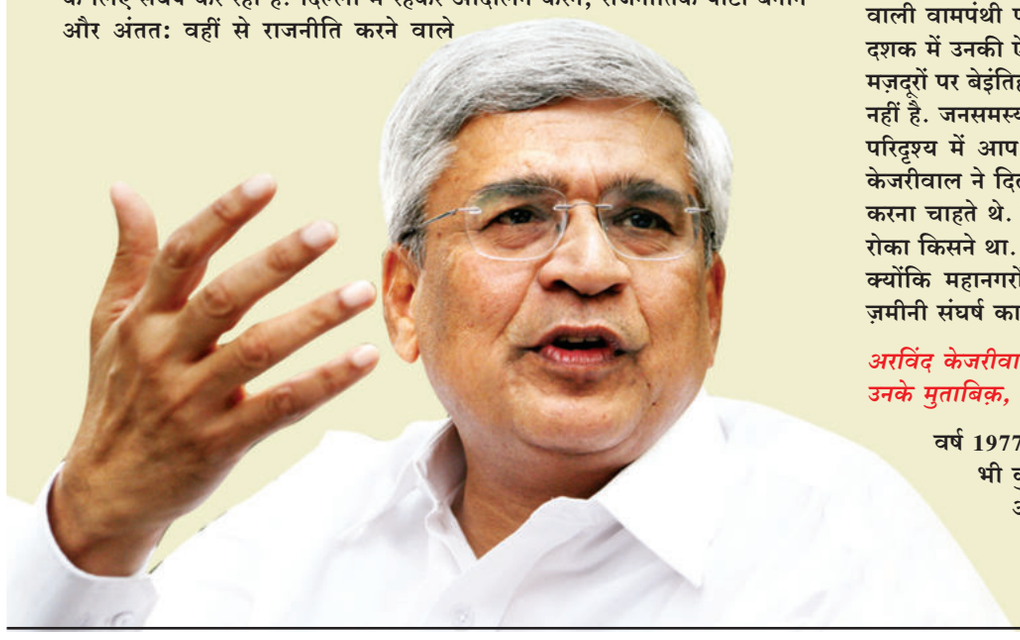

अरविंद केजरीवाल को दरअसल, आम आदमी की परख ही नहीं है. वह उन लोगों की भूख मिटाना चाहते हैं, जिनका पेट भरा हुआ है. वह दिल्ली से बाहर उन वंचितों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, जो आज भी ग़ैर-बराबरी के शिकार हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरने का मन बना रही है, लेकिन इस पार्टी के किसी नेता और स्वयं केजरीवाल को उन इलाक़ों की कोई ख़ैर-ख़बर नहीं है, जो जल, जंगल और ज़मीन बचाने के लिए ज़द्दोज़हद कर रहे हैं. देश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, क्या वे लोग आम आदमी नहीं हैं? अगर वे लोग आम आदमी हैं, तो अरविंद केजरीवाल उनके अधिकारों की बात क्यों नहीं करते?

*पिछले दिनों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन किया है, इसे आप किस रूप में देखते हैं?*

आम आदमी पार्टी के संदर्भ में प्रकाश करात का यह बयान वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे वामपंथी नेताओं की बुद्धि पर तरस आता है. वामदलों को कभी तीसरे मोर्चे में संभावना दिखती है, तो कभी आम आदमी पार्टी में. दरअसल, संसद में बैठकर राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों को अपनी क्षमताओं पर यकीन नहीं रह गया है. आज देश भर में सैकड़ों जनांदोलन चल रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति करने वाली वामपंथी पार्टियों की भागीदारी उसमें नगण्य है, जबकि साठ और सत्तर के दशक में उनकी ऐसी हालत नहीं थी. मौजूदा समय में आदिवासियों, किसानों और मज़दूरों पर बेइंतिहा जुल्म हो रहे हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को उनकी तनिक भी चिंता नहीं है. जनसमस्याओं से बेख़बर रहने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों का हश्र राजनीतिक परिदृश्य में आप लगातार देख ही रहे हैं. प्रकाश करात ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिन मुद्दों को उठाया, दरअसल इसके लिए वामदल संघर्ष करना चाहते थे. माकपा के महासचिव से यह पूछा जाना चाहिए कि आख़िर उन्हें रोका किसने था. मैं समझता हूं कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि महानगरों और शहरों में बैठकर राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियों ने ज़मीनी संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया है.

*अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पिछले दिनों रेल भवन के बाहर धरना दिया था. उनके मुताबिक़, वह जो कर रहे हैं, वही वास्तविक लोकतंत्र है.*

वर्ष 1977 में जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी. उस समय भी कुछ ऐसे ही हालात उत्पन्न हुए थे. देश की राजनीति बदल रही है और लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, जैसे तमाम जुमलों का इस्तेमाल उन दिनों भी किया गया था, लेकिन महज दो वर्षों के भीतर जनता पार्टी सरकार का पतन हो गया. यहां तक कि पार्टी भी बिखर गई और उसके समर्पित नेताओं ने दूसरे दलों का दामन थाम लिया. मेरे ख्याल से देश की समस्याओं का समाधान इलेक्शन फ्रेमवर्क से नहीं होगा.

*सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एफडीआई की मंजूरी निरस्त कर दी. क्या इससे यह माना जाए कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ख़िलाफ़ हैं?*

दिल्ली में एफडीआई रद्द करने को यह मान लेना कि वह कंपनीराज के ख़िलाफ़ हैं, यह ज़ल्दबाज़ी है. आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने कभी भी खुलकर कॉरपोरेट्स का विरोध नहीं किया. जैसा कि आपको मालूम है, आम आदमी पार्टी में एनजीओ संचालक लगातार शामिल हो रहे हैं. पार्टी के कुछ मंत्री, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल भी एनजीओ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं. देश में एनजीओ की क्या भूमिका है, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बात करने वाली आम आदमी पार्टी ने क्या कभी कॉरपोरेट्स और एनजीओ के भ्रष्टाचार की बात की है? देश में प्राकृतिक संसाधनों की लूट और विविध परियोजनाओं के नाम पर अपनी ज़मीनों से बेदख़ल होने वाले लोगों के बारे में उन्होंने आज तक कोई बात नहीं की. उनके राजनीतिक उभार में मीडिया, ख़ासकर समाचार चैनलों की अहम भूमिका रही है. देश के सुदूर इलाकों में ग़रीब आदमी सरकारी दमन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी ख़बर टेलीविजन पर दिखाई नहीं देती है.

*आपके मुताबिक़, अगर देश की समस्याओं का समाधान इलेक्शन फ्रेमवर्क से संभव नहीं है, तो क्या समस्याओं का समाधान नक्सलवाद से संभव है?*

यह अफ़सोसजनक है कि भारत में नक्सलवाद को पूरी तरह हिंसा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि यह पूरी सच्चाई नहीं है. अन्याय, दमन और असमानता के ख़िलाफ़ संघर्ष करने से लोगों को वंचित करना अनुचित है. अगर देखा जाए, तो पिछले ढाई-तीन दशकों में सबसे अधिक हिंसा सरकारों ने की है. हज़ारों की संख्या में बेगुनाहों को गोलियों का शिकार बनाया गया है. यह इसलिए कि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों की लूट रोकने के लिए आंदोलनरत हैं. तथाकथित विकास के नाम पर राजनेता और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जनता का शोषण कर रहे हैं. देश में समस्याओं का समाधान सिर्फ़ चुनावी राजनीति के जरिए संभव नहीं है. नक्सलवाद भी एक विचार है, जिसे पूरी तरह हिंसक गतिविधियों से जोड़कर देखना ग़लत है.■

arsingh@chauthiduniya.com

# सीट बंटवारे पर बवाल, कई बदलेंगे पाला

**बिहार**

सरोज सिंह

सूबे में सियासी दलों के बीच तालमेल की कुछ तस्वीरें भले ही अभी धुंधली हैं, मगर उसी ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि लोकसभा के अखाड़े में कूदने वाले कई सूरमा अब पाला बदलने की कवायद में जुट गए हैं. तालमेल की तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है, जिसमें उनका चेहरा दिख नहीं रहा है. सबसे ज़्यादा बवाल राजद में मचा है. अगर नए फार्मूले के तहत राजद, कांग्रेस एवं लोजपा का तालमेल हुआ, तो तय मानिए कि राजद के कई नेता दूसरे दलों, खासकर जदयू की तरफ़ मुखातिब होते नज़र आएंगे. इसी तरह टिकट न मिलता देख जदयू के भी कई नेता इधर-उधर हाथ-पैर मारने लगे हैं. भाजपा और लोजपा में यह रोग थोड़ा कम है. दरअसल, ये हालात इसलिए भी पैदा हुए हैं कि कई नेता यह मानकर चल रहे थे कि फलां सीट पर उन्हें टिकट मिलना तय है. कुछ को आलाकमान ने इशारा भी कर दिया था, पर तालमेल की गाड़ी कुछ इस तरह चल रही है कि उन्हें अपनी मंजिल मिलना मुश्किल लग रहा है. सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने अपने और लोजपा के लिए सीटों की सूची राजद को दे दी है. उनमें सासाराम, किशनगंज, मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, जमुई, नवादा, पटना साहिब, अररिया, बेतिया एवं मोतिहारी हैं. लोजपा को हाजीपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, गोपालगंज एवं आरा की सीटें दी जाएंगी और राकांपा को कटिहार सीट. सूत्र बताते हैं कि आख़िरी दौर में एक-दो सीटों में फेरबदल की गुंजाइश है. अगर तालमेल की यही तस्वीर रही, तो राजद भारी संकट में पड़ सकता है.

सासाराम सीट पर पिछले चुनाव में मीरा कुमार के सामने भाजपा के मुन्नीलाल एवं राजद के ललन पासवान थे. इस बार योद्धाओं के बदलाव, बदलते समीकरण और गठबंधन के बीच कई दलों की मेहनत पर पानी फिरने वाला है. सबसे ज़्यादा नुकसान राजद को होने का अनुमान है. पार्टी ने पहले ही संकेत देकर अपने पूर्व प्रत्याशी ललन पासवान को क्षेत्र भ्रमण से लेकर मातमपुर्सी और मिजाजपुर्सी के लिए छोड़ रखा था. ललन ने मेहनत भी खूब की. अब कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात चल रही है, तो सासाराम सीट पर पहला दावा मीरा कुमार का बनता है. वैसे भी भाजपा की तरफ़ से छेदी पासवान की उम्मीदवारी की चर्चा ने राजद के लिए एकजुट हुए मतदाताओं को कांग्रेस से गठबंधन के बाद एक आसरे के रूप में देखा है. खासकर सवर्ण मतदाताओं के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा के समान है. पहले भी भाजपा उम्मीदवार मुन्नीलाल की नैय्या सवर्ण मतदाताओं के सहारे पार होती थी. ललन पासवान की तरफ़ राजपूत मतदाताओं का बढ़ता झुकाव उम्मीदवार न आने पर भाजपा की ओर चला जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा. सासाराम में ब्राह्मण मतदाता पहले से ही भाजपा उम्मीदवार की ओर नज़र गड़ाए बैठे हैं. जैसे ही पार्टी ने मनमाफिक उम्मीदवार दिया, राजद का काफी आधार वोट भाजपा की ओर खिसकेगा, जिसका शायद ही कोई लाभ कांग्रेस उम्मीदवार को मिल पाए.

ऐसे में ललन पासवान अपनी जीत की प्रबल संभावना को देखते हुए टिकट न मिलने की स्थिति में पाला बदल भी सकते हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इसका लाभ उठाकर ललन को अपना प्रत्याशी बना सकती है. कांग्रेस मधुबनी से डॉ. शकील अहमद को उम्मीदवार बनाएगी. यहां से सिर्फ़ उनके नाम की सिफारिश की गई है. ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी को काफी दिक्कत हो जाएगी. उन्होंने कहा भी है कि अगर उन्हें टिकट न मिला, तो वह काफी आहत होंगे. जदयू की नज़र हमेशा उन पर लगी रहती है. हो सकता है, जदयू सिद्दीकी के आहत दिल पर मरहम लगाने में जुट जाए. मुजफ्फरपुर सीट के लिए विनिता विजय, अक्षय वर्मा एवं सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद कंठ के पुत्र प्रत्युष कंठ का नाम कांग्रेस को भेजा गया है. लोजपा की ओर से यहां विजेंद्र चौधरी प्रबल दावेदार हैं. क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है और पिछले दो सालों से चौधरी पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. ऐसे में अगर यह सीट कांग्रेस के पास चली जाती है, तो चौधरी राजद या फिर किसी अन्य दल का दामन थाम सकते हैं. इस सीट को लेकर जदयू में भी परेशानी है. देवेश चंद्र ठाकुर यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर जदयू यहां से किसी अतिपिछड़े को टिकट देने के मूड में है. ऐसे में देवेश कोई अलग रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं.

अब्दुल

शत्रुघ्न सिन्हा

रमई राम

देवेश चंद्र ठाकुर

बिजेन्द्र चौधरी

अख्तरुल ईमाम

रामबदन राय

समीर महासेठ

सम्राट चौधरी

ललन पासवान

सीतामढ़ी सीट के लिए कांग्रेस के समीर महासेठ और विमल शुक्ला में जंग छिड़ी है. कांग्रेस के पैनल में महासेठ का नाम नहीं भेजा गया है, विमल शुक्ला ने उसमें बाजी मार ली है. महासेठ की आख़िरी उम्मीद अब राहुल गांधी पर आकर टिक गई है. क़ांग्रेस से तालमेल की स्थिति में राजद को खगड़िया सीट से हाथ धोना पड़ सकता है. यहां से सम्राट चौधरी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं. कांग्रेस यह सीट महबूब अली कैसर के लिए चाहती है. लालू प्रसाद कई दफा कह चुके हैं कि तालमेल के लिए वह कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं. अगर तालमेल में यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई, तो सम्राट चौधरी को लपकने में जदयू जरा भी देरी नहीं करेगा.

अपने बिहारी बाबू का मन भी इन दिनों डोल रहा है. वह जमकर आप पार्टी का गुणगान कर रहे हैं. दरअसल, पाटिलीपुत्र सीट पर जोरों से सुशील कुमार मोदी का भी नाम चल रहा है. हालांकि मोदी इन बातों से इंकार करते हैं. इसी तरह किशनगंज सीट अगर कांग्रेस के खाते में रही, तो फिर राजद के अख्तारुल इमाम जदयू का तीर यहां से चला सकते हैं. जदयू की नज़र काफी पहले से इमाम पर लगी है. पूरे सीमांचल में राजद के वह विधानसभा में अकेले प्रतिनिधि हैं. तेजतर्रार एवं युवा इमाम इस बार किसी भी हाल में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं. राजद से टिकट न मिला, तो वह दूसरे दल में जाने से परहेज नहीं करेंगे. अररिया सीट लोजपा जाकिर साहब के लिए हर हाल में चाहती है, लेकिन राजद के तस्लीमुद्दीन हैं कि मानते ही नहीं. उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है. अगर तालमेल हुआ, तो तय है कि यहां जाकिर पाला बदलेंगे या फिर तस्लीमुद्दीन. हाजीपुर में जदयू के रमई राम ने ताल ठोंक दी है. मौजूदा सांसद रामसुंदर दास अगर स्वास्थ्य के कारण चुनाव नहीं लड़ते या राज्यसभा जाते हैं, तो यह सीट खाली होगी, पर यहां का प्रत्याशी उनकी मर्जी से ही तय होगा. सूत्र बताते हैं कि रामसुंदर दास रमई राम के पक्ष में नहीं हैं. ऐसे में रमई राम चुनाव लड़ने के लिए कोई भी क़दम उठा सकते हैं.

नवादा सीट पर भी कई दलों को परेशानी है. भाजपा से यहां भोला सिंह सांसद हैं. अगर रालोसपा के साथ भाजपा का तालमेल हुआ, तो परेशानी हो सकती है. डॉ. अरुण कुमार अपने लिए यह सीट चाहते हैं. बेगूसराय की सीट भी कांग्रेस ने अपने लिए मांगी है. अगर कांग्रेस की बात मानी गई, तो रामबदन राय का सपना टूट सकता है. रामबदन बेगूसराय में काफी सक्रिय हैं और इस बार उनकी जीत की संभावना भी है, लेकिन अगर कांग्रेस ने टांग अड़ा दी, तो फिर पाला बदल के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा. यह हालत तो तब है, जब तालमेल पूरी तरह साफ़ नहीं है. जब तस्वीर साफ़ हो जाएगी, तो पाला बदल का खेल और जोर पकड़ेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

**सच्चर समिति ने सातवीं अनुशंसा में देश के दूसरे समुदायों के साथ मुसलमानों के मेल-मिलाप को यक़ीनी बनाने के लिए यूपीए सरकार से एक विविधता सूचकांक (डाइवर्सिटी इंडेक्स) तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन मनमोहन सरकार ने इसे भी लागू नहीं किया.**

## सच्चर समिति की सिफ़ारिशों का सच

# 73 नहीं, सिर्फ़ 31 पर अमल

**जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में गठित सच्चर समिति ने वर्ष 2006 में यूपीए सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में देश के मुसलमानों की बदहाली दूर करने और उनकी बेहतरी के लिए 76 अनुशंसाएं की थीं, जिनमें से 45 अनुशंसाओं पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई. बावजूद इसके, यूपीए सरकार झूठ दर झूठ बोलती जा रही है कि उसने 72/73 अनुशंसाएं मंज़ूर कर ली हैं.**

डॉ. क़मर तबरेज़

घोटालों के लिए मशहूर केंद्र की मनमोहन सरकार ने एक बार फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया है. इस बार यह झूठ मुसलमानों के कल्याणार्थ बनाई गई योजनाओं के बारे में बोला जा रहा है. वर्ष 2004 में जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी सरकार ने देश में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अगुवाई में सच्चर समिति बनाई थी. इस समिति ने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी और अपनी जांच के आधार पर बताया था कि देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है. मुसलमानों की हालत ठीक करने के लिए सच्चर समिति ने 76 अनुशंसाएं की थीं, जिनमें से 45 अनुशंसाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान लगातार झूठ बोल रहे हैं कि 73 अनुशंसाएं लागू की जा चुकी हैं. हैरानी की बात यह है कि अब प्रधानमंत्री भी उनकी हां में हां मिला रहे हैं. मनमोहन सिंह ने बीती 13 जनवरी को राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की नवीं वार्षिक कांफ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार ने सच्चर समिति की 76 में से 72 अनुशंसाएं मंज़ूर कर ली हैं और उन पर कार्यवाही हो रही है. इस कांफ्रेंस में सच्चर समिति के सदस्य सचिव रहे डॉक्टर ज़फ़र महमूद भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को ग़लत क़रार देते हुए अपना विरोध जताया.

**वर्ष 2004 में जब मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी सरकार ने देश में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अगुवाई में सच्चर समिति बनाई थी. इस समिति ने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी और अपनी जांच के आधार पर बताया था कि देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है.**

चौथी दुनिया ने सच्चर समिति की सभी अनुशंसाओं का गहन अध्ययन करने के बाद पता लगाया है कि 76 में से 45 अनुशंसाओं पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है. आइए देखते हैं कि वे 45 अनुशंसाएं कौन-कौन सी हैं, जिन पर यूपीए सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है......

1. सच्चर समिति ने अपनी प्रथम अनुशंसा में कहा था कि देश के मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नीतियां बनाते समय समावेशी विकास एवं इस समाज को मुख्य धारा में शामिल करने पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए और ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि मुसलमानों के विकास को सभी क्षेत्रों में यक़ीनी बनाया जाए और यह विकास देश में सभी जगहों पर दिखाई भी देता हो. यूपीए सरकार ने सच्चर समिति की यह प्रथम अनुशंसा लागू नहीं की.

2. सच्चर समिति ने अपनी दूसरी अनुशंसा में कहा था कि एक नेशनल डेटा बैंक तैयार किया जाए, जिसमें विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक वर्गों की जानकारी या एसआरसी और सभी महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे भी लागू नहीं किया. अब तक देश में कोई भी नेशनल डेटा बैंक तैयार नहीं हुआ है.

3. सच्चर समिति ने अपनी तीसरी अनुशंसा में कहा था कि जब इस प्रकार के आंकड़े तैयार हो जाएं, यानी जब नेशनल डेटा बैंक पूरी तरह काम करने लगे, तो उसके बाद एक स्वतंत्र आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण (एसेसमेंट ऐंड मॉनीटरिंग अथॉरिटी) बनाया जाए, जो इस बात का पता लगा सके कि जिन कार्यक्रमों या योजनाओं को लागू किया गया है, उनसे उन्हें (पात्रों को) कितना लाभ मिल रहा है. हकीकत तो यह है कि अभी तक न तो नेशनल डेटा बैंक बन पाया है और न ही आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण.

4. सच्चर समिति ने अपनी चौथी अनुशंसा में कहा था कि चूंकि मुसलमानों में आम तौर पर यह सोच पाई जाती है कि उनके साथ समाज में हर स्तर पर भेदभाव बरता जाता है, इसलिए कोई ऐसा तंत्र बनाया जाए, जिससे उनकी यह शिकायत दूर की जा सके. इसलिए सच्चर समिति ने समान अवसर कार्यालय (इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस) स्थापित करने का सुझाव दिया था, लेकिन संसद ने अपने पिछले मानसून सत्र में इस बिल को ख़ारिज कर दिया.

5. सच्चर समिति ने अपनी पांचवीं अनुशंसा में केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया था कि वह आंध्र प्रदेश की तरह स्थानीय निकायों (लोकल बॉडिज) में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को यक़ीनी बनाए, लेकिन यूपीए सरकार ने इस पर भी कोई अमल नहीं किया.

6. सच्चर समिति ने अपनी छठवीं अनुशंसा में, परिसीमन (ऊशश्रळाळींरींळेप) के तहत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों (ठशीशर्ीींशव उेपीींळींीशपलळशी) में जो कमियां पाई जाती हैं, उन्हें दूर करने का सुझाव दिया था, लेकिन मनमोहन सरकार ने इस पर भी कोई अमल नहीं किया.

7. सच्चर समिति ने सातवीं अनुशंसा में देश के दूसरे समुदायों के साथ मुसलमानों के मेल-मिलाप को यक़ीनी बनाने के लिए यूपीए सरकार से एक विविधता सूचकांक (ऊळींशीीळीूं खपवशु) तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन मनमोहन सरकार ने इसे भी लागू नहीं किया.

8. सच्चर समिति ने कहा था कि चूंकि मुसलमान ग़रीब हैं और अधिकतर मुस्लिम परिवार एक कमरे के घर में रहते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को एक कमरे के घर में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने में परेशानी होती है. इसे ध्यान में रखते हुए समिति ने विद्यार्थियों के लिए कम्युनिटी स्टडी सेंटर बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन देश भर में हमें ऐसे केंद्र दिखाई नहीं देते. यूपीए सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट पर सच्चर समिति की इस 13वीं अनुशंसा को लागू करने का कोई वर्णन नहीं मिलता है.

9. सच्चर समिति ने अपनी 14वीं अनुशंसा में कहा था कि चूंकि देश भर में अधिकतर मुस्लिम छात्र-छात्राएं हाईस्कूल की परीक्षा में असफल हो जाते हैं या फिर उससे पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, इसलिए उनकी आगे की पढ़ाई का इंतज़ाम करने के लिए सरकार टेक्निकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करे और उन क्षेत्रों में आईटीआई खोले, जहां पर मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है, लेकिन मनमोहन सरकार ने यह अनुशंसा भी लागू नहीं की.

10. सच्चर समिति ने 15वीं अनुशंसा के तहत कहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जो पैसा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को देता है, उसमें से कुछ हिस्सा विभिन्न वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए लगाया जाना चाहिए. सच्चर समिति ने यहां पर भी एक डाइवर्सिटी इंडेक्स तैयार करने की बात कही है, लेकिन मनमोहन सरकार ने इसे भी लागू नहीं किया है.

11. सच्चर समिति ने अपनी 16वीं अनुशंसा में कहा था कि सभी सामाजिक एवं धार्मिक बिरादरियों में से जो बच्चे सबसे ज़्यादा ग़रीब हों, नियमित कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उनके प्रवेश के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जानी चाहिए. लेकिन केंद्र की मनमोहन सरकार ने इस बारे में भी कोई पहल नहीं की.

12. अपनी 17वीं अनुशंसा में सच्चर समिति ने कहा था कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों, खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए उनके इलाक़ों में छात्रावास बनाया जाना चाहिए. सच्चर समिति ने तो यहां तक कहा था कि स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिले, इसलिए ज़िला मुख्यालयों में बोर्डिंग हाउस का निर्माण होना चाहिए, जहां पर ग़रीब बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन की भी व्यवस्था हो. लेकिन केंद्र सरकार ने देश भर में न तो कहीं पर छात्रावास बनवाए हैं और न बोर्डिंग हाउस.

13. सच्चर समिति ने अपनी 20वीं अनुशंसा के तहत कहा था कि जिन राज्यों में उर्दू बोलने वालों की संख्या अधिक है, वहां पर सरकार की तरफ़ से उर्दू माध्यम के स्कूल खोले जाने चाहिए, लेकिन मनमोहन सरकार ने यह अनुशंसा भी लागू नहीं की.

14. सच्चर समिति ने अपनी 21वीं अनुशंसा में कहा था कि उर्दू में मानक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और जिन-जिन राज्यों में उर्दू बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, वहां केसरकारी और सरकारी सहायता से चलने वाले स्कूलों में उर्दू को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए.

**हैरानी की बात यह है कि अब प्रधानमंत्री भी उनकी हां में हां मिला रहे हैं. मनमोहन सिंह ने बीती 13 जनवरी को राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की नवीं वार्षिक कांफ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार ने सच्चर समिति की 76 में से 72 अनुशंसाएं मंज़ूर कर ली हैं और उन पर कार्यवाही हो रही है. इस कांफ्रेंस में सच्चर समिति के सदस्य सचिव रहे डॉक्टर ज़फ़र महमूद भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को ग़लत क़रार देते हुए अपना विरोध जताया.**

यूपीए सरकार इस 21वीं अनुशंसा के लागू होने पर खामोश है. इसका मतलब तो यही निकलता है कि उसने इसे भी लागू नहीं किया है.

15. सच्चर समिति ने 22वीं अनुशंसा के तहत कहा था कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, ताकि मदरसे से पढ़कर निकलने वाले छात्र-छात्राओं को भी नियमित स्कूलों में प्रवेश मिल सके और साथ ही वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाग ले सकें, लेकिन यूपीए सरकार ने इस दिशा में भी कोई काम नहीं किया.

16. सच्चर समिति ने अपनी 30वीं अनुशंसा में कहा था कि देश भर में अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित जो भी काम हो रहे हैं, उन्हें सरकार को हर तीन महीने में एक बार प्रकाशित करना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन यूपीए सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है. इससे उसके खोखले दावों की पोल खुलती जा रही है.

17. सच्चर समिति ने अपनी 35वीं अनुशंसा में कहा था कि यूपीए सरकार अव्यवस्थित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा (सोशल सिक्योरिटी) उपलब्ध कराने की योजना पहले से बना रही है, जिसे जल्द ही लागू किया जाना चाहिए और उसमें मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए. सरकार ने इस क़ानून को संसद से तो पारित करा लिया है, लेकिन यह योजना अभी तक ज़मीन पर नहीं उतर पाई है. सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि इससे मुसलमानों को कितना फायदा मिलने वाला है.

18. मुसलमान जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि सरकार की तरफ़ से लगातार अनदेखी के चलते उनके अंदर हीनभावना बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है. इसलिए सच्चर समिति ने अपनी 36वीं अनुशंसा के तहत कहा था कि सरकारी नौकरियों और ख़ासकर अध्यापन, स्वास्थ्य, पुलिस एवं बैंकिंग सेवाओं में मुसलमानों की भर्ती करके उनकी यह हीनभावना दूर करने का काम किया जाना चाहिए और हर विभाग में समान अवसर कार्यालय बनाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया.

19. सच्चर समिति ने अपनी 38वीं अनुशंसा में कहा था कि मुसलमानों को भी अपना एनजीओ स्थापित करने में सहायता मिलनी चाहिए और मस्जिद की कमेटी के रूप में अगर कोई मुसलमान अपना ट्रस्ट स्थापित करना चाहता है, तो सरकार को ऐसी संस्थाओं की स्थापना में मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी तक यह अनुशंसा भी लागू नहीं की जा सकी है. ■

*(शेष अगले अंक में)*

feedback@chauthiduniya.com

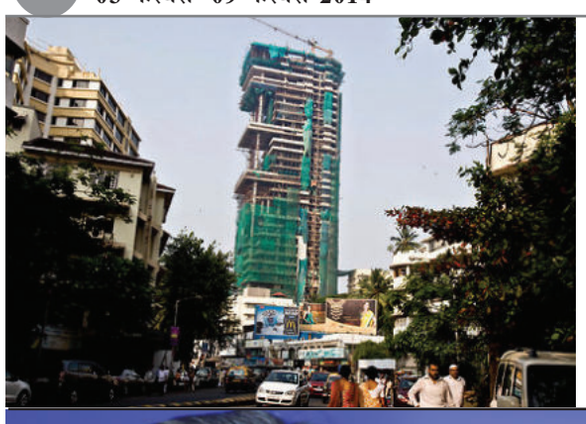

वर्ष 2002 में यह संपत्ति अंतीलिया कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने करीम भाई खोजा ट्रस्ट से वक्फ़ एक्ट के सेक्शन 51 की अवहेलना करते हुए ख़रीदी थी. इस ख़रीद–फ़रोख्त ने महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ–साथ कई अहम हस्तियों की मिलीभगत का पर्दाफाश किया है. उस समय महाराष्ट्र के वक्फ़ मंत्री नवाब मलिक ने इसका विरोध किया था.

## वक्फ़ भूमि पर अंबानी के महल को स्टे पर स्टे

# रक्षक बने भक्षक

**दक्षिण मुंबई में अल्टामाउंट रोड पर स्थित यतीमखाना एवं मस्जिद से बिलखते यतीम बच्चों को निकाल कर उस 4532 वर्गमीटर वक्फ़ भूमि पर उद्योगपति मुकेश अंबानी का 27 मंजिला महल अंतीलिया खड़ा है. दिल दहलाने वाली बात तो यह है कि महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनका कार्य वक्फ़ संपत्तियों की रक्षा करना और यतीम बच्चों को सहारा देना था, वे भी इस पूरी घटना में किसी न किसी रूप में स्वयं शरीक हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि देश का उच्चतम न्यायालय भी बॉम्बे हाईकोर्ट द्धारा मुकेश अंबानी के हक़ में दिए गए निर्णय को स्टे पर स्टे दिए जा रहा है. प्रस्तुत है, चौथी दुनिया की यह विशेष रिपोर्ट.**

**ए. यू. आसिफ**

***एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर,***
***हम ग़रीबों की मुहब्बत का उड़ाया है मजाक.***

उक्त पंक्तियां प्रसिद्ध उर्दू कवि साहिर लुधियानवी की मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में आगरा में बनवाए गए ताज़महल पर लिखी गई नज़्म से ली गई हैं, जिसे 68 हज़ार अमेरिकी डॉलर (32 मिलियन रुपये) की लागत एवं 22 हज़ार मज़दूरों और एक हज़ार हाथियों के परिश्रम से 17वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था. मगर ऐसा लगता है कि साहिर की उक्त पंक्तियां 21वीं शताब्दी के आरंभ में उद्योगपति मुकेश अंबानी द्वारा 500–700 मिलियन डॉलर की लागत से यतीम बच्चों एवं मस्जिद के लिए समर्पित वक्फ़ भूमि पर बनवाई गई 27 मंजिला भव्य इमारत अंतीलिया को मुंह चिढ़ा रही हैं. मुकेश अंबानी का यह महल 2005 से लेकर 2010 तक, यानी छह वर्षों में बनकर तैयार हुआ. इसे करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीमखाना ट्रस्ट द्वारा मुकेश अंबानी के अंतीलिया कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई 2002 में 7.1 मिलियन डॉलर में बेचा गया था.

टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा अंतीलिया को निर्धनों के प्रति धनी भारतवासियों की अकृपा एवं असहानुभूति का बदतरीन उदाहरण बताते हैं. लेखिका अरुंधति राय का सवाल है कि क्या अंबानी परिवार निर्धनता से अपने संबंध को समाप्त करना एवं अंतीलिया द्वारा एक नई सभ्यता को जन्म देना चाहता है? अंबानी एंड संस: ए हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस के विदेशी लेखक एमिश मैकडोनाल्ड तो साफ़ तौर पर कहते हैं कि यह धन का बेढंगा शो है एवं यह बिज़नेस टाइकून्स को भारत के नए महाराजा के तौर पर सामने लाने का प्रयास है. इस मुद्दे पर शुरू से ही विवाद रहा है. अदालत में मुक़दमा चल रहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुकेश अंबानी को इस विवाद से निजात दे दी थी, मगर मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी गई. उसके बाद इसे स्टे पर स्टे मिल रहा है. सवाल यह है कि यतीमखाना और मस्जिद को समाप्त करके वक्फ़ की यह भूमि ग़ैरक़ानूनी तौर पर किस तरह बेची गई? इसे किसने बेचा? इस मामले में पर्दे के पीछे कौन–कौन सी हस्तियां छिपी हुई हैं? और, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी क़ाबिले एहतराम संस्था इस पूरे विवाद में पड़ने से क्यों कतरा रही है?

वर्ष 2002 में यह संपत्ति अंतीलिया कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने करीम भाई खोजा ट्रस्ट से वक्फ़ एक्ट के सेक्शन 51 की अवहेलना करते हुए खरीदी थी. इस ख़रीद–फ़रोख्त ने महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ–साथ कई अहम हस्तियों की मिलीभगत का पर्दाफाश किया है. उस समय महाराष्ट्र के वक्फ़ मंत्री नवाब मलिक ने इसका विरोध किया था. इसी तरह राज्य सरकार के रेवेन्यू विभाग ने भी आपत्ति जताई थी. शुरुआत में महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज करते हुए वक्फ़ बोर्ड से बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा था. बहरहाल, इस मामले पर राज्य वक्फ़ बोर्ड ने अंतीलिया कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 16 लाख रुपये की धनराशि पाने के बाद अपनी पीआईएल वापस ले ली और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया. जून 2011 में केंद्र ने महाराष्ट्र से इस मामले को सीबीआई के हवाले करने के लिए कहा, परंतु ऐसा नहीं हो सका. उस समय इस मुद्दे पर बहुत हंगामा हुआ था और महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड के सीईओ ए आर शेख का स्थानांतरण कर दिया गया था.

वक्फ़ काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सचिव डॉ. मोहम्मद रिज़वानुल हक़ ने चौथी दुनिया को बताया कि जब यह मामला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समक्ष लाया गया और यह मांग की गई कि इस वक्फ़ भूमि पर यतीमखाने के अलावा एक मस्जिद भी थी, जो कि मुकेश अंबानी के महल तले ज़मींदोज़ हो गई. अतएव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मस्जिद एवं यतीमखाने के मुद्दे को अपने एजेंडा में सम्मिलित करे और इस सिलसिले में प्रस्ताव भी पारित करे. परंतु इस मांग को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि बोर्ड केवल बाबरी मस्जिद के मामले तक ही सीमित है, वह किसी अन्य मस्जिद के मामले को अपने अधीन नहीं लेगा. कुछ मुस्लिम संगठन इस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट ले गए. मुकेश अंबानी की ओर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य एवं विधि विशेषज्ञ यूसुफ हातिम मुछाला ने अपने वकीलों की टीम के साथ मुक़दमा लड़ा और सफलता प्राप्त की. यह कैसी विडंबना थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वरिष्ठ सदस्य मस्जिद एवं यतीमखाने की वक्फ़ भूमि के स्वामित्व के ख़िलाफ मुकेश अंबानी के हित की पैरवी कर रहा था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए दायर की गईं चार पिटीशनों में से मुकेश अंबानी का नाम निकाल कर अलग कर दिया, जिसके फलस्वरूप मुकेश को क़ानूनी तौर से राहत मिल गई. उन दिनों उर्दू मीडिया को भी मैनेज किया गया, जिसके चलते उस दिन उर्दू अख़बारों ने अपने फ्राइडे एडिशन में मुकेश अंबानी को बेकसूर बताते हुए उनकी सफलता पर मुबारकबाद दी.

मौलाना सैय्यद निजामुद्दीन

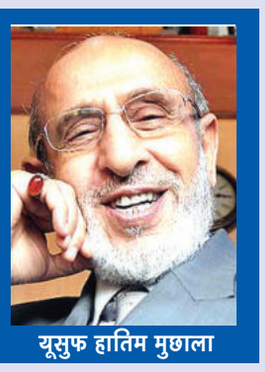
यूसुफ हातिम मुछाला

हाईकोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध कुछ मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला लिया. तब अंबानी ग्रुप की ओर से उपरोक्त निर्णय पर स्टे लेने की योजना बनाई गई. विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कि अंबानी के वकील के निकट संबंधी हैं, के आवास पर रिट पिटीशन तैयार की गई और एक सप्ताह पहले से ही यह अफवाह सुनाई पड़ने लगी कि दिल्ली में जज साहब से स्टे के लिए बात कर ली गई है. अंतत: यह अफवाह सच साबित हुई और मुकेश अंबानी को स्टे मिल गया. उसके बाद से स्टे के बाद स्टे का सिलसिला जारी है और इस तरह अंबानी का महल अपनी जगह बरकरार है.

गत वर्ष के अंत में, 5 सितंबर, 2013 को लोकसभा में वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2010 पर बहस के दौरान भी मुकेश अंबानी के अंतिलिया कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खोजा मुस्लिम चैरिटेबल संस्था से खरीदे एवं वहां उनके महल अंतिलिया का निर्माण किए जाने का मुद्दा उठा, जिस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तिहादुल मुस्लमीन के अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बैरिस्टर भी हैं, ने वक्फ़ क़ानून को ही उपरोक्त एवं अन्य वक्फ़ संपत्तियों पर क़ब्जे का कारण बताया. उनका साफ़ तौर पर कहना था कि इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति ने मुंबई के एक यतीमखाना की भूमि पर क़ब्जा जमाया. उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने यतीमों की भूमि ले ली.

चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए उनका यह भी कहना था कि वह ऐसा करने में इसलिए सफल हो गए, क्योंकि उस राज्य में पूरे अधिकारों के साथ और क़ानूनी तौर पर कोई वक्फ़ बोर्ड बना हुआ नहीं था. अतएव उसके सीईओ ने उन्हें हरी झंडी दे दी. उनके अनुसार, एक पूर्ण अधिकार वाला बोर्ड इसीलिए आवश्यक है. इस तरह के बोर्ड के बिना भविष्य में वक्फ़ भूमि पर ग़ैरक़ानूनी एवं अनाधिकृत क़ब्जों को रोका नहीं जा सकता है. उन्होंने इस बात पर भी जोर डाला कि हिंदू एंडाऊमेंट बोर्ड की तरह वक्फ़ बोर्ड को भी वही अधिकार दिए जाने चाहिए. उन्होंने बताया कि कुछ अन्य राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश में हिंदू एंडाऊमेंट बोर्ड के पास क़ब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने, पूर्ण रूप से क़ब्जा हटाने का अधिकार एवं पावर है, मगर अभी हाल में बनाए गए नए वक्फ़ क़ानून में वक्फ़ बोर्ड को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है. उनका इस बात पर जोर है कि वक्फ़ क़ानून में ऐसा प्रावधान अवश्य होना चाहिए कि अगर एक मजिस्ट्रेट क़ब्जा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए.

इस पूरे मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका सबसे अधिक अफ़सोसनाक है. एक बात तो यह रही कि इसके क़ानूनी वकील ने स्वयं मुकेश अंबानी के इस मुकदमे में मुख्य भूमिका निभाई. और दूसरी बात यह है कि इसके महासचिव मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन ने इस पूरे मामले से यह कहकर कन्नी काट ली कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दायरा मात्र बाबरी मस्जिद एवं उससे संबंधित वक्फ़ भूमि तक ही सीमित है. अतएव वह किसी और मस्जिद या वक्फ़ भूमि के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा. सवाल यह है कि आख़िर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मामले में दिलचस्पी लेने से कौन रोक रहा है? ज़ाहिर सी बात है कि इसके कुछ वरिष्ठ सदस्यों के स्वार्थ के ही कारण ऐसा हो रहा है. क़ाबिले ग़ौर है कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही वक्फ़ भूमि पर स्थित मस्जिद एवं यतीमखाना के मामले में आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर आख़िर कौन बढ़ेगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

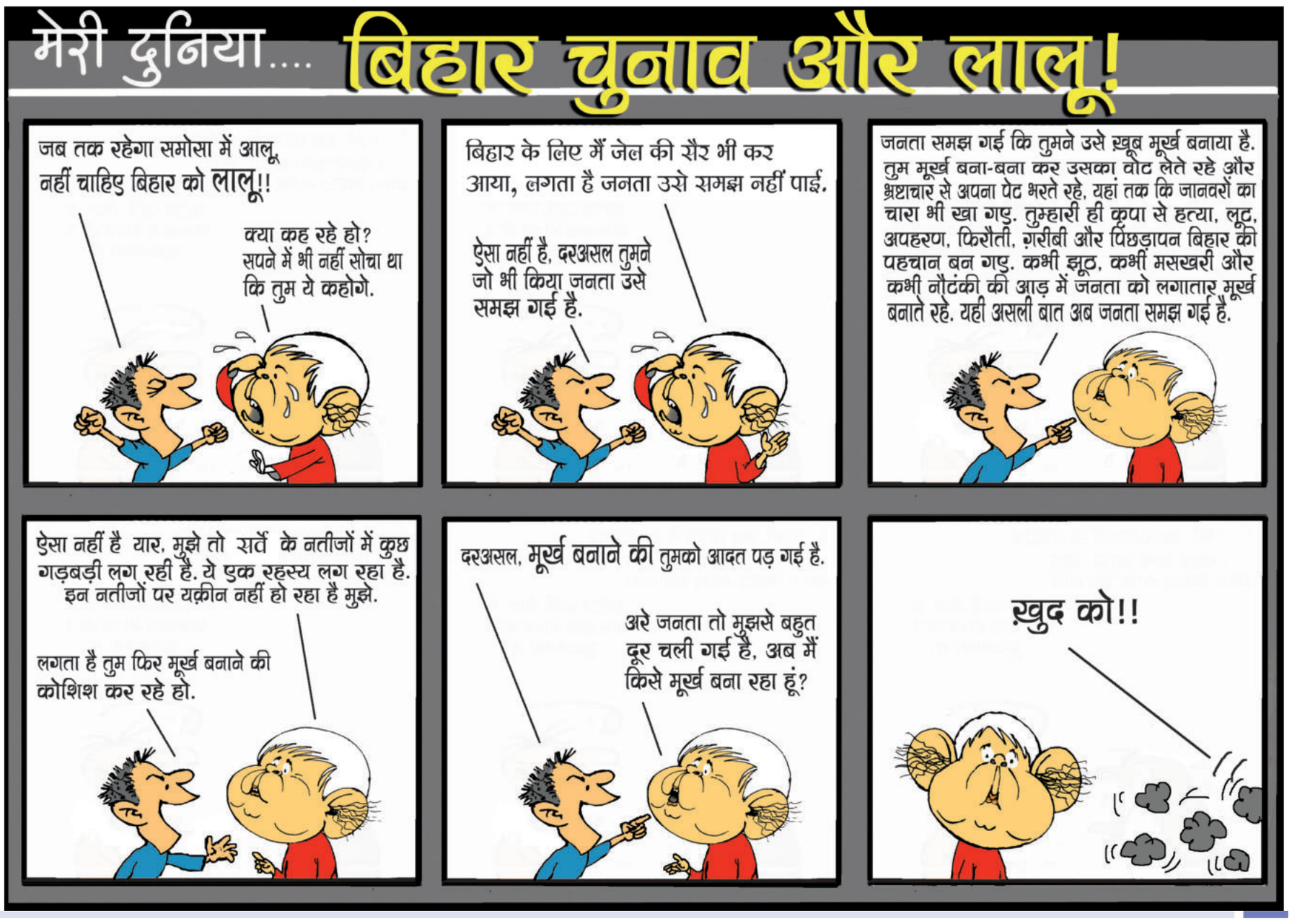

यह उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के फर्जीवाड़े का छोटा–सा नमूना है. अगर भर्ती करने के पहले पुलिस वेरीफिकेशन की हालत इतनी खस्ता है, तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे न जाने कितने कर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस में होंगे. साजिद नाडियाडवाला के घर यह वारदात 9 जनवरी, 2009 को हुई थी, जिसमें क़रीब 40 लाख रुपये के गहने और लगभग 10 लाख रुपये नगद दिनदहाड़े लूट लिए गए थे.

# विदेशी पर्यटकों को भारत में डर लगता है

नवीन चौहान

राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से महज एक किलोमीटर की दूरी पर 50 साल की डेनमार्क नागरिक के साथ हुए गैंग रेप और लूटपाट की घटना ने भारत में विदेशी सैलानियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. विदेशी पर्यटकों ख़ासकर महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराध में बढ़ोत्तरी की वजह से भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में कमी आने की संभावना जताई जा रही है. साल 2013 में एसोसिएशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने एक सर्वे कराया था, जिसके अनुसार भारत में विदेशी महिला पर्यटकों के साथ छेड़छाड और रेप की घटनाओं की वजह जनवरी से मार्च के बीच विदेशी पर्यटकों की संख्या में 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई थी. इसकी मुख्य वजह 16 दिसंबर, 2012 को राजधानी दिल्ली में फिजियोथैरेपिस्ट छात्रा निर्भया से गैंग रेप की घटना थी. इस बर्बर घटना के बाद दुनिया भर में भारत की तीखी आलोचना भी हुई थी. लिहाज़ा पिछले साल एसोचैम ने देश भर के 1200 टूर ऑपरेटरों के बीच यह सर्वे कराया था. इस सर्वे नतीजों से यह बात निकलकर सामने आई थी कि भारत में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के कारण साल 2013 के जनवरी माह में 72 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों ने अपना दौरा रद्द कर दिया था. दौरा रद्द करने वालों में ज़्यादातर पर्यटक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के थे.

रेप की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र कई देश अपने नागरिकों को भारत ना जाने की एडवाइजरी भी जारी करते रहे हैं. जिसका सीधा असर भारतीय पर्यटन उद्योग पर पड़ता है. सर्वे के मुताबिक़, भारत में महिला संबंधी अपराध की वजह से विदेशी पर्यटकों ने भारत छोड़ दूसरे एशियाई देशों में जाना पसंद किया.

ग़ौरतलब है कि पिछले साल मध्यप्रदेश के दतिया में भी एक स्विस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी. इसके अलावा, आगरा में एक ब्रिटिश युवती ने भी छेड़खानी से बचने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी. इस तरह की घटनाओं ने भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों पर काफी बुरा प्रभाव छोड़ा है. दिल्ली में निर्भया बलात्कार कांड की वजह से भारतीय पर्यटन उद्योग में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि डेनमार्क की महिला के साथ हुई रेप की घटना के बाद हालात और अधिक ख़राब होंगे. टूर ऑपरेटरों के अनुसार, निर्भया रेप मामले के बाद पर्यटन उद्योग को रिकवर होने में लगभग नौ महीने लग गए. समय रहते अगर ऐसी घटनाओं को रोका नहीं गया, तो भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव करेगा.

**2008 में मुंबई आतंकवादी हमले का असर भी पर्यटन उद्योग में देखा गया था. वर्ष 2009 में विदेशी सैलानियों की वार्षिक वृद्धि नकारात्मक(-2.2 प्रतिशत) थी . चूंकि 2008 की मंदी का असर भी पर्यटन उद्योग पर पड़ा था बावजूद इसके सुरक्षा विदेशी पर्यटकों के लिए मुख्य मुद्दा थी. वर्ष 2010 में विदेशी पर्यटकों की वजह से भारत को क़रीब 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आमदनी हुई थी. वहीं वर्ष 2011 में यह 16 बिलियन और 2012 में लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी.**

दुनिया भर में भारत की धूमिल होती छवि से चिंतित पर्यटन मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त महीने में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था. इस सम्मेलन में आई रिस्पेक्ट वीमेन नाम से एक कैंपेन भी लांच किया गया था. आई रिस्पेक्ट वीमेन कैंपेन के तहत भारत के टूर ऑपरेटर, टूर गाइड, टैक्सी, ऑटो ड्राइवर और होटल कारोबार से जुड़े लोग अंग्रेजी, कोरियन, जापानी, रूसी और चीनी भाषा में आई रिस्पेक्ट वीमेन का बैज लगाएंगे, और महिला पर्यटकों के साथ विनम्रता और शिष्टाचार से पेश आएंगे, ताकि विदेशी महिला पर्यटक बेख़ौफ़ भारत में भ्रमण कर सकें. हालांकि, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैज लगाने से क्या लोगों की सोच और बदलाव में कोई बदलाव आएगा?

उल्लेखनीय है वर्ष 2010 में विदेशी सैलानियों की संख्या में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई थी, लेकिन वर्ष 2012 में वर्ष 2011 की तुलना में केवल 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं वर्ष 2012 में विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी 0.64 प्रतिशत थी. वैश्विक पर्यटन में भारत 2011 में 38वें स्थान में था, जबकि 2012 में यह 41वें स्थान पर पहुंच गया.

**दुनिया भर में भारत की धूमिल होती छवि से चिंतित पर्यटन मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त महीने में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था. इस सम्मेलन में आई रिस्पेक्ट वीमेन नाम से एक कैंपेन भी लांच किया गया था. आई रिस्पेक्ट वीमेन कैंपेन के तहत भारत के टूर ऑपरेटर, टूर गाइड, टैक्सी, ऑटो ड्राइवर और होटल कारोबार से जुड़े लोग अंग्रेजी, कोरियन, जापानी, रूसी और चीनी भाषा में आई रिस्पेक्ट वीमेन का बैज लगाएंगे, और महिला पर्यटकों के साथ विनम्रता और शिष्टाचार से पेश आएंगे.**

2008 में मुंबई आतंकवादी हमले का असर भी पर्यटन उद्योग में देखा गया था. वर्ष 2009 में विदेशी सैलानियों की वार्षिक वृद्धि नकारात्मक(-2.2 प्रतिशत) थी . चूंकि 2008 की मंदी का असर भी पर्यटन उद्योग पर पड़ा था बावजूद इसके सुरक्षा विदेशी पर्यटकों के लिए मुख्य मुद्दा थी. वर्ष 2010 में विदेशी पर्यटकों की वजह से भारत को क़रीब 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आमदनी हुई थी. वहीं वर्ष 2011 में यह 16 बिलियन और 2012 में लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी. हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में पर्यटन से होने वाली आय की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है. भारत की जीडीपी में 6.6 प्रतिशत भागीदारी पर्यटन उद्योग की है. पर्यटन उद्योग भारत में लगभग 4 करोड़ नौकरियों का सृजन करता है.

ग़ौरतलब है कि भारत आने वाले विदेशी सैलानियों में लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं हैं. यदि भारत सरकार विदेशी सैलानियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती है, तो इसका दूरगामी असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है.■

feedback@chauthiduniya.com

# लूट के आरोपी को पुलिस की नौकरी!

अरुण तिवारी

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला का घर. शाम क़रीब तीन बजे डोर बेल बजने की आवाज़ सुनकर जैसे ही साजिद की पत्नी ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने देखा कि उनके सुरक्षा गार्ड ने उन पर रिवाल्वर तान रखी है. गार्ड ने उन्हें बंधक बना लिया. इसके बाद गार्ड और उसके साथ आए बदमाश डकैती को अंजाम देते हैं. साजिद के घर में इस बड़ी डकैती में चार लोग शामिल थे, लेकिन उनका सरगना आज उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बन बैठा है. इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि राज्य पुलिस के अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके महकमे में एक ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है, जिसने बड़ी डकैती को अंजाम दिया.

यह उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के फर्जीवाड़े का छोटा–सा नमूना है. अगर भर्ती करने के पहले पुलिस वेरीफिकेशन की हालत इतनी खस्ता है, तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे न जाने कितने कर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस में होंगे. साजिद नाडियाडवाला के घर यह वारदात 9 जनवरी, 2009 को हुई थी, जिसमें क़रीब 40 लाख रुपये के गहने और लगभग 10 लाख रुपये नगद दिनदहाड़े लूट लिए गए थे. चूंकि यह घटना मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से जुड़ी हुई थी, इस वजह से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. फिर इस कांड के मुख्य आरोपी प्रभात त्रिपाठी का नाम सामने आया, जिसे क्राइम ब्रांच ने लखनऊ से गिरफ्तार किया. प्रभात फिल्म अभिनेता सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड शेरा की कंपनी टाइगर में गार्ड का काम करता था. पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई कि मुख्य आरोपी प्रभात त्रिपाठी ने अपने तीन साथियों अनीस अनवारुल खान, शिवचंद रामकिशोर मौर्या और असगर रज्जब अली खान के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. प्रभात इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन इलाके का रहने वाला है. मुंबई के वर्सोवा थाने में इन चारों अभियुक्तों के ख़िलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 397, 341, 452, 120 बी, 506–2 और अवैध हथियार रखने के मामले में आर डब्ल्यू 3,25 के तहत मुकदमा दर्ज किया. वहीं पुलिस ने इस घटना के मुख्य अभियुक्त प्रभात त्रिपाठी के पास से 1,07,500 रुपये भी बरामद किए थे.

इस हाई प्रोफाइल वारदात की जांच कर रहे मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर ने उस समय बताया था कि इस घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने तीन–चार महीने पहले ही योजना बनानी शुरू कर दी थी. इसके बाद प्रभात और उसके दो साथी अनीस अनवारुल खान के संपर्क में आए, जो छोटा राजन गैंग का सदस्य था. इस घटना को अंजाम देने के लिए अनवारुल ने ही रिवाल्वर मुहैया कराई थी. सिर्फ़ इतना ही नहीं, एक शातिर अपराधी की तरह प्रभात ने शेरा की सिक्योरिटी एजेंसी में अपना पता भी गलत दे रखा था. इसे सिर्फ़ एक अपराधी का शातिराना क़दम ही कहा जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से मुंबई पुलिस को उसकी तलाश करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद और मुंबई पुलिस की तेज कार्रवाई के चलते उसे खोज निकाला गया. मुंबई पुलिस ने उसे लखनऊ में गिरफ्तार किया.

प्रभात त्रिपाठी

**अब सवाल यह उठता है कि अगर प्रभात के ख़िलाफ जांच चल रही है, तो वह अभियुक्त होते हुए भी पूरी तरह से ड्यूटी पर कैसे बहाल है? जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियमावली के अनुसार जिस व्यक्ति पर चार्जशीट दायर हो और वह 48 घंटे तक हिरासत में रहा हो, तो उसे विभाग द्वारा अयोग्य करार दिया जाता है. ऐसे में जब हमारी टीम द्वारा छानबीन की गई, तो ज्ञात हुआ कि आरोपी पर थाना कैंट इलाहाबाद में भी 22 दिसंबर, 2010 को एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप है और धारा 395 के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी प्रभात त्रिपाठी को पेश होने का आदेश जारी किया गया .**

साल 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फ़ैसला सुनाया और मायावती द्वारा निरस्त की गई भर्ती को फिर से बहाल कर दिया. कोर्ट के इस निर्णय का लाभ प्रभात त्रिपाठी को भी मिला. उसने अपने काले कारनामे को छिपाते हुए बहाली के दौरान झूठा हलफनामा दायर किया और नियुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया. वह मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में तैनात है. आरटीआई द्वारा इस बात की जानकारी मिली कि प्रभात के ख़िलाफ विभागीय जांच चल रही है. अधिकारियों से पूछताछ करने पर इस बात की पुष्टि हुई थी कि अभियुक्त प्रभात त्रिपाठी के क़ब्जे से 1,07,500 रुपये की बरामदगी करके उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. माता सुशीला त्रिपाठी ने एक लाख रुपये की एनएससी लगाकर प्रभात की जमानत कराई गई थी.

अब सवाल यह उठता है कि अगर प्रभात के ख़िलाफ जांच चल रही है, तो वह अभियुक्त होते हुए भी पूरी तरह से ड्यूटी पर कैसे बहाल है? जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियमावली के अनुसार जिस व्यक्ति पर चार्जशीट दायर हो और वह 48 घंटे तक हिरासत में रहा हो, तो उसे विभाग द्वारा अयोग्य करार दिया जाता है. ऐसे में जब हमारी टीम द्वारा छानबीन की गई, तो ज्ञात हुआ कि आरोपी पर थाना कैंट इलाहाबाद में भी 22 दिसंबर, 2010 को एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप है और धारा 395 के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी प्रभात त्रिपाठी को पेश होने का आदेश जारी किया गया है. इतना ही नहीं, आरोपी प्रभात साल भर तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ और उसने जमानत भी नहीं कराई. ऐसे में यह सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है कि लूट का आरोपी पुलिस वाला जनता की सुरक्षा में कितनी दिलचस्पी लेता होगा! उधर, विभागीय जांच के नाम पर यूपी पुलिस द्वारा जो खेल हो रहा है, उसे सहज ही समझा जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com



कमल मोरारका

**महंगाई एक बड़ा मसला है और लोगों का कांग्रेस से मोहभंग का एक बड़ा कारण भी. महंगाई ने सबको प्रभावित किया है. किसी ने कहा है कि महंगाई कराधान का एक सबसे ख़तरनाक रूप है. यह एकमात्र ऐसा कराधान है, जो संसद की अनुमति के बगैर लगता है. एक व्यक्ति जिसकी निश्चित आय है, वह चाहे बड़ी मात्रा में टैक्स दे या फिर महंगी वस्तुएं खरीदे, दोनों में क्या फर्क है? वास्तव में महंगाई वह शांत कराधान है, जो आम आदमी को मार देती है. आज वास्तव में महंगाई सबसे बड़ी समस्या है और विडंबना यह है कि राहुल गांधी इस विषय पर कोई राय नहीं रखते हैं. जैसा है, वैसे ही चलता जा रहा है, हर स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी.**

# राहुल गांधी के इन प्रयासों से क्या हासिल होगा

लोकसभा चुनावों में अब चार महीने ही बचे हैं. इस संदर्भ में आधिकारिक सूचना भी संभवत: 22 फरवरी के आसपास संसद सत्र की समाप्ति के बाद जारी कर दी जाएगी. चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के संदर्भ में कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वह एक जैसी ही बातें हर जगह कर रहे हैं. उनके पास नया कहने के लिए बमुश्किल ही कुछ बचा है. दूसरी तरफ़ कांग्रेस पार्टी एकाएक खुद में कुछ नयापन दिखा रही है. पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब आक्रामक छवि अख्तियार कर रहे हैं और अपने हावभाव में भी जोश प्रकट कर रहे हैं. बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब काफी देर कर दी है. कांग्रेस पार्टी अब जो कोशिशें कर रही है, उसका मई में होने लोकसभा चुनावों पर कोई खास असर पड़ेगा, ऐसा लग नहीं रहा है.

राहुल गांधी को इन प्रयासों की शुरुआत तीन साल पहले ही कर देनी चाहिए थी. वास्तव में जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में जनलोकपाल को लेकर अनशन कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने लोकसभा में इस मसले पर हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि जनलोकपाल को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन यह बात वहीं ख़त्म हो गई. हो सकता है कि वह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष या फिर किसी और के दबाव में रहे हों. उस दौर में उन्हें वे क़दम उठाने चाहिए थे, जो वह आज उठा रहे हैं. मुझे लगता है कि पिछले दो–ढाई वर्षों में परिस्थितियां काफी बदल सकती थीं. राहुल गांधी युवा पीढ़ी के नेता हैं और ऐसे में अगर वह व्यवस्था में बदलाव की बात करते, तो उनकी एक विश्वसनीयता भी रहती, लेकिन बीते दो वर्षों में कई घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ. हां, यह ज़रूर है कि पहले दागी सांसदों–विधायकों के अध्यादेश के मुद्दे पर अपनी जोरदार राय रखकर और फिर जनलोकपाल बिल को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राहुल गांधी ने सही दिशा हासिल की, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता. देश की जनता अब यह मानने को तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस मुद्दों को लेकर गंभीर भी है.

दूसरी तरफ़ भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण भारत और पूर्व में बड़ा जनाधार नहीं है, इसलिए अगर वह उत्तर भारतीय राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती भी है, तो भी 170–175 सीटों पर आकर ही ठहर जाएगी. ऐसी स्थिति में भी वह नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना रही है, जो कि हास्यास्पद लगता है. अगर भाजपा को लगता है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी के कारण उसे सीटें मिल रही हैं, तो बिना 272 सीटों के वह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी? व्यवहारिक तौर पर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में जो सीटें मिल रही हैं, वे पार्टी या फिर किसी और व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं मिल रही हैं. वे सीटें भाजपा कैडर और कांग्रेस विरोधी लहर के कारण मिल रही हैं. राजस्थान का उदाहरण लीजिए. विधानसभा चुनावों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 199 सीटों में से 163 सीटें अशोक गहलोत की अयोग्यता के कारण नहीं, बल्कि कांग्रेस विरोधी लहर और केंद्र में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की नकारात्मक छवि बनने की वजह से मिलीं.

महंगाई एक बड़ा मसला है और लोगों का कांग्रेस से मोहभंग का एक बड़ा कारण भी. महंगाई ने सबको प्रभावित किया है. किसी ने कहा है कि महंगाई कराधान का एक सबसे ख़तरनाक रूप है. यह एकमात्र ऐसा कराधान है, जो संसद की अनुमति के बगैर लगता है. एक व्यक्ति जिसकी निश्चित आय है, वह चाहे बड़ी मात्रा में टैक्स दे या फिर महंगी वस्तुएं खरीदे, दोनों में क्या फर्क है? वास्तव में महंगाई वह शांत कराधान है, जो आम आदमी को मार देती है. आज वास्तव में महंगाई सबसे बड़ी समस्या है और विडंबना यह है कि राहुल गांधी इस विषय पर कोई राय नहीं रखते हैं. जैसा है, वैसे ही चलता जा रहा है, हर स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी.

आम आदमी पार्टी को राजनीति में एक बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है. अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है. एक हद तक यह ठीक भी है, लेकिन केजरीवाल इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि वह वास्तव में व्यवस्था में किस तरह का बदलाव करना चाहते हैं. स्थिति तब और दु:खद हो जाती है, जब मीडिया भी इसका सही ढंग से विश्लेषण नहीं करता. उनकी सरकार का एक मंत्री पुलिस को कार्रवाई करने को कहता है और स्थितियां बिगड़ जाती हैं. यहां मसला यह नहीं है कि मंत्री को स्वयं यह क़दम उठाना चाहिए था या नहीं? असल मसला तो यह है कि इसकी प्रक्रिया क्या है? अगर गलत परंपरा बनने लगेगी, तो आप उसे कैसे संभालेंगे? केजरीवाल ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर) घूस लेते हैं. कुछ लोगों ने जांच की मांग की. वास्तव में यह जांच का मसला नहीं है. क्या किसी ने इससे मना किया? गृहमंत्री ने भी इसके लिए मना नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं, कोई न कोई दिक्कत तो है, यह हर कोई मान रहा है.

दिल्ली में पुलिस द्विभाजन के रूप में है. मुख्यमंत्री का पुलिस पर अधिकार नहीं है. पुलिस उपराज्यपाल और केंद्र के अधीन है. मुंबई में एकसत्तात्मक व्यवस्था है. दिल्ली में ऐसा नहीं है, यहां दोहरी सत्तात्मक व्यवस्था है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली में पुलिस को मुख्यमंत्री के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि वहां पर इसकी प्रक्रिया क्या है? लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली पुलिस में गड़बड़ ज़रूर है. अपराध बढ़ता ही जा रहा है. हां, यह ज़रूर है कि दिल्ली में बड़ी जनसंख्या निवास करती है, वहां पर बेहतर मौक़े हैं, संभ्रांत लोग हैं. ऐसे में अपराध की संभावना भी बढ़ती है, लेकिन इस अपराध की एक बड़ी वजह पुलिसिया कार्रवाई का अभाव भी है. दिल्ली पुलिस के एसएचओ इस बात के लिए बदनाम हैं कि पहले तो वे कार्रवाई ही नहीं करते और करते भी हैं, तो पक्षपाती तौर पर. ऐसे में केजरीवाल जो कह रहे हैं, वह कोई नई बात नहीं है. हर कोई इससे अवगत है. हो सकता है कि वह धरने पर बैठकर इस मसले पर लोगों का ध्यान खींचना चाहते हों, लेकिन देश में व्याप्त समस्याओं का हल धरने से नहीं होने वाला.

देश के वरिष्ठ लोगों, संभवत: प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह एक कमेटी बनाएं, जो जनता की बेहतरी के लिए व्यवस्था में बदलाव लाने की दिशा में काम करे. इसकी शुरुआत वह दिल्ली पुलिस से कर सकते हैं. एक मंत्री अगर इस प्रकरण को लोगों की निगाह में लाया है, तो इस मौक़े का फायदा उठाइए और इस समस्या को ठीक करिए. जहां पर भी अपराध होता है, ऐसा देखा गया कि अपराध इसलिए हुआ, क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. सिविल सोसाइटी के लोग, देश के नामी–गिरामी वकील एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता सभी क़ानून मंत्री में दोष खोज रहे हैं. भले ही वह क़ानून मंत्री हैं, लेकिन उसके पहले देश के नागरिक भी तो हैं, उस क्षेत्र के विधायक भी हैं. ठीक है, हो सकता है कि जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, वह गलत थी, तो वास्तविकता क्या थी, इस पर भी गौर करना चाहिए. क्या वहां पर कोई ड्रग रैकेट था? ठीक है कि क़ानून मंत्री रेसिस्ट हैं, यह कहा जा रहा है, लेकिन अगर युगांडा और नाइजीरिया के नागरिक ड्रग्स के अवैध कारोबार में लिप्त हैं, तब उनके ख़िलाफ कार्रवाई करना रेसिज्म नहीं है. वास्तव में पिछले 10–15 वर्षों के भीतर सिस्टम पूरी तरह से असफल हो गया है और यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ है. आप किससे कहने जाएंगे? हर अधिकारी एक जैसा है. हर कमिश्नर, जो कि दिल्ली आता है, वैसा ही हो जाता है. अब यह प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी है कि वह गृहमंत्री से बात करें या फिर उन्हें चाहिए कि वह गृहमंत्री को ही बदलें. इस मुद्दे पर और गंभीर होने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा मसला है. 16 दिसंबर, 2012 के दुष्कर्म प्रकरण के बाद भी दिल्ली में न जाने कितने बलात्कार हुए! ज़रूरी है कि कुछ बड़े उठाए जाएं. नहीं तो कम से कम कोशिश ही की जाए, वरना राहुल गांधी के प्रयासों के कोई मायने नहीं रह जाएंगे..■

feedback@chauthiduniya.com

# उम्मीदवार का चयन

ठाकुर दास बंग

*अगर प्रतिनिधि के चुनाव में कई नाम आ जाएं, तो क्या होगा?*

ऐसा हो सकता है कि कई नाम आ जाएं, चुनाव आख़िर चुनाव है, लेकिन हर चीज का उपाय है. अगर आपकी इकाई के मतदाताओं को 3 प्रतिनिधि चुनने हैं, तो उनका चुनाव इस प्रकार होगा, मान लीजिए कि मतदाताओं की बैठक हो रही है. सभा का संचालन करने वाला सभापति लोक उम्मीदवार का विचार समझा देने के बाद सबसे पहले नाम मांगेगा. सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि एक ऐसा नाम आ जाए, जिसे सब पसंद कर लें और उसका चुनाव निर्विरोध हो जाए. लेकिन, ऐसा उन्हीं क्षेत्रों में होगा, जिनमें ऐसे लोग होंगे, जो सेवाभावी, चरित्रवान एवं लोकप्रिय होंगे. अन्य क्षेत्रों में प्राय: कई नाम आएंगे. मान लीजिए, 3 जगहों के लिए 6 नाम आए, तो सब नाम किसी बोर्ड पर लिख दिए जाएं और सभा का सभापति सब नामों को धीरे–धीरे सुना दे. नाम मोटे अक्षरों में लिखे जाएं, ताकि हर आदमी देख सके. इस नाते गांव के स्कूल में सभा बुलाना हमेशा अच्छा होगा, स्कूल के शिक्षकों की मदद भी मिल जाएगी. जब सबको मालूम हो जाए कि किसके–किसके नाम आए हैं, तो वोट लिया जाए. सिलसिलेवार हर नाम पर बारी–बारी वोट हो और वोट हाथ उठाकर हो. जिस नाम पर जितने हाथ उठें, उतने गिनकर उस नाम के सामने बोर्ड पर साफ़–साफ़ लिख दिए जाएं. पहले वोट में जिसे सबसे कम वोट मिलें, उसका नाम छांट दिया जाए. इस तरह पहला वोट पूरा हो गया और दूसरे वोट के लिए 6 में से एक नाम छंट जाने के बाद 5 नाम बच गए. अब दूसरी बार भी पहली बार की तरह ही वोट लिया जाए. दूसरा वोट होने के बाद तीसरे वोट के लिए 4 नाम बचेंगे. इसी तरह तीसरे वोट के बाद केवल 3 नाम बचेंगे. अंत में जो तीन नाम बच जाएं, उन्हें सफल माना जाए, क्योंकि आपको तीन प्रतिनिधि चाहिए. वे ही आपके गांव के प्रतिनिधि माने जाएंगे.

**अच्छी बात तो यह होगी कि एक ऐसा नाम आ जाए, जिसे सब पसंद कर लें और उसका चुनाव निर्विरोध हो जाए. लेकिन, ऐसा उन्हीं क्षेत्रों में होगा, जिनमें ऐसे लोग होंगे, जो सेवाभावी, चरित्रवान एवं लोकप्रिय होंगे.**

*प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाने के बाद क्या होगा?*

मान लीजिए, क्षेत्र भर की कुल प्राथमिक इकाइयों में ऊपर बताई गई पद्धति के अनुसार चुनाव हुए और कुल 400 प्रतिनिधि चुने गए, तो इन्हीं 400 प्रतिनिधियों को मिलाकर क्षेत्र का निर्वाचक मंडल बनेगा.

*लोक उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं खड़ा होगा, तो क्या प्रतिनिधियों के चुनाव में राजनीतिक दल के लोग भाग ले सकते हैं?*

राजनीतिक दल का आदमी भी प्राथमिक इकाई में प्रतिनिधि के लिए अपना मत दे सकता है, क्योंकि वह मतदाता है, लेकिन वह स्वयं प्रतिनिधि नहीं हो सकता. प्रतिनिधि वही हो सकता है, जो निर्दलीय है. यह महत्व की बात है, इसे सभा के सामने अच्छी तरह से समझा देना होगा.

*क्षेत्र भर से 400 प्रतिनिधि चुन लिए गए और उनका निर्वाचक मंडल बन गया. अब यह निर्वाचक मंडल क्या करेगा?*

लोक उम्मीदवार तय करेगा, यह इसीलिए तो बना है.

*यह कार्य कैसे होगा और बैठक कौन बुलाएगा?*

निर्वाचक मंडल की बैठक क्षेत्र के किसी केंद्रीय स्थान पर बुलाई जाएगी. कार्यकर्ता या नागरिक, जो लोग लोक उम्मीदवार का काम कर रहे होंगे, वे पहली बैठक बुला सकते हैं. निर्वाचक मंडल की बैठक किसी ऐसे विद्यालय में बुलाई जाए, जिसके शिक्षक एवं आसपास के लोग लोक उम्मीदवार के विचार के अनुकूल हों और चयन के काम में मददगार हों. बैठक में चार–पांच घंटे से कम समय नहीं लगेगा. हो सकता है कि कई नाम होने के कारण जल्द फ़ैसला न हो, तो एक दिन के बाद दूसरे दिन भी बैठना पड़े. किसी विद्यालय के हॉल में बैठक हो, तो सुविधा होगी. एक वरिष्ठ, निष्पक्ष एवं चरित्रवान व्यक्ति सभापति चुना जाए. संभव हो तो प्रार्थना से सभा शुरू हो. पहले सभापति स्वयं या कोई मुख्य व्यक्ति अच्छी तरह समझा दे कि सभा किसलिए बुलाई गई है और काम किस पद्धति से होगा. लोग जो प्रश्न पूछें, उनका समझा कर, धीरज के साथ उत्तर दिया जाए. दो बातें साफ़–साफ़ और बार–बार समझाई जाएं. पहली बात यह कि किसी राजनीतिक दल का सदस्य न प्रतिनिधि हो सकता है, न लोक उम्मीदवार. दूसरी बात यह कि निर्वाचक मंडल का सदस्य स्वयं उम्मीदवार नहीं हो सकता. ये बातें सब लोग अच्छी तरह समझ जाएं, तो सभापति लोक उम्मीदवार के लिए नाम मांगें. नाम मांगने पर दो बातें सामने आ सकती हैं, या तो एक नाम आएगा या एक से अधिक नाम आएंगे. यदि एक ही नाम आया तो बहुत अच्छा, वही लोक उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अगर एक से अधिक नाम आए, तो मतदान होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

**निर्वाचक मंडल की बैठक किसी ऐसे विद्यालय में बुलाई जाए, जिसके शिक्षक एवं आसपास के लोग लोक उम्मीदवार के विचार के अनुकूल हों और चयन के काम में मददगार हों. बैठक में चार-पांच घंटे से कम समय नहीं लगेगा. हो सकता है कि कई नाम होने के कारण जल्द फ़ैसला न हो, तो एक दिन के बाद दूसरे दिन भी बैठना पड़े. किसी विद्यालय के हॉल में बैठक हो, तो सुविधा होगी. एक वरिष्ठ, निष्पक्ष एवं चरित्रवान व्यक्ति सभापति चुना जाए.**

# पाठकों की दुनिया



## उम्मीदों पर पानी फेरा

जनता ने मायावती को बेदखल करके सूबे की सत्ता अखिलेश यादव के हाथों में इस उम्मीद के साथ सौंपी थी कि वह अपनी पार्टी पर लगे आरोपों के दाग मिटाकर कुछ कठोर फ़ैसले लेंगे और जाति–धर्म से परे हटकर जनहितैषी कार्य करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह एवं अखिलेश ने जनता की सारी उम्मीदें तार–तार कर दीं. मुजफ्फरनगर जिस तरह दंगे की आग में जला, उससे मुस्लिम समुदाय में सपा के प्रति खासा रोष है. मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर आज तक मुलायम सिंह एवं अखिलेश कुछ करना तो दूर, कुछ कह भी नहीं रहे हैं. अगर ऐसा रहा, तो मुलायम सिंह के प्रधानमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा.

**–जावेद अंसारी,** *देवरिया, उत्तर प्रदेश.*

## एक बेबाक विश्लेषण

20–26 जनवरी का अंक मिला. कवर स्टोरी–भारत बन गया दुनिया का सबसे भ्रष्ट प्रजातंत्र में संतोष भारतीय ने यूपीए के दस वर्षों के शासनकाल की जो तस्वीर पेश की, वह निस्संदेह चिंता पैदा करने वाली है. हमारा देश इन 10 वर्षों में कहां से कहां चला गया, महंगाई किस गति से बढ़ी, भ्रष्टाचार ने किस कदर आम आदमी का जीना दूभर कर दिया और सिस्टम में मनमानी के चलते विकास की रफ्तार कैसे थम–सी गई, जैसे बिंदुओं का बेबाक विश्लेषण बताता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है, बल्कि यह कहा जाए कि कुछ भी अच्छा नहीं है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी.

**–प्रतीक, पालम कालोनी,** *नई दिल्ली.*

## केजरीवाल और आंदोलन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वह अराजक हैं. यह सच है कि वह लोकसभा चुनाव की जल्दी में अराजक हो गए हैं. वह कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं. जबकि सच यह है कि वह अपने स्वार्थवश और मीडिया में बने रहने के लिए आंदोलन करते हैं. केजरीवाल देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि वह एक मुख्यमंत्री होते हुए भी पुलिस के ख़िलाफ धरना देते हैं. देश में पुलिस से तंग आ चुके लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा, यही उनकी रणनीति है. पुलिस पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वह नेताओं के इशारे पर काम करती है और केजरीवाल खुद चाहते हैं कि पुलिस उनके और उनकी काबीना के अनुसार कार्य करे. केजरीवाल एक तरफ़ यह चाहते हैं कि सीबीआई को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ़ वह चाहते हैं कि पुलिस उनके अधीन कार्य करे.

**–दीपक,** *रायपुर, छत्तीसगढ़.*

## कांग्रेस की परंपरा

कांग्रेस पार्टी ने परंपरा की दुहाई देते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया. कांग्रेस के कुछ नेता एवं कार्यकर्ता चाहते थे कि राहुल गांधी को चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, लेकिन सोनिया गांधी एवं कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना था कि यदि ऐसा होगा, तो लोकसभा चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाएगा. ऐसे में, अगर कांग्रेस की हार होती है, तो हार का ठीकरा राहुल के सिर पर फूटेगा. इसलिए कांग्रेस परंपरा की दुहाई देकर प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करने से बच गई.

**–हेमेंद्र सिंह,** *गाजीपुर, उत्तर प्रदेश.*

## सरकारी भोंपू

आलेख–सरकार का भोंपू: दूरदर्शन और आकाशवाणी (अंक: 20–26 जनवरी) खासा विचारोत्तेजक है. प्रियंका प्रियम तिवारी ने दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के कामकाज और विश्वसनीयता में आई गिरावट पर बख़ूबी प्रकाश डाला है. बीते दस सालों में इन दोनों प्रचार माध्यमों ने आम जनता को काफी निराश किया. दीगर चैनल दिनोंदिन तरक्की करते रहे, लेकिन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सिर्फ़ सरकार की वाहवाही में जुटे रहे. और तो और, प्रसार भारती का संचालन अपने हाथों में लेकर सरकार ने उसे भी अपनी जेबी संस्था बना लिया.

**–त्रिलोक कुमार झा,** *दरभंगा, बिहार.*

## भारतीय प्रतिभाओं ने मान बढ़ाया

आलेख–भारतीय शख़्सियतों ने लहराया परचम (अंक:27 जनवरी–02 फरवरी) पढ़ा, अच्छा लगा. दुनिया के हर कोने में भारतीयों ने अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं. वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आज़ाद, समाजसेवी अन्ना हज़ारे, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा एवं अमिताभ बच्चन जैसी शख़्सियतों ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है. अपने इस आलेख के जरिए राजीव रंजन ने इन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में पाठकों को ज्ञानवर्द्धक एवं विस्तृत जानकारी दी है.

**–आर. के. सक्सेना,** *ग्वालियर, मध्य प्रदेश.*

## ग़रीबों से छलावा

आम आदमी पार्टी और उसकी दिल्ली सरकार की सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि ग़रीबों का शोषण–उत्पीड़न बढ़ाने वाली है. दिल्ली सरकार ने 48 घंटे के अंदर मध्यम वर्ग को दो बड़े तोहफे दिए. पहला, प्रत्येक मीटर वाले घर को प्रतिदिन मुफ्त 667 लीटर पानी और दूसरा, 400 यूनिट तक रियायती बिजली. मीटर वाले घर अधिकतर मध्यम वर्ग के हैं, लेकिन ग़रीबों के पास न मीटर है और न बिजली–पानी. ऐसे में उन्हें इस घोषणा से क्या लाभ मिलेगा? क्या सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ सिर्फ़ मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए? क्या दिल्ली के ग़रीबों के वोटों की कोई क़ीमत नहीं है.

**–विकास कुमार पाटनी,** *कोडरमा, झारखंड.*

**पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :**

**चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301**

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com







संतोष भारतीय

# जब तोप मुक़ाबिल हो



## आशाओं और आशंकाओं के फ़ैसले का वक्त

मुझसे एक अजीब सवाल पूछा गया कि क्या अन्ना का आंदोलन समाप्त हो गया? क्या अन्ना शांत होकर बैठ गए? क्या इतने शांत हो गए हैं कि देश में जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है, उसके ऊपर उनकी कोई राय नहीं है? यह सवाल सुनकर मैं इसलिए चौंका, क्योंकि सवाल पूछने वाला व्यक्ति अन्ना जी का समर्थक है और उन्हें दिलो–जान से चाहता है. ऐसे व्यक्ति के मन में भी जब यह सवाल खड़ा हो, तब यह जानने की ज़रूरत है कि आख़िर अन्ना कर क्या रहे हैं.

अन्ना इस समय अपने आश्रम रालेगण सिद्धि में हैं, जो पूना से 80 किलोमीटर दूर है. पिछले अक्टूबर माह से अन्ना की तबियत ठीक नहीं चल रही है. अन्ना ने 30 मार्च, 2013 से देशव्यापी जनतंत्र यात्रा की शुरुआत की थी. अमृतसर का जलियावालां बाग यात्रा का प्रारंभ बिंदु था. आख़िरी बिंदु का तो पता नहीं, लेकिन पांच महीने अन्ना देश के छह राज्यों में घूमे. इन छह राज्यों में उन्हें अपार जनसमर्थन मिला. लोगों ने उनका साथ देने का वायदा किया. अन्ना उस उत्साह को देखकर गदगद थे और यात्रा जारी रखना चाहते थे, लेकिन अचानक अन्ना की कुछ बीमारियां उभर आईं. अन्ना की उम्र इस समय 76 वर्ष है और कुछ बीमारियां उम्र से भी जुड़ी होती हैं. अन्ना को जब पेशाब करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी, तब उनका एक साधारण–सा ऑपरेशन प्रोस्टेट का हुआ, लेकिन प्रोस्टेट में डॉक्टरों को एक गांठ नज़र आई, तो वह साधारण–सा ऑपरेशन अचानक बड़ा हो गया. डॉक्टरों को वह गांठ निकालने में लगभग सात घंटे तक मेहनत करनी पड़ी. इस प्रक्रिया में अन्ना का इतना खून बह गया कि उनकी शारीरिक क्षमता निम्नतम स्तर पर आ गई थी. अन्ना ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने से मना किया और वह प्राकृतिक आहार से अपने शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करने लगे. अचानक एक दूसरी बीमारी सामने आई. अन्ना ने छह प्रदेशों की अपनी यात्रा सड़क मार्ग से की थी. लगभग 750 सभाएं हुईं और इन सभाओं के लिए गड्ढे भरी सड़कों, पहाड़ी सड़कों पर यात्रा के चलते अन्ना की रीढ़ की हड्डी में समस्या पैदा हो गई. उनकी रीढ़ की हड्डी के दो मनके घिस गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, जिसकी दवाएं चल रही हैं. अन्ना की आवाज़ में भी कमजोरी दिखाई दे रही है. ऐसी स्थिति में भी अन्ना अपने आश्रम में प्रतिदिन उन सबसे मिलते हैं, जो मिलने आते हैं. रालेगण में उनसे मिलने के लिए देश भर से आने वालों का मेला लगा रहता है. अन्ना के पास सिर्फ़ दोपहर में सोने के लिए एक घंटा है, जो संभवत: साढ़े तीन से साढ़े चार बजे का है, जब वह किसी ने नहीं मिलते. अन्यथा वह सुबह साढ़े आठ से लेकर रात साढ़े नौ–दस बजे तक लोगों से मिलते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं और देश के हालात पर बातचीत करते रहते हैं.

अन्ना राजनेता नहीं है कि प्रतिदिन प्रेस को बुलाएं और अपने वक्तव्य दें. और, चूंकि अन्ना राजनेता नहीं हैं, इसलिए राजनीतिज्ञ भी उनके पास नहीं जाते. अन्ना के समर्थक, खासकर उत्तर भारत के समर्थक उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वे यात्रा कर रालेगण सिद्धि पहुंच सकें. दूसरी तरफ़ मीडिया अन्ना के पास तभी जाता है, जब देश में कोई क्राइसिस हो या अरविंद केजरीवाल को लेकर उसे अन्ना से ऐसी कोई बाइट या वक्तव्य चाहिए, जो देश में कुछ अंतर्विरोध पैदा कर सके. यहां एक बात और देखने में आई है कि मीडिया अन्ना से कभी देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, विरोधी दलों के बारे में या विकास के बारे में सवाल नहीं पूछता. ज़्यादातर सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर पूछे जाते हैं. अन्ना ऐसे सवालों का जवाब देने से हिचकते हैं, क्योंकि उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण है. इसीलिए अन्ना मीडिया को बहुत प्रोत्साहित भी नहीं करते. पिछले दिनों मीडिया के कुछ लोग रालेगढ़ गए और उन्होंने अन्ना का लंबा इंटरव्यू किया. इसी क्रम में जी न्यूज पर सुमित अवस्थी का लिया इंटरव्यू लोगों ने काफी दिलचस्पी से देखा.

इन दिनों अन्ना रालेगण में अपनी तबियत सुधारने के साथ–साथ देश में जनतंत्र कैसे आए और देश का जनतंत्र आख़िर कहां गायब हो गया, इसके ऊपर एक लंबा लेख लिख रहे हैं. अन्ना ने एक आर्थिक कार्यक्रम तैयार किया है. पहले अन्ना ने एक 24 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था और अब उसे वह 17 बिंदुओं पर ले आए हैं. उन्होंने उस आर्थिक कार्यक्रम को देश के सभी राजनेताओं को भेजा है और उनसे कहा है कि यह देश के लिए आवश्यक है. आप देश की जनता को यह आश्वासन दीजिए कि अगर आप लोकसभा चुनाव जीतते हैं, तो इस आर्थिक कार्यक्रम पर अमल करेंगे. आर्थिक कार्यक्रम में गांव हैं, जल–जंगल–जमीन हैं, बेरोज़गारी है, किसान हैं, उनकी जमीनों से जुड़े मसले हैं, विदेशी कंपनियां हैं और भ्रष्टाचार से जुड़ी मुश्किलें हैं. दरअसल, यह दस्तावेज भारत के बदलाव का दस्तावेज है, भारत को अराजकता से बचाने का दस्तावेज है और भारत में नई राजनीति शुरू करने का दस्तावेज है.

यहां सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दो राजनीतिक दलों को छोड़कर किसी ने भी इस आर्थिक कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी. उनमें पहला नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है. उनकी पार्टी के महासचिव श्री मुकुल राय ने अन्ना को एक पत्र भेजा है कि हम इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और इसके लिए हम लड़ाई लड़ने को वचनबद्ध हैं. दूसरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन कार्यक्रमों का मौखिक समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि अन्ना के संघर्ष का, अन्ना की नीतियों का, अन्ना के कार्यक्रम का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं. इसके अलावा कोई राजनीतिक दल अभी तक आगे नहीं आया है. उत्तर प्रदेश की पीस पार्टी के डॉ. मोहम्मद अयूब ने इस दस्तावेज का सौ प्रतिशत समर्थन किया है और दूसरी तरफ़ राजस्थान के नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने इस दस्तावेज का पूरी तरह समर्थन

किया है. सवाल यह है कि चूंकि पीस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी छोटी पार्टियां हैं, तो क्या उनके अन्ना के आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार करने के पीछे बड़ा बनने की आकांक्षा है या वे अपनी उतनी ही ज़िम्मेदारी महसूस करती हैं, जितनी गैर–ज़िम्मेदारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है. इन दोनों पार्टियों ने तो अन्ना के पत्र का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया.

यद्यपि सारा देश जानता और मानता है कि श्री अन्ना हज़ारे की वजह से संसद में लोकपाल बिल पास हुआ. अगर अन्ना अनशन न करते, तो न यह लोकपाल बिल संसद में आता और न ही पारित होता. कुछ लोग चाहते थे कि अन्ना लोकपाल के इस रूप को न स्वीकार करें, क्योंकि यह उस रूप में नहीं है, जिस रूप में अन्ना ने अगस्त 2011 में देश के सामने रखा था. इस पर अन्ना ने जवाब दिया था कि मैं जहां तक ले आ सकता था, वहां तक ले आया हूं. अब इसके आगे का काम उन्हें करना चाहिए, जिन्हें लगता है कि यह काम अधूरा है या कमजोर है. उन्हें मजबूत लोकपाल लाने के लिए देश में प्रचार करना चाहिए और देश में घूमना चाहिए. देश में कोई तीसरा मोर्चा नहीं बना है. लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट देने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि इन दोनों के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, वे बातें ज़्यादा करती हैं और काम कुछ भी नहीं करतीं. धीरे–धीरे चुनाव सिर पर आ गया और अभी तक इन पार्टियों में औपचारिक बातचीत भी नहीं हुई.

पर एक हलचल दिखाई देती है, जिसे अन्ना के आर्थिक कार्यक्रम ने स्वीकार किया है. अन्ना का आर्थिक कार्यक्रम कई दलों के आपस में मिलने का एक केंद्र बिंदु बनता दिख रहा है. अगर यह केंद्र बिंदु काम कर गया और देश या बाहर के राजनीतिक कार्यकर्ता इसके इर्द–गिर्द इकट्ठा होने लगे, तो एक नए तरह का दबाव उन राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, जो भाजपा और कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं और यही महत्वपूर्ण चीज इस समय देश की हवा में फैल गई है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता इसका जायजा ले रहे हैं कि कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को माना और क्या जो लोग कार्यक्रम मानेंगे, अन्ना उनका समर्थन करने के लिए निकलेंगे. इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है. मेरा मानना है कि खुद अन्ना के पास भी अभी इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब मार्च में मिल जाएगा कि अन्ना का रुख–नज़रिया, जो उनका कार्यक्रम स्वीकार करते हैं राजनीतिक दल के तौर पर, उनकी तरफ़ क्या होगा और जो नहीं स्वीकार करते हैं, उनकी तरफ़ क्या होगा. आम आदमी पार्टी को लेकर भी अन्ना का रुख अप्रैल में साफ़ दिखाई देगा, जब वह प्रेस वालों के सामने उनके आर्थिक कार्यक्रम को मानने वाले लोगों के पक्ष या विपक्ष में राय देंगे.

यह दु:ख की बात कम और हर्ष की बात ज़्यादा है कि अन्ना हज़ारे देश को लेकर अभी भी खामोश नहीं बैठे हैं. वह एक ऐसा जमीनी दस्ता बनाना चाहते हैं, जो देश की समस्याओं के ऊपर किए गए वायदों पर निगरानी रखे या दबाव बनाए. अन्ना को लगता है कि देश की जनता जब तक संसद पर नियंत्रण रखने का सपना नहीं देखेगी, तब तक संसद उसके पक्ष में सोचने की स्थिति में नहीं आएगी और मेरा ख्याल है कि जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति की भावना और अन्ना के समाज परिवर्तन के क़दमों की भावना में अक्षरश: साम्य है. अब देखना यह है कि अन्ना का विश्वास कितने राजनीतिक दलों को हिला–डुला पाता है, कितने लोग तैयार करता है, जो अन्ना के सपने को लेकर लोकसभा में जाएं. और कितने लोगों, जिन्हें यह अपेक्षा है कि अन्ना चुनाव के गुण–दोष को लेकर राजनीतिक दलों के बारे में ज़रूर बोलेंगे, उन सबकी आशाएं कितनी फलीभूत होती हैं और शंकाएं कितनी निर्मूल साबित होती हैं या फिर शंकाएं फलीभूत होती हैं और आकांक्षाएं निर्मूल साबित होती हैं, यह देखने का वक्त है. और शायद अगले पंद्रह से बीस दिनों में स्थितियां साफ़ होनी शुरू हो जाएंगी.■

editor@chauthiduniya.com



मेघनाद देसाई

**मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए आख़िर कितनी सीटों की ज़रूरत होगी? ऐसा माना जा रहा है कि ये सीटें वही 60 शहरी सीटें होंगी, जो कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती थीं. इन सीटों पर भाजपा उम्मीद कर रही है कि वह 45 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी. अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उनमें लगता है कि आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और बाकी सीटें भाजपा को मिलेंगी, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को अतिरिक्त 30 सीटें जीतनी पड़ेंगी, जिससे भाजपा अपने 230 के जादुई आंकड़े को छू पाने में नाकामयाब हो जाए.**

# कांग्रेस की आख़िरी प्रार्थना

महाभारत में भीष्म पितामह का धनुष नीचे रखवा देने के लिए अर्जुन के पास सिर्फ़ एक ही विकल्प था कि वह शिखंडी के पीछे छिप जाते, जो कि एक महिला थी. उपमाएं कभी भी एकदम सटीक नहीं होती हैं. जैसा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के बारे में सोचती है कि वह दुर्योधन हैं या भीष्म? जबकि भीष्म एक ऐसा पद है, जिसे आडवाणी भाजपा में अपना मानते हैं. लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आने वाले चुनाव में महाभारत की तरह लक्ष्य एक ही होगा, दिल्ली का सिंहासन हासिल करना. कांग्रेस ने तो जीत की उम्मीदें छोड़ दी हैं. अब उसका निशाना कोई और नहीं, सिर्फ़ नरेंद्र मोदी रह गए हैं. जहां तक कांग्रेस की बात है, तो उसका मानना है कि भाजपा की जीत का तो स्वागत है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सीटें न जीतने दी जाएं. पार्टी सिर्फ़ इस बात की प्रार्थना कर रही है कि भाजपा 170 से ज़्यादा सीटें न जीतने पाए. ऐसी अवस्था में भाजपा को बहुत सारे सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी और कांग्रेस का ऐसा मानना है कि उस अवस्था में मोदी बहुत पार्टियों को आकर्षित कर पाने में नाकाम रहेंगे और भाजपा का ही कोई दूसरा अधिक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति उनकी जगह ले लेगा. इसमें सबसे ज़्यादा योग्य आडवाणी ही हैं, जिन्हें शायद बाबरी मस्जिद ध्वंस के लिए भुला दिया जाएगा, क्योंकि 2002 के दंगे उससे ज़्यादा भयावह थे.

यह कांग्रेस का एक सपना है, लेकिन यह सपना सच्चाई में तब्दील होगा कैसे? राहुल गांधी का अभिषेक करने से वास्तविकता में कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बीते चुनावों में इसका कोई विशेष फायदा नहीं दिखा. इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी है कि राहुल गांधी लहर को फिर से शुरू किया जाए. चुनावी विशेषज्ञ इन बातों का विश्लेषण करने में लगे हुए हैं कि यह शायद 1977 और 1998 के लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के लिए अभी तक का सबसे खराब चुनाव साबित हो सकता है.



अगर कांग्रेस के भाग्य ने साथ दिया, तभी वह तीन अंकों के आंकड़े को छू पाएगी, अन्यथा 80 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी. कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की तुलना में ज़्यादा सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी, अगर उसे मोदी के अलावा किसी भी अन्य को प्रधानमंत्री बनाना है तो. यही कारण है कि कांग्रेस लालू यादव और रामविलास पासवान से व्यग्रता के साथ गठजोड़ करने में लगी हुई है. उसे इस बात की आशा है कि मायावती का भी सहयोग मिल जाएगा और चुनाव के बाद मोदी को रोकने के लिए नीतीश कुमार भी पार्टी के साथ हो सकते हैं. मोदी को रोकने के लिए सभी विरोधी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी.

वहीं अगर चुनावी तैयारी की चर्चा की जाए, तो यह जानकारी मिलेगी कि कांग्रेस के जागने से बहुत पहले ही भाजपा ने कमर कस ली थी और उसे इस बात का पूरा भरोसा भी है कि वह 200–230 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी. उसका ऐसा मानना है कि अगर वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तो गठबंधन बनाने के लिए कई दल तैयार हो जाएंगे और अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी. उसके बाद ही नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा, लेकिन भाजपा के इस तरह से सोचने का तरीका काफी हद तक टूटा है. आम आदमी पार्टी के आने से उन लोगों में भी खुशी है, जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सभी लोग आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं. उनकी शिकायत है कि आम आदमी पार्टी काफी हो–हल्ला मचाती है, जनमत संग्रहों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, उसका नेतृत्व तानाशाही रवैया अपनाता है और इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे हैं. लेकिन, एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी अकेला ऐसा हथियार है, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है. इस वजह से सीटों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. इस लिहाज से यह देखा जा रहा है कि जहां कांग्रेस की सीटें कम होने की उम्मीद है, वहीं आम आदमी पार्टी को ऐसी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है, जो अधिक से अधिक सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को आगामी 15 अगस्त को लालकिले पर भाषण देने से रोक सकती है, यानी उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती है.

मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए आख़िर कितनी सीटों की ज़रूरत होगी? ऐसा माना जा रहा है कि ये सीटें वही 60 शहरी सीटें होंगी, जो कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती थीं. इन सीटों पर भाजपा उम्मीद कर रही है कि वह 45 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी. अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उनमें लगता है कि आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और बाकी सीटें भाजपा को मिलेंगी, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को अतिरिक्त 30 सीटें जीतनी पड़ेंगी, जिससे भाजपा अपने 230 के जादुई आंकड़े को छू पाने में नाकामयाब हो जाए. यह संभव हो पाने की कितनी संभावनाएं हैं, चलिए इसका एक जायजा लिया जाए.

विचार कीजिए कि अगर कांग्रेस की 80 सीटों से ज़्यादा 100 सीटें जीतकर आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, तो दोनों ही पार्टियों के पास वाइल्ड कार्ड एंट्री की संभावनाएं बन सकती हैं. ऐसी अवस्था में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी और उसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा. ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास यह संभावना रहेगी कि वे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दें. तब शायद जयललिता अपनी 35 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बन जाएं या लालकृष्ण आडवाणी धर्मनिरपेक्षतावादियों में अधिक खुशी की लहर पैदा कर सकें. ऐसी अवस्था में मोदी को मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए, जो उन्हें यह बता सकेंगे कि यह प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है, जिसके पास सारे अधिकार होते हैं. नरेंद्र मोदी गठबंधन के नेता बन सकते हैं और शायद यही वह जगह है, जहां असली शक्ति निहित है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूचना का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

# आरटीआई की दूसरी अपील

चौथी दुनिया ब्यूरो

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी सूचना की अभिगम्यता प्रदान करने से मना किया गया हो, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष अपील/ शिकायत दायर कर सकते हैं.

**दूसरी अपील कब दर्ज करें**

19 (1) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) अथवा धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट समय के अंदर निर्णय प्राप्त नहीं होता है अथवा वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से पीड़ित है. वह उक्त अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर अथवा निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उस अधिकारी के पास एक अपील दर्ज करा सकता है, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का है. मामला चाहे जैसा भी हो:

बशर्ते, उक्त अधिकारी 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर लेता है. यदि वह इसके प्रति संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील करने से रोकने का पर्याप्त कारण है.

19 (2): जब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष की सूचना का प्रकटन किया जाता है, तब संबंधित तीसरा पक्ष आदेश की तिथि के 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है.

19 (3) उपधारा 1 के तहत निर्णय के विरुद्ध एक दूसरी अपील तिथि के 90 दिनों के अंदर की जाएगी, जब निर्णय किया गया है अथवा इसे केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है:

बशर्ते, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह इसके प्रति संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण हैं.

19 (4): यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा कि मामला हो, दिया जाता है और इसके विरुद्ध तीसरे पक्ष की सूचना से संबंधित एक अपील की जाती है तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तीसरे पक्ष को सुनने का एक पर्याप्त अवसर देगा.

19 (7): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, मानने के लिए बाध्य होगा.

19 (8): अपने निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित का अधिकार होगा.

(क) लोक प्राधिकरण द्वारा वे क़दम उठाए जाएं, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ पालन को सुनिश्चित करें, जिसमें शामिल हैं.

• सूचना तक पहुंच प्रदान करने द्वारा, एक विशेष रूप में, यदि ऐसा अनुरोध किया गया है.

• केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति द्वारा,

• सूचना की कुछ श्रेणियों या किसी विशिष्ट सूचना के प्रकाशन द्वारा.

• अभिलेखों के रख-रखाव, प्रबंधन और विनाश के संदर्भ में प्रथाओं में अनिवार्य बदलावों द्वारा.

• अपने अधिकारियों को सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान बढ़ाकर.

• धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) का पालन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रदान करना;

(ख) लोक प्राधिकरण द्वारा किसी क्षति या अन्य उठाई गई हानि के लिए शिकायतकर्ता को मुआवज़ा देना.

(ग) अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों को अधिरोपित करना.

(घ) आवेदन अस्वीकार करना.

**केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा कि मामला हो, दिया जाता है और इसकेविरुद्ध तीसरे पक्ष की सूचना से संबंधित एक अपील की जाती है तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तीसरे पक्ष को सुनने का एक पर्याप्त अवसर देगा.**

19 (9): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील के अधिकार सहित अपने निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को देगा.

19 (10): केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उक्त प्रक्रिया में निर्धारित विधि द्वारा अपील का निर्णय देगा. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301, ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

# राशिफल

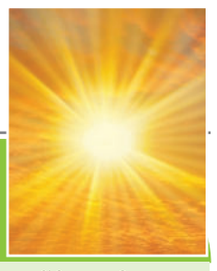

**मेष** — 21 मार्च से 20 अप्रैल

आपकी योग्यता में बढ़ोत्तरी होगी और आप मांगलिक कार्यों में भाग लेंगे. अपनी बात मजबूती के साथ रखें. इस सप्ताह आप कोई नया वाहन या गृहस्थी से जुड़ी वस्तु ख़रीदने की योजना बनाएंगे. आर्थिक दृष्टि से आप संतुष्ट रहेंगे. नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए समय प्रतिकूल रहेगा. बेहतर होगा अपने अधिकारियों से व्यवहार अच्छा रखें.

**वृष** — 21 अप्रैल से 20 मई

आप अपनी सामान्य ज़रूरतों पर ध्यान दें. आप लोगों के उनके स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करें. आकस्मिक लाभ मिल सकता है. इस सप्ताह धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी रूचि कम रहेगी. परिजनों के सहयोग से कार्य बनेंगे. नौकरीपेशा वालों के लिए समय अच्छा है. पूर्व में किए गए आपके किसी कार्य लिए पुरस्कार भी मिल सकता है.

**मिथुन** — 21 मई से 20 जून

अगर आप कहीं बेहतर विकल्प के साथ स्थानांतरित होने के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी मित्र से आपको मदद मिलेगी. ऋण लेने से पहले विचार अवश्य करें. इस सप्ताह दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे. तनाव से बचें नहीं, तो आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा.

**कर्क** — 21 जून से 20 जुलाई

किसी मसले पर अपनी राय रखने से पहले, उसके विषय में जानने की कोशिश करें, तभी अपनी राय दें. आपके दैनिक ख़र्चों में वृद्धि होगी, इसलिए आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लें. संपत्ति ख़रीदने के लिए समय उचित नहीं है. अतः ज़ल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय न लें. इस सप्ताह सफलता मिलने में देरी हो सकती है.

**सिंह** — 21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह आपको संयम बरतने की ज़रूरत है. मित्रों की सहायता से आपका कार्य सफल होगा. इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आप चिंतित रहेंगे. आर्थिक मामलों में आपको फ़ायदा होगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. व्यवसायी फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन नौकरीपेशा लोग परेशान रहेंगे.

**कन्या** — 21 अगस्त से 20 सितंबर

आपकी सकारात्मक सोच के आगे नकारात्मक सोच नहीं टिक पाएंगे. सीधे दौड़ने से पहले आप चलना सीखें. आप धन कमाने के तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और उसमें आप सफल भी होंगे. किसी कार्य के संपन्न होने से आपको फ़ायदा होगा. क़ानूनी दस्तावेज़ पर सोच-विचार कर ही दस्तख़त करें. इस सप्ताह पैतृक संपत्ति से जुड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.

**तुला** — 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

निवेश करने से पहले यह विचार करें कि यह आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा. समय का सदुपयोग करें. इस सप्ताह शत्रु हावी रहेंगे, लेकिन परेशान न हों. अत्यधिक कार्यों की वजह से आप थकान का अनुभव करेंगे. नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए यह सप्ताह विशेष फलदायी रहेगा.

**वृश्चिक** — 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

आप इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. पारिवारिक मेल-मिलाप होगा और आप खुशी का अनुभव करेंगे. सामाजिक कार्यों के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. इस सप्ताह दांपत्य और संतान सुख में वृद्धि होगी.

**धनु** — 21 नवंबर से 20 दिसंबर

अपने ऊपर विश्वास रखें. किसी को भी इतनी छूट ना दें कि वह आपके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करे. अनावश्यक ख़र्च से बचें. संपत्ति ख़रीदने के लिए भी यह समय उचित है. ज़ल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. सफलता मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए विचलित न हों. दांपत्य जीवन में तनाव से बचें.

**मकर** — 21 दिसंबर से 20 जनवरी

दांपत्य जीवन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. आपकी नए लोगों से पहचान बढ़ेगी. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ेगी और आप चिंतित रहेंगे. इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है, आपको फायदा होगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. व्यापारियों को उनके कार्य में उन्नति मिलेगी.

**कुंभ** — 21 जनवरी से 20 फरवरी

आपका निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा. इसलिए आप एक नए सिरे से कार्य आरंभ करें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. इस सप्ताह शत्रु परास्त होंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. व्यापारियों को कारोबारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

**मीन** — 21 फरवरी से 20 मार्च

आपसे अच्छे स्वभाव के कारण नए संपर्क बनेंगे. घर-परिवार में समय दें. इस सप्ताह आपकी प्रगति के राह खुलेंगे. धनागम के अवसर पैदा होंगे. इस सप्ताह स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

# सोशल मीडिया विंडो

## लाइक इट

राखी सावंत- हां, मैं आइटम गर्ल हूं, अपनी मेहनत के दम पर नाम कमाया है , जगह बनाई है, मैं केजरीवाल कि तरह दिल्ली की जनता को मूर्ख नहीं बनाती , झूठे वादे नहीं करती, मुख्यमंत्री होती तो काम करती, सड़क पर धरना देकर समय नहीं बर्बाद करती, महिलाओं की कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करती, अपनी पार्टी के लोगों को समझा कर रखती कि बड़ी मुश्किल से जीतकर आए हैं, संभल कर रहो. मोदी जी के लिए कहा- मोदी जी की मैं बहुत इज्जत करती हूं, शेर है वो, दहाड़ कर रहते हैं.

दिव्या श्रीवास्तव

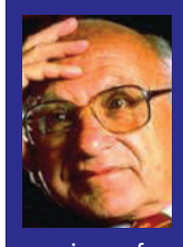
संजय गर्ग

सावधान !!!!
चुनावी आंकलन करने में जो चैनल कांग्रेस को पिछड़ता और केजरीवाल की पार्टी को बढ़ता हुआ बता रहे हैं, वे निश्चित रूप से कांग्रेस से पोषित हैं !!!! यह कांग्रेस की ही एक रणनीति के तहत हो रहा है ... वो इसलिए ताकि लोगों को लगे कि उनका आंकलन भेदभाव रहित है और पूर्वाग्रह से मुक्त है .

## कार्टून क्लास

*कार्टूनिस्ट* सागर की फेसबुक वॉल से साभार

## स्वीट-ट्वीट

राजनीति सिर्फ़ दूसरों को ग़लत ठहरा देना भर नहीं होती, ख़ुद को सही भी साबित करना होता है

उमाशंकर सिंह

शेखर कपूर

हम संसद में प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वे हमारा एजेंडा रख सकें लेकिन अगर वे अपना एजेंडा रखने लगें तो अगले पांच साल का इंतजार कीजिए .

## गॉसिप गैलरी

रेल भवन से धरना हटते ही बन्दरों ने मेरे घर के सामने धरना दे दिया लेकिन ये मैं हूं आम आदमी वाले बन्दर नहीं. वास्तविक बन्दर कह रहे थे, ये आमआदमी, हमारी संतानें हैं. हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमने इन्हें कई हजार वर्ष पहले अपनी जाति से बेदखल कर दिया था. हमारा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है. अत: इन्हें बन्दर कह कर हमें लज्जित न किया जाए. मैंने क्षमा याचना की और सार्वजनिक घोषणा का आश्वासन दिया कि अब (आप के) आम आदमी, लोगों को बन्दर नहीं कहूँगा... तब कहीं जाकर बन्दर शांत हुए और लोकसभा चुनाव में विजय का आशीर्वाद प्रदान किया.

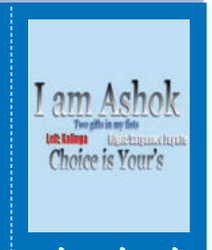

अशोक सत्यमेव जयते

मधुकर वर्मा

सुना है कि एक गिरगिट ने ख़ुदकुशी कर ली. सुसाइड नोट में लिखा था कि वो गहरे अवसाद में था क्योंकि रंग बदलने में वह केजरीवाल का मुक़ाबला नहीं कर पा रहा था.

## एडवर्ड स्नोडेन

अमेरिका के गोपनीय निगरानी कार्यक्रमों का खुलासा कर सनसनी मचाने के कारण एडवर्ड स्नोडेन का नाम सुर्खियों में आया. 30 वर्षीय स्नोडेन ने अमेरिका की दादागिरी की परवाह किए बिना, उसके कारनामों को दुनिया के सामने लाया. अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के लिए तकनीकी सहायक के रूप में कार्य कर चुके स्नोडेन ने खुलासा किया था कि किस तरह आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अमेरिका लोगों की निजता के अधिकार का हनन कर रहा है. स्नोडेन ने अमेरिका के दो कार्यक्रमों के बारे में बताया कि किस तरह से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए अपने एक प्रोजेक्ट के द्वारा लाखों-करोड़ों फोन कॉल के ब्यौरे जमा करता है. उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिये अमेरिका एक विशाल डाटाबेस तैयार कर रहा है. अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए अपने इस प्रोजेक्ट के तहत यह पता लगाने की कोशिश करता है कि संदिग्ध आतंकवादी अमेरिका में किन लोगों के संपर्क में हैं. एनएसए के दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है प्रिज्म. इसमें एनएसए और एफबीआई इंटरनेट कंपनियों के सभी प्रकार के इंटरनेट इस्तेमाल पर नजर रखती है. इनमें ऑडियो, वीडियो, तस्वीरें और ईमेल के सर्च भी शामिल हैं. इसका मकसद देश के बाहर शुरू हुई संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता लगाना है. स्नोडेन ने इन प्रोजेक्ट्स या कार्यक्रमों को असुरक्षित बताया है. औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद एडवर्ड स्नोडेन के पास कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, जिसकी बदौलत वह खुफिया सेवा में काफी आगे बढ़ गया. एडवर्ड स्नोडेन के इस खुलासे से अमेरिका का असली चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है. अमेरिकी गुप्त दस्तावेज़ चुराने के आरोपों के बाद स्नोडेन कुछ दिन तक हांगकांग में रहा और इसके बाद रूस ने उसे शरण दी. अमेरिका चाहता है कि रूस स्नोडेन को उसे सौंप दे, जिससे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके. स्नोडेन कहता है कि वह अमेरिका कभी नहीं लौटना चाहता, क्योंकि उसे अमेरिका में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा नहीं है.

# अमेरिका की दादागिरी चलती रहेगी

**कल तक दुनिया को यह पता था कि वे अमेरिका द्वारा साइबर हमले के विरोध में अपनी बात उस तक पहुंचाने में सफल हो गए हैं, लेकिन वे ग़लत थे, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कह कर सनसनी फैला दिया है कि उनका देश विश्व के अन्य देशों की जासूसी करता रहेगा. अमेरिका की इस दादागिरी से आने वाले दिनों में पूरे विश्व में अगर साइबर वार छिड़ जाए, तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता.**

राजीव रंजन

एक तो चोरी, क तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, ये जुमला अमेरिका पर हमेशा से ही सही साबित होता आया है. ताज़ा मामला दूसरे देशों की जासूसी का है, जिसका खुलासा एडवर्ड स्नोडेन ने किया था, जब उसने अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे प्रिज्म कार्यक्रम के बारे में दुनिया को बताया था. इस खुलासे के बाद दुनिया के अधिकांश देशों ने अमेरिका का कड़ा विरोध किया था. इसी कार्यक्रम को लेकर पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वह विदेशी सरकारों की जासूसी करता रहेगा और इस कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा. ओबामा के इस कथन से अमेरिका की साइबर दादागिरी का पता चलता है. जर्मनी चासंलर एंजेला मर्केल ने जी 8 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी जासूसी का मुखर विरोध किया था और कहा था कि अमेरिका ने अपनी इस करतूत के कारण पूरे विश्व के देशों का विश्वास खो दिया है. अमेरिका की जासूसी के चलते जर्मनी ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देश भी समय-समय विरोध दर्ज़ कराते रहे हैं, लेकिन ओबामा ने उनके विरोध को दरकिनार कर जिस तरह से अपना फरमान सुनाया है, वह आने वाले दिनों में विश्व के देशों को एक बार फिर अमेरिका की मनमानी पर सोचने के लिए बाध्य कर देता है. सबसे बड़ी बात यह है कि ओबामा ने जर्मनी जैसे देशों को अमेरिका के सर्विलांस प्रोग्राम से परेशान न होने का आश्वासन दिया है, जिससे उसकी दोहरी नीतियों का भी पता चलता है. अमेरिका के इस कदम पर कई सवाल उठने लगे हैं. पहला सवाल यह कि अमेरिका की मंशा क्या है? अधिकारों की बात करने वाला अमेरिका दूसरे के घरों में क्यों झांकना चाहता है? क्या लोकतंत्र की पैरवी करने वाले अमेरिका ने दूसरे देशों की संप्रभुता को ताक पर रख दिया है? वह दूसरे देशों की जासूसी कर आखिर अपना कौन सा मक़सद पूरा करना चाहता है? क्या अमेरिका साइबर वार की तैयारी में है?

ओबामा ने प्रिज्म कार्यक्रम को जायज ठहराते हुए दलील दी है कि यह अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है. ग़ौरतलब है कि अमेरिका द्वारा जर्मनी और कुछ अन्य क़रीबी देशों की जासूसी कराए जाने से जुड़े एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे के बाद यूएस के अपने क़रीबियों से रिश्ते तल्ख़ हो चले थे. ओबामा ने अपने सफाई में कहा है कि दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों की तरह ही अमेरिका की भी जासूसी एजेंसी है और वह इन एजेंसियों के प्रयोग के लिए स्वतंत्र है. यहां सवाल यह है कि कोई भी देश अपनी जासूसी एजेंसी के प्रयोग के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्या किसी देश को अपनी जासूसी एजेंसी के बहाने दूसरे देशों की जासूसी करने का हक़ मिल जाता है? जब विश्व के अन्य देश अमेरिका की जासूसी नहीं करते तो अमेरिका उनकी जासूसी क्यों कर रहा है? जूलियन असांजे के आरोपों से तो यही बात सामने आ रही है कि विश्व के देशों का अमेरिका ही जासूसी कर रहा है. दूसरा सवाल यह है कि जब अमेरिका दूसरे देशों की जासूसी कर रहा है तो उसे जायज ठहराता है, लेकिन जब अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी के पूर्व एजेंट एडवर्ड स्नोडेन उसके जासूसी प्रकरण की पोल खोलकर दुनिया के सामने रख देता है, तो अमेरिका को यह नागवार गुजरता है और वह स्नोडेन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ठान लेता है.

### ऑपरेशन प्रिज्म

ऑपरेशन प्रिज्म अमेरिकी खुफिया एजेंसी एनएसए द्वारा शुरू किया गया खुफिया प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों से संबंधित खुफिया जानकारी हासिल करना है. अपने इसी उद्देश्य के तहत अमेरिका के एनएसए ने विभिन्न देशों के लाखों घरेलू फोन उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड हासिल किया. बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के इन करतूतों के खुलासे के बावजूद ओबामा प्रशासन ने इसे उचित ठहराया है. ओबामा का कहना है कि आप सौ फ़ीसद सुरक्षा और सौ फ़ीसद गोपनीयता को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं. दूसरी चिंता इस बात की है कि अमेरिकी कंपनियां भी अपने देश की सरकार को इस काम में पूरा सहयोग दे रही हैं. ऐसा वे अपने आर्थिक लाभ के लिए कर रही हैं. हालांकि, वे कंपनियां इस बात का खंडन करती हैं और कहती हैं कि वे क़ानून के दायरे में रहकर ही इस तरह के आंकड़ों को सरकारों के साथ साझा करती हैं. हैरत की बात तो यह है कि गूगल जैसी कंपनी को एनएसए के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है. जिस तरह से उसने इस खुफिया प्रिज्म प्रोजेक्ट पर प्रतिक्रिया दी है, उससे तो कम से कम यही लगता है. गूगल पर यह आरोप है कि उसने अपने सर्वरों की जानकारी सरकारी एजेंसियों को पिछले दरवाजे से मुहैया कराई है. गूगल, माइक्रोसॉफ़्ट और याहू जैसी अमेरिकी कंपनिया कहती हैं कि अमेरिकी सरकार की ओर से इकट्ठा की गई जानकारी को रोकने के लिए वे उचित कदम उठा रही हैं. हालांकि उनका यह कदम संदेह से परे नहीं कहा जा सकता.

अमेरिका हर दिन लगभग 22 करोड़ एसएमएस की जासूसी करता है. विभिन्न देशों द्वारा विरोध के बावजूद भी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) हर दिन पूरी दुनिया से संदेशों की जासूसी कर अपने यहां सूचनाएं एकत्र कर रही हैं. इसके अलावा लोगों की यात्रा, आपसी संपर्क तथा क्रेडिट कार्डों के आधार पर की गई लेन-देन की भी जानकारी एजेंसी एकत्र कर रही है. अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी 2007 से ही दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क से ईमेल और अन्य सूचनाओं की खुफिया जासूसी कर रही है. इसके लिए उसका डाटा निगरानी तंत्र बाउंडलेस इंफॉर्मेंट सक्रिय है. अमेरिका ने अपने इस निगरानी तंत्र के ज़रिये इस वर्ष मार्च में विश्व भर के कंप्यूटर नेटवर्क से 97 अरब सूचनाएं एकत्रित किया है. अमेरिका ने लगभग 14 अरब सूचनाएं अपने कट्टर दुश्मन ईरान से जुटाई. अमेरिका की यह जासूसी सिद्ध करता है कि वह किसी भी देश की जासूसी अपने सुरक्षा के लिए नहीं करता, जैसा कि वह कहता रहता है, बल्कि वह इन देशों की जासूसी इस आधार पर करता है कि उसका उस देश से किस हद तक अच्छे या बुरे संबंध हैं. अमेरिका ने पाकिस्तान से करीब 13.5 अरब जानकारियां एकत्रित कीं. अमेरिका द्वारा जानकारियां जुटाने के मामले में भारत पांचवें स्थान पर है. इंफॉर्मेंट ने भारत से क़रीब 6.3 अरब सूचनाएं जुटाई हैं. अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए फेसबुक, गूगल, याहू इत्यादि से जुड़े दूसरे देशों के उपभोक्ताओं की भी जानकारी जमा करती रही है. हालांकि गूगल, एप्पल और अन्य कंपनियों ने दावा किया है कि वे अपने उपभोक्ताओं के आंकड़ों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं और वे इन जानकारियों को किसी भी सरकार या एजेंसी के साथ साझा नहीं करते हैं. एनएसए ने उन अमेरिकी नागरिकों की जानकारियों पर भी नज़रें रखीं, जो दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के संपर्क में थे. अमेरिका द्वारा की जा रही जासूसी के बारे में गोपनीय दस्तावेज़ों से पता चलता है कि एनएसए की ओर से कनाडा की एक एजेंसी ने लगभग 21 देशों की जासूसी की. कहा तो यहां तक जाता है कि अमेरिका के इस कार्यक्रम में ब्रिटेन की सरकार भी साथ है.

अभी हाल ही में अमेरिकी जासूसी से जर्मनी काफी परेशान हुआ था. जब यह बात सामने आई कि एनएसए ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के फोन की जासूसी की थी तो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध ख़राब हो गए थे. हालांकि अमेरिका अपने क़रीबी देशों को इस जासूसी प्रकरण से अलग रखने के लिए आश्वासन देता है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं करता, ताकि उक्त देश के साथ वह अपने व्यापारिक और सामरिक संबंधों को मजबूती प्रदान कर सके. ऐसा ओबामा के हाल ही में दिए गए उस कथन से स्पष्ट होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जर्मनी को अमेरिकी जासूसी की तरफ से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देश भी अमेरिकी जासूसी से परेशान हैं. ब्राजील का भी आरोप है कि ई-मेल और टेलीफोन कॉल्स की जानकारी के लिए एनएसए ने ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध डाली थी.

### जूलियन असांजे

जूलियन पॉल असांजे विकीलीक्स के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं. विकीलीक्स की स्थापना से पहले वे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर थे. विकीलीक्स पर उसके किए गए कार्यों के लिए 2008 में उन्हें इकॉनोमिस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवॉर्ड और 2010 में सेम एडम्स अवॉर्ड प्रदान किया गया. उन्होंने इराक युद्ध से जुड़े लगभग चार लाख दस्तावेज़ अपनी वेबसाइट पर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड एवं नाटो की सेनाओं के गंभीर युद्ध अपराध के प्रमाण मौजूद हैं. इन प्रमाणों को ख़ारिज करना नामुमकिन था, क्योंकि इसके अपने आधार थे. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसके ख़िलाफ़ उन्हें चेतावनी दी, जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से उसे छिप-छिप कर जीवन बिताना पड़ा. 30 नवंबर, 2010 को अंतरराष्ट्रीय लोक अभियोजन अधिकारी ने असांजे के ख़िलाफ़ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया. उसके ख़िलाफ़ यौन अपराधों का मुक़दमा दर्ज़ किया गया और 7 दिसंबर, 2010 को असांजे को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया.

## भारत का सख्त रुख

अमेरिका द्वारा जासूसी मसले पर भारत ने अपने सख्त रुख़ से अमेरिका को अवगत कराया है. भारत हैरान है कि अच्छे संबंधों के बावजूद अमेरिका उसके कंप्यूटर नेटवर्क की खुफिया निगरानी करा रहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय का मानना है कि साइबर जासूसी को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है. ऐसा करके अमेरिका भारत के निजता क़ानूनों का उल्लंघन कर रहा है, जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र को स्वीकार्य नहीं होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

बाबा के समाधिस्थ होने के सात दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी. मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था. उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था. वह किसी अज्ञात पीड़ा और दर्द से दु:खी था. उसके पालक तीन दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते थे.

एक बार...

# साई तेरा नाम बड़ा सुखदायी

चौथी दुनिया ब्यूरो

सद्गुरु साई बाबा धन्य हैं. हम सब साई बाबा को नमन करते हैं. साई विश्व को सुख पहुंचाते और भक्तों का कल्याण करते हैं. साई उदार हृदय हैं. जो भक्तगण साई के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, साई उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार करते हैं. साई बाबा, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूं, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं. यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन–पूजन करें, तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी. आज निंदित विचारों के तट पर मायामोह के कारण धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं. अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहंभाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्पों–विकल्पों की भंवर में निंदा, घृणा एवं ईर्ष्या रूपी मछलियां तैर रही हैं. यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है, तो भी हमारे सद्गुरु साई महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं. इसलिए साई के भक्तों को किंचित मात्र भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वह हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भव–समुद्र से पार उतार देंगे.

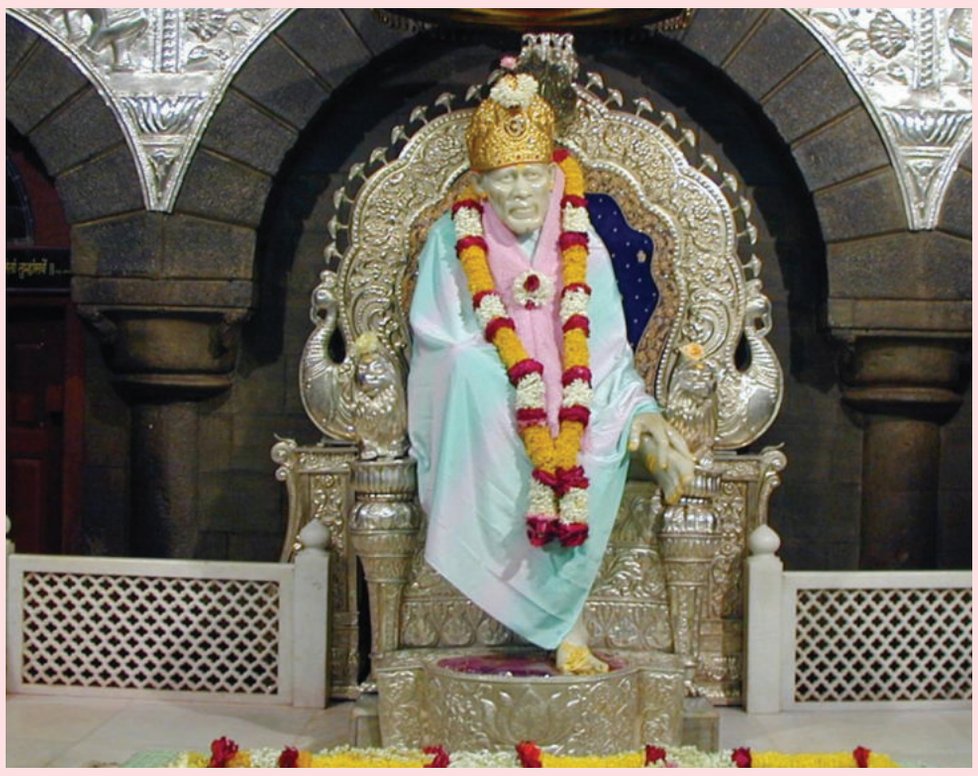

**इस संसार में वस्तुत: कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है. हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे. पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है. यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा एवं उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक का प्रयोग तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे.**

ऐसी ही एक कथा बारे में बताता हूं. बाबा के समाधिस्थ होने के सात दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी. मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था. उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था. वह किसी अज्ञात पीड़ा और दर्द से दु:खी था. उसके पालक तीन दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते थे. यही उनके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था. उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हुआ. कहीं से बाबा की कीर्ति भी उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साई दरबार में आए. हाथों से जंजीरें पकड़ कर उन्होंने बाघ को मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया. वह स्वभावत: ही भयानक था, लेकिन दर्द के कारण वह बेचैन था. लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे. दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए. जैसे ही बाघ सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी. जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई, तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेमपूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा. उसने अपनी पूंछ हिलाकर तीन बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए. उसे मृत देखकर दरवेश बड़े निराश एवं दु:खी हुए. तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ, तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट थी. चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सरीखे महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई. वह दरवेशियों का ऋणी था और जब वह मर गया, तो स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साई चरणों में सद्गति मिली. जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे, तो उसकी मुक्ति हो जाती है.

एक और कथा. यह सर्वविदित है कि साई बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे और उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता, उससे वह ईधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्जवलित रखते थे. इसी धूनी की भस्म ही उदी कहलाती है. भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्तहस्त से उन्हें वितरित कर दी जाती है. इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि अंगारे की तरह गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है. हमारा तन भी ईधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म में परिवर्तित हो जाएगा. भक्तों को यह याद दिलाने के लिए बाबा उदी वितरित करते थे कि अंत में यह देह भी भस्म सदृश होने वाली है. बाबा इस उदी द्वारा एक और शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या. इस संसार में वस्तुत: कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है. हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे. पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है. यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा एवं उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक का प्रयोग तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे. उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है. इन दोनों के अभाव में इस मायारूपी भवसागर को पार करना कठिन है, इसलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे. जब भक्तगण विदा लेते, तब वह प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना आशीर्वाद देते थे. जब बाबा प्रसन्नचित्त होते, तब वह प्रेमपूर्वक गीत गाते थे. भजन बाबा शुद्ध एवं मधुर स्वर में गाते थे. यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, लेकिन उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंतामुक्ति और अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए. ■

feedback@chauthiduniya.com

## साई भक्तों!

**आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.**

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

# शरीर और मन मिट्टी का बना है

डॉ. अभय बंग

सर्च अस्पताल में रोगियों की सेवा, एक सौ देहातों में ग्राम–आरोग्य सेवा व रिसर्च, व्यसनमुक्ति, युवक–युवती प्रशिक्षण और बाल मृत्यु घटाने के प्रयोग, ये सारे कार्यक्रम बढ़िया तरीके से चल रहे हैं. झेन पंथ की एक पुरानी कहावत है, साक्षात्कार से पहले मैं लकड़ी काटता था, पानी भरता था. साक्षात्कार के बाद भी मैं लकड़ी काटता हूं, पानी भरता हूं. मैं तो साक्षात्कार से बहुत दूर हूं. पहले का ही काम करता हूं, लेकिन भीतरी समझ व भाव में कुछ बदलाव हुआ है. छोटी–छोटी सांसारिक बातों में उलझना कम हो गया है. कभी–कभी गुस्सा आता है, अपेक्षा भंग भी होती है. कई बार अनजाने में मन सपनों में खो जाता है. काम एवं परिणाम के प्रति आसक्ति भी हो जाती है, लेकिन मन में आकांक्षाएं आते ही असंतोष एवं तनाव शुरू हो जाता है, यह बात समझ में आ जाती है. फिर मैं तुरंत स्वयं को संभाल लेता हूं. भार दूर फेंक देता हूं, जिस कारण अब अधिक प्रसन्नता है. सच कहूं, तो गर्व और अट्टहास से की गई उठापटक कितनी व्यर्थ है, यह भी समझ में आने लगा है. जीवन के प्रवाह में सहज रूप से तैरते रहने से हम स्वयं मंजिल पर पहुंच जाते हैं. अट्टहासपूर्वक तैरने और पहुंचने की कोशिश करने से नाक–मुंह में पानी जाता है, लेकिन इस प्रवाह पर दिशा व गति के बोर्ड लगे हुए नहीं हैं. कुछ न करते हुए केवल पानी पर सहज रूप से तरंगित रहने से इस जीवन–प्रवाह का अनुभव होता है. यह सीधा सा प्राथमिक सत्य मेरी समझ में आने लगा.

मृत्यु की चिंता, जीवन का उद्देश्य एवं जीवन कैसे जिया जाए, इस विषय में मेरे संशय समाप्त हो गए, बुद्धि को उत्तर मिल गया, लेकिन इससे उत्तर हाथ में नहीं आ गया. नक्शे पर दिल्ली कहां है, यह समझने एवं प्रत्यक्ष दिल्ली पहुंचने में जो फर्क है, वैसा ही बखूबी समझ में आ गया था कि यह विश्व, इसके पीछे का वैश्विक सत्य एवं मैं–ये सब एक ही हैं, परंतु क्या इससे खुद को अलग समझने की प्रवृत्ति चली गई? बुद्धि के स्तर पर जो समझा है, उसे अनुभूति, वृत्ति एवं आचरण के स्तर पर जीना, यह खूब लंबा सफर है. यह शरीर एवं मन मिट्टी का बना है, इसका बारंबार अनुभव मुझे होता है. बुद्धि हज़ारों मील आगे भागती है, शरीर और मन खूब धीरे–धीरे रेंगते हैं. शरीर और मन की आदतें नहीं बदलतीं, वे बारंबार पुरानी आदतों की ओर चले जाते हैं, लेकिन मन निराश नहीं होता. इस प्रयत्न में, यात्रा में भरपूर आनंद का अनुभव होता है. इस जन्म में शायद इस अंतर को पूरी तरह पार कर पाना संभव भी नहीं. शरीर उतने लंबे समय तक टिकेगा, इसका क्या भरोसा? लेकिन प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण ही यदि गंतव्य हो जाए, तो कहीं और पहुंचने की आवश्यकता क्या है? मैं कछुए की गति से चल रहा हूं. मैं खरगोश नहीं हूं. खरगोश की गति मुझे उपलब्ध नहीं है, होगी भी नहीं. उसका दु:ख भी नहीं. कछुआ चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है.

मेरी यात्रा अभी चल ही रही है. अनेक बार भ्रमित हो जाता हूं. कभी परिस्थितियों के वश, कभी स्वयं के कारण. घानी के बैल जैसा उसी जगह पर चक्कर काट रहा हूं या स्पाइरल (घुमावदार) सीढ़ियों सी प्रत्येक चक्राकार यात्रा के बाद पहले से थोड़ा ऊपर पहुंच रहा हूं, कह नहीं सकता और पुन: पुरानी जगह ही पहुंचूं, तब भी इस बार नया ही अर्थ समझ में आता है. अभी भी मैं सर्वत्र ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता. सारे लोगों से अभी भी पूर्ण प्रेमभाव से एकरूप नहीं हो सकता. मुझे मालूम है कि प्रेम दूसरों से जोड़ता है, बुद्धि उसमें कम पड़ती है. मेरा मैं अभी विसर्जित नहीं हुआ है. समाप्त ही नहीं होता! वह बारंबार बीच–बीच में आकर रुकावट बनता है, लेकिन मैं सतत सुधार कर रहा हूं. रोज स्वयं को बदलने का, बनाने का आनंद ले रहा हूं. जेसी जैक्सन नामक नीग्रो पादरी द्वारा 1984 में कहा गया एक वाक्य मुझे सदा याद रहता है, मित्रो! मेरे दोषों के लिए मुझे क्षमा करो. ईश्वर ने मुझ पर काम करना अभी समाप्त नहीं किया है.

**मेरे हृदय रोग के निदान ने मुझे खूब बेवकूफ बनाया था और इसके विषय में मेरे मन में बहुत विषाद एवं अपराध की भावना थी. एक दिन लान्सेट नामक जगप्रसिद्ध चिकित्सकीय जर्नल का हृदय रोग पर वार्षिक विशेषांक प्रकाशित हुआ. इस अंक के अतिथि संपादक हृदय रोग के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं. उन्होंने लिखा था, गत वर्ष मुझे हार्ट अटैक आया, तब छाती में दर्द होते हुए भी चिकित्सकीय निदान करके मदद लेने में मैंने 72 घंटे की देर कर दी. मेरी इस मूर्खता के कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी.**

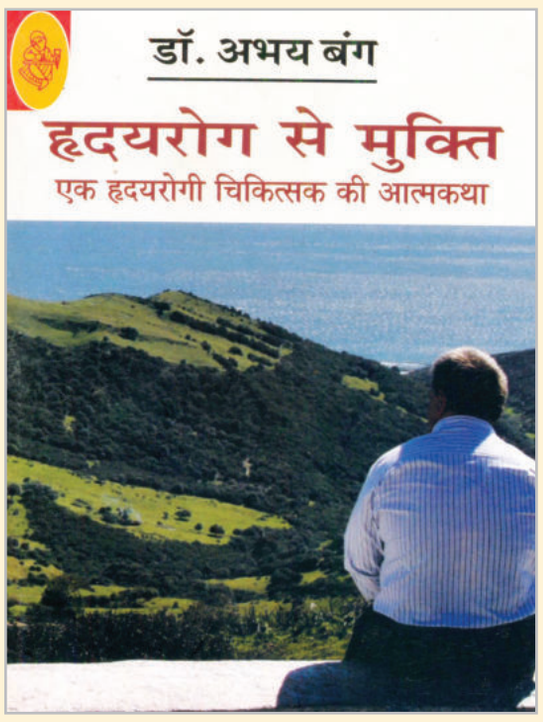


मेरे हृदय रोग के निदान ने मुझे खूब बेवकूफ बनाया था और इसके विषय में मेरे मन में बहुत विषाद एवं अपराध की भावना थी. एक दिन लान्सेट नामक जगप्रसिद्ध चिकित्सकीय जर्नल का हृदय रोग पर वार्षिक विशेषांक प्रकाशित हुआ. इस अंक के अतिथि संपादक हृदय रोग के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं. उन्होंने लिखा था, गत वर्ष मुझे हार्ट अटैक आया, तब छाती में दर्द होते हुए भी चिकित्सकीय निदान करके मदद लेने में मैंने 72 घंटे की देर कर दी. मेरी इस मूर्खता के कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी. अतएव मैंने पिछले कुछ वर्षों में जिन्हें हार्ट अटैक हो चुका है, ऐसे विश्व के दस प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञों से उनके अनुभव पूछे. दर्सों विशेषज्ञों ने स्वयं के चिकित्सकीय निदान में गलती की थी, उसे टाला था एवं इलाज में देरी की थी. विश्वस्तरीय हृदय रोग विशेषज्ञों की ऐसी अजीब संगति पाकर मेरी अपराध भावना एवं शर्मिंदगी कम हुई. स्वयं के स्वास्थ्य के विषय में हम डॉक्टर कई बार गलती करते हैं, मात्र यह बात भलीभांति ध्यान रही. ■

*राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित*

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

## ब्रह्मा जी का थैला

इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने एक बार मनुष्य को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, मैं उन्नति करना चाहता हूं, सुख–शांति चाहता हूं और चाहता हूं कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें. ब्रह्मा जी ने मनुष्य के सामने दो थैले धर दिए और बोले, इन थैलों को ले लो. इनमें से एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराइयां भरी हैं, उसे पीठ पर लाद लो और सदा बंद रखना. न तुम देखना, न दूसरों को दिखाना. दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हैं, उसे सामने लटका लो और बार–बार खोलकर देखा करो. मनुष्य ने दोनों थैले उठा लिए, लेकिन उससे एक भूल हो गई. उसने अपनी बुराइयों का थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसकर बंद कर दिया. अपने पड़ोसी की बुराइयों से भरा थैला उसने सामने लटका लिया. उसका मुंह खोलकर वह उसे देखता रहता और दूसरों को भी दिखाता रहता. इससे उसने जो वरदान मांगे थे, वे भी उलटे हो गए. वह अवनति करने लगा, उसे दु:ख और अशांति की प्राप्ति होने लगी. तुम मनुष्य की वह भूल सुधार लो, तो तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हें सुख–शांति की प्राप्ति होगी और जगत में तुम्हारी प्रशंसा होगी. तुम्हें करना यह है कि अपने पड़ोसियों एवं परिचितों के दोष देखना बंद कर दो और अपने दोषों पर सदा दृष्टि रखो.

***शिक्षा :** दूसरे के दोष देखने के बजाय हमें अपने दोषों को देखना चाहिए.*

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

> जयपुर साहित्य महोत्सव इस मायने में अहम भी है कि इसने भारत में इस तरह के साहित्यिक उत्सवों की एक संस्कृति विकसित की है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की देखादेखी आज देश भर में कई लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होने लगे हैं. हर संस्थान इस तरह का आयोजन करने के लिए लालायित नज़र आ रहा है. अख़बारों ने भी लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने में खासी रुचि दिखाई है. नतीजा यह हुआ है कि इस तरह के आयोजन महानगरों के अलावा सुदूर छोटे शहरों में भी होने लगे हैं. यह एक अच्छी बात है और साहित्य के लिए शुभ संकेत भी.

# साहित्य का मीना बाज़ार

अनंत विजय

जयपुर के दिग्गी पैलेस होटल परिसर में पांच दिनों तक चलने वाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म हो गया .जनवरी की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में राज्यपाल मारग्रेट अल्वा और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने इसकी औपचारिक शुरुआत की थी. सात सालों से हर साल आयोजित होने वाला यह लिटरेचर फेस्टिवल अब साहित्यिक विमर्श के मंच से बहुत आगे जा चुका है. अब यह मेला पूरी तरह से कमर्शियल हो गया है. दिग्गी पैलेस के परिसर में अब एक पूरा मीना बाज़ार सजने लगा है. एक-एक इंच खाली ज़मीन पर तरह-तरह के सामानों की दुकानें खड़ी हो गई हैं. राजस्थानी कपड़ों से लेकर हस्तशिल्प तक और सोने के गहनों से लेकर जूतियों एवं थैलों तक की दुकानें वहां लगने लगी हैं. किताबों की दुकानें कम, अन्य चीजों की दुकानें ज़्यादा हो गई हैं. मैं इस साहित्यिक महफिल को इस वजह से मीना बाज़ार कहता हूं कि वहां वह पूरा माहौल है, जो किसी भी मजमे को मीना बाज़ार बनाने के लिए काफी होता है. चाय और कॉफी के अलग-अलग स्टॉलों के अलावा बर्गर से लेकर लजीज व्यंजन तक अब वहां मौजूद हैं. इन सबसे आयोजकों को अच्छी-खासी आय होती है. हस्तशिल्प और गहने तो विदेशी मेहमानों को ध्यान में रखकर लगाए गए हैं. क़ीमत भी उसी हिसाब से रखी गई है. मुझे याद है कि छह साल पहले जब दिग्गी पैलेस के फ्रंट लॉन में साहित्यिक विमर्श होता था, तो साहित्य के गंभीर श्रोता और साहित्यप्रेमी ही वहां उपस्थित होते थे, न कोई भीड़भाड़, न कोई तामझाम. अब तो कुल्हड़ की चाय का भी व्यवसायीकरण हो गया है. राजस्थानी साफा बांधे कुल्हड़ में चाय पीने के लिए कूपन लेने वालों की लंबी कतार फ्रंट लॉन में लगती है.

साहित्य प्रेमियों के अलावा बच्चे भी अच्छी-खासी संख्या में इस मेले को देखने आते हैं. अब तो हालत यह है कि जिस तरह से किसी भी स्कूल से बच्चों को अप्पूघर ले जाया जाता है, उसी तरह स्कूली बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में इस मीना बाज़ार में घूमने आते हैं. साथ में उनके शिक्षक भी होते हैं, जो उन्हें लाइन लगवा कर मेला दिखाते हैं और फिर बाहर ले जाते हैं. साहित्य प्रेमियों से ज़्यादा भीड़ तमाशा और सेलिब्रिटीज को देखने और उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की होती है. हर बार साहित्यिक सुपरस्टार के साथ-साथ लोकप्रिय फिल्मी कलाकारों को भी यहां बुलाया जाता है, ताकि आम जनता को आकर्षित किया जा सके. मुझे याद है कि पिछली बार जब राहुल द्रविड़ और राजदीप सरदेसाई का सेशन हुआ था, तो फ्रंट लॉन को सेशन शुरू होने के पहले ही बंद कर देना पड़ा था. इतनी भीड़ थी कि सुरक्षाकर्मियों को उसे काबू में करने में दिक्कत हो रही थी. दिग्गी पैलेस के सामने सड़क तक लंबी कतार लगी हुई थी. ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों की भीड़ काबू में करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी थी.

पिछले दो सालों से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विवादों की वजह से चर्चा में रहा है. पिछले साल समाजशास्त्री आशीष नंदी द्वारा पिछड़ों पर दिए गए बयान और आशुतोष के प्रतिवाद ने पूरे देश में एक विवाद खड़ा कर दिया था. आशीष नंदी ने कहा था, इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द करप्ट कमन फ्राम दे ओबीसी ऐंड शेड्यूल कास्ट ऐंड नाऊ इंक्रीजिंगली शेड्यूल ट्राइब्स. आशीष नंदी के उस बयान का उस वक्त पत्रकार रहे और अब आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने जमकर प्रतिवाद किया था. उस विवाद पर हफ्तों तक न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर लंबी बहसें चली थीं. आयोजकों और आशीष नंदी पर मुकदमे भी हुए थे, वारंट जारी हुआ था. बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुलझा, तब तक लिटरेचर फेस्टिवल हर किसी की जुबां पर था. आशीष नंदी के बयान पर उठे विवाद के पहले भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी के जयपुर आने को लेकर अच्छा-खासा विवाद हुआ था. कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने सलमान के जयपुर साहित्य महोत्सव में आने का विरोध किया था. उनकी दलील थी कि सलमान ने अपनी किताब-सैटेनिक वर्सेस में अपमानजनक बातें लिखी हैं, जिनसे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं. उस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, लिहाजा सियासी दलों ने भी इस विवाद को जमकर हवा दी थी. उस विवाद की छाया लंबे समय तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को प्रसिद्धि दिलाती रही थी. चूंकि सलमान रश्दी विवाद के केंद्र में थे, इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में उनको खासी तवज्जो मिली.

> साहित्य प्रेमियों के अलावा बच्चे भी अच्छी-खासी संख्या में इस मेले को देखने आते हैं. अब तो हालत यह है कि जिस तरह से किसी भी स्कूल से बच्चों को अप्पूघर ले जाया जाता है, उसी तरह स्कूली बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में इस मीना बाज़ार में घूमने आते हैं. साथ में उनके शिक्षक भी होते हैं, जो उन्हें लाइन लगवा कर मेला दिखाते हैं और फिर बाहर ले जाते हैं. साहित्य प्रेमियों से ज़्यादा भीड़ तमाशा और सेलिब्रिटीज को देखने और उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की होती है. हर बार साहित्यिक सुपरस्टार के साथ-साथ लोकप्रिय फिल्मी कलाकारों को भी यहां बुलाया जाता है, ताकि आम जनता को आकर्षित किया जा सके.

अब तो हालत यह है कि जयपुर साहित्य महोत्सव इंटरनेशनल लिटरेरी कैलेंडर में अपना एक अहम स्थान बना चुका है. इस बार कोई विवाद नहीं हुआ, इस वजह से चर्चा भी कम हुई. इस बार फ्रीडम जैसा उपन्यास लिखकर दुनिया भर में शोहरत पा चुके अमेरिकी उपन्यासकार जोनाथन फ्रेंजन, झुंपा लाहिरी समेत कई विदेशी लेखक पहुंचे थे. जोनाथन का उपन्यास फ्रीडम खासा चर्चित रहा है और आलोचकों ने उसे वॉर एंड पीस के बाद का सबसे अहम उपन्यास माना है. नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने आम आदमी पार्टी के उभार को भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती के तौर पर पेश किया. उन्होंने आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें भारत में एक ऐसी दक्षिणपंथी पार्टी की अपेक्षा है, जो धर्मनिरपेक्ष हो. इसके पहले अमर्त्य सेन का नरेंद्र मोदी विरोध काफी चर्चा में रह चुका है और अब वह आम आदमी पार्टी के बहाने से एक नया शिगूफा छोड़ गए हैं. वहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नेत्रहीन लेखक वेद मेहता ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर वह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ऐसा भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए ख़तरनाक होगा. उनके मुताबिक, मोदी के विचार हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने वाले होते हैं. 80 वर्षीय मेहता ने अपने विचारों और वक्तव्य से स्पंदन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उनके विचारों में मौजूद पूर्वाग्रह साफ़ झलक रहा था, लिहाजा लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया. साहित्योत्सव में हर बार इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि किसी व्यक्ति विशेष के ख़िलाफ पूर्वाग्रह लेकर विमर्श में वस्तुनिष्ठता कैसे आ सकती है. हिंदी से अशोक वाजपेयी और यतींद्र मिश्र के अलावा भी कई लेखक इसमें शामिल हुए.

जयपुर साहित्य महोत्सव इस मायने में अहम भी है कि इसने भारत में इस तरह के साहित्यिक उत्सवों की एक संस्कृति विकसित की है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की देखादेखी आज देश भर में कई लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होने लगे हैं. हर संस्थान इस तरह का आयोजन करने के लिए लालायित नज़र आ रहा है. अख़बारों ने भी लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित करने में खासी रुचि दिखाई है. नतीजा यह हुआ है कि इस तरह के आयोजन महानगरों के अलावा सुदूर छोटे शहरों में भी होने लगे हैं. यह एक अच्छी बात है और साहित्य के लिए शुभ संकेत भी. इस तरह के आयोजनों और विमर्श से हमारे समाज में एक सांस्कृतिक संस्कार विकसित हो सकता है. इसके लिए यह ज़रूरी है कि इस तरह के उपक्रमों का व्यवसायीकरण न हो, यह पैसा कमाने का उद्यम न बनें. इस तरह के आयोजनों में मंशा ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि अगर मंशा साफ़ है, तो नतीजे बेहतरीन मिलते हैं. ■

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)*

anant.ibn@gmail.com

## कविता

**महेंद्र अवधेश**

लौट पड़े थे मेरे क़दम
एक बार फिर वहीं
जहां है मौजूद तू और तेरा अक्स!
सिर्फ़ इस चाह में कि
कभी न कभी
किसी न किसी पल
टूटेगी तेरी कुंभकर्णी नींद
जागेगी तेरी संवेदना
जो बन गई है पत्थर
बाज़ारवाद के स्पर्श से,
लेकिन ठगा-सा रह
गया उस दिन
यह देखकर कि
तू स्वयं है तत्पर
बनने को बाज़ार का हिस्सा
वह भी संवेदनाओं के
सारे बंधन तोड़कर!
इसलिए-
थके क़दमों से
वापस हो चला हूं
उस मोड़ की तरफ़
जहां से खोज सकूं
एक ऐसा रास्ता
जो तेरे बाज़ार से
होकर तो गुजरे
लेकिन-
जिंदा रखे वह दर्शन
जो है मेरा साथी
मेरा मार्गदर्शक
और जिस पर अवलंबित है
मेरा समूचा अस्तित्व!

mahendra.awdhesh@gmail.com

## किताब मिली

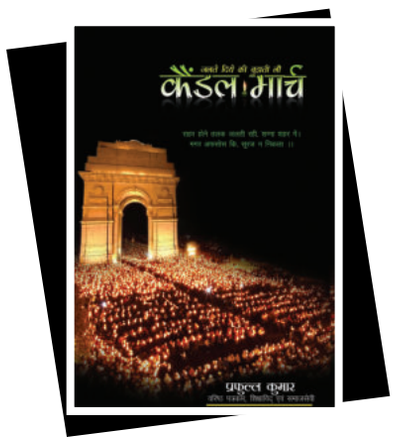


| पुस्तक | लेखक |
|---|---|
| जलते दिये की बुझती लौ कैंडल मार्च | प्रफुल्ल कुमार |
| **प्रकाशक** | **मूल्य** |
| डायमंड बुक्स, दिल्ली | 125 रुपये |

हाल में हुए जनांदोलनों को लेकर लिखी गई यह पुस्तक हमें बताती है कि भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों के लिए सिर्फ़ ऐसा करने वाला ही दोषी नहीं होता है, बल्कि उसमें हम भी कहीं न कहीं शामिल होते हैं, कुसूरवार होते हैं, चाहे ऐसा जानते हुए हो अथवा अनजाने में. वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल कुमार की यह पुस्तक अपने 12 अध्यायों के अंतर्गत कई गंभीर बिंदुओं की न केवल चर्चा करती है, बल्कि हमें उन पर चिंतन-मनन के लिए भी प्रेरित करती है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई-मेल: feedback@chauthiduniya.com

## पुस्तक समीक्षा

# जिज्ञासुओं और ज्ञान-पिपासुओं का अमृत घट

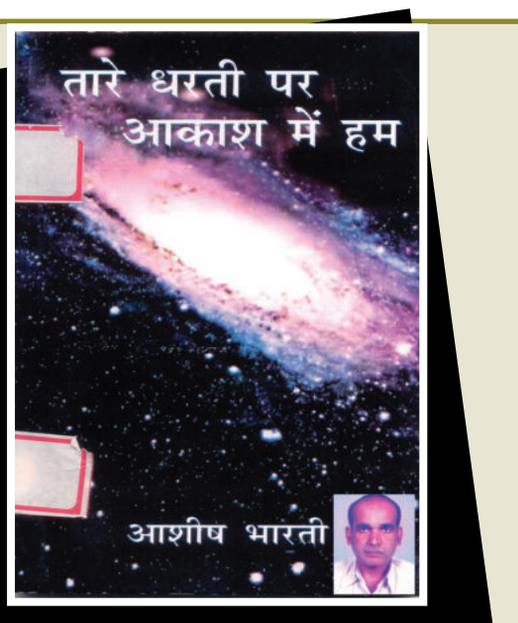


**समीक्ष्य पुस्तक :** तारें धरती पर आकाश में हम
**लेखक :** आशीष भारती
**प्रकाशक :** परा विद्या शोध केंद्र, बिहार.

**डॉ. अनिल सुलभ**

मानव मन आदिकाल से ही अति जिज्ञासु रहा है. मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह केवल भोजन और नर-मादा के बीच नैसर्गिक आकर्षण (मैथुन) तक सीमित नहीं रह सकता था. उसका विकसित मस्तिष्क अपने आसपास की वस्तुओं, पृथ्वी एवं आकाश की घटनाओं, उसके स्वयं के अस्तित्व, जीवन-मृत्यु और गोचर-अगोचर रहस्य को जानने के लिए व्याकुल हुआ. मानव अब अपने और निखिल ब्रह्मांड के समस्त चराचर के सभी पक्षों पर चिंतन करने लगा. चिंतन की दिशा में तब का मानव जितना आगे बढ़ा, उसकी जिज्ञासाएं और बढ़ती गईं.

भारतीय वांगमय में, विशेष रूप से वैदिक साहित्य में, हम मानव-जिज्ञासा का उत्कर्ष पाते हैं. चिंतन तब आत्मा, परमात्मा और जीवन की उत्पत्ति तथा ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज की ओर बढ़ चुका था. आध्यात्मिक चिंतन अब किसी पड़ाव पर पहुंच रहा था. आध्यात्मिक-स्थापनाएं अपना रूप ले रही थीं. मान्यताएं विश्वास का स्थान ग्रहण कर रही थीं. भारतीय मनीषा जब पराकाष्ठा पर पहुंची, तो चारो वेद, उपनिषद एवं 18 पुराण अस्तित्व में आए, जिन्होंने मानव मन की उत्कट जिज्ञासाओं को बहुत सीमा तक तुष्ट करने और गुणवत्तापूर्ण मूल्यवान-जीवन के मार्ग प्रशस्त किए, किंतु आत्मा-परमात्मा, जीवन-मृत्यु, इहलोक-परलोक, धरती-आकाश और निखिल ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर जिज्ञासाएं अब भी समाप्त नहीं हुईं. शायद यह रहस्य-रोमांच का कारण और कारक भविष्य के मानवों के सामने भी इसी तरह चिर नवीन प्रश्न की तरह बना ही रहेगा.

इसी प्रसंग में, जिज्ञासु और साधक-साहित्यसेवी आशीष भारती की सद्य: प्रकाशित कृति-तारे धरती पर आकाश में हम, दर्शन साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान पाने योग्य है. यह अध्यात्म के गूढ़ विषय में चिंतनशील जिज्ञासुओं और ज्ञान-पिपासुओं के लिए अमृत घट की तरह है. लेखक ने निश्चय ही इस पुस्तक के प्रणयन में श्लाघ्य श्रम किया है. लेखक के शोधपरक चिंतन में सांख्य-दर्शन (जिसके प्रतिपादक वरेण्य महर्षि कपिल थे) का सर्वाधिक प्रभाव है. विदित होता है कि लेखक ने इस उत्कृष्ट रचना में आधार तत्व ऋगवेद, महर्षि वामदेव के दर्शन, भागवत गीता एवं अन्य वैदिक साहित्य से भी प्राप्त किया है. लेखक यह मानता है कि अमृत ज्ञान-स्वरूप है. जीवात्मा द्वारा पूर्ण ज्ञान (प्रकृति में उपलब्ध ज्ञान, जिसका एक सिरा स्थूल संसार के रूप में काल-क्रमानुसार प्रकाशित होता है, कार्यक्रम परंपरा के रूप में, और एक कारण ब्रह्म भावरूप भवसागर, जिसमें कालचक्र की पूरी गति दर्ज है) को जानने के बाद ही संभव हो पाता है, जो आत्मा के पूर्ण ज्योतिर्मय स्वरूप को दर्शाते हुए मोक्ष प्राप्ति तक ले जाता है.

चिंतन और प्रतिपादन की दृष्टि से पुस्तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ दिखाई देती है. निश्चय ही प्रबुद्ध पाठक इससे लाभांवित होंगे. अध्यात्म के निगूढ़ तत्व को समझने में इससे पर्याप्त सहायता मिलेगी, किंतु यह विषय मानस-मंथन का नहीं, यह अनुभूति से अर्थ रखता है. जिस तरह किसी फल को चखे बिना उसके स्वाद का पता नहीं पाया जा सकता, उसी तरह तत्व-ज्ञान भी अनुभूति के बगैर न तो समझा जा सकता है और न समझाया. अस्तु, जीवन के रहस्य को समझने के लिए हमें उस मार्ग पर बढ़ना पड़ता है, जिस पर चलकर किसी आचार्य ने वह अनुभूतिपरक उपलब्धि प्राप्त की हो.

उससे पहले उस मार्ग अथवा उस सद्गुरु को प्राप्त करना होगा, जो उस पथ को जानते हों, स्वयं जिस पर चलकर जिन्होंने वह परम-प्रसाद पाया हो, उस अजस्र स्रोत से जुड़ पाया हो और सक्षम भी हो, उतना कि किसी अन्य को उस पथ पर आगे बढ़ाकर गंतव्य तक पहुंचा सकता हो. क्योंकि, परमात्म-तत्व का वह मार्ग ऐसा है कि आगे बढ़ते जाने पर ही आगे का अगला हिस्सा दिखता है. अगले पग के सामने क्या आने वाला है, यह पथिक को ज्ञात नहीं रहता.

प्रस्तुत पुस्तक से सुधी पाठक निश्चित रूप से अपना अगला कर्तव्य समझ सकेंगे, ऐसा विश्वास किया जा सकता है. मुद्रण के पूर्व जो प्राय: हुआ करता है, वर्ण-शुद्धि (प्रूफ रीडिंग) के कार्य में किंचित त्रुटि दिखाई देती है, जिससे जहां-तहां व्याकरण का दोष दिखता है. लेकिन मैं यह मानता हूं कि महान लक्ष्य को ध्यान में रखकर सुधी पाठक इस त्रुटि को दृष्टि में नहीं रखेंगे. पाठकों द्वारा यह पुस्तक ससम्मान स्वीकार की जाएगी, ऐसी कामना के साथ मैं लेखक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. पुस्तक निस्संदेह स्वागतेय है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> बाइक में 106.7 सीसी इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इसका इंजन 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, एयरकूल्ड है. कंपनी ने इसके इंजन में एमसीआई–5 तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो इसके पॉवर और माइलेज में एक बढ़िया सामंजस्य बैठाती है. इसका इंजन टॉप 7500 आरपीएम पर 8.5 एनएम का टार्क पॉवर देता है, जो 110 सीसी के लिए काफी है.

# नए डिजाइन में क्रॉस पोलो

**कंपनी ने फ्रंट में सिंगल होरिजंट क्रोम स्लेट का इस्तेमाल किया है. रियर बैक में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. इसके एलॉय व्हीकल्स, हेलोजन हेडलैंप और ओआरवीएम में भी कुछ बदलाव किया गया है. क्रॉस पोलो अपने नए लुक और कलर की वजह से अन्य कारों से निश्चित तौर पर अलग नज़र आएगी.**

क्रॉस पोलो का कॉन्सेप्ट अधिकतर फैबिया स्काउट से मिलता–जुलता है. आने वाले समय में इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां देखने को मिल सकती हैं. क्रॉस पोलो की खास बात इसका डिजाइन है. नई क्रॉस पोलो में पुरानी पोलो के डिजाइन की तुलना में कई बदलाव किए गए हैं. कंपनी ने फ्रंट में सिंगल होरिजंट क्रोम स्लेट का इस्तेमाल किया है. रियर बैक में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. इसके एलॉय व्हीकल्स, हेलोजन हेडलैंप और ओआरवीएम में भी कुछ बदलाव किया गया है. क्रॉस पोलो अपने नए लुक और कलर की वजह से अन्य कारों से निश्चित तौर पर अलग नज़र आएगी.

**इंटीरियर:** इसके इंटीरियर में 2 डिन म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसे एयूएक्स, यूएसबी, एसडी कार्ड और ब्लूटूथ के साथ प्ले कर सकते हैं. इसमें इलेक्ट्रिक के जरिए एडजस्ट होने वाले रियर व्यू मिरर का भी इस्तेमाल किया गया है.

**इंजन और परफॉर्मेंस:** फॉक्सवैगन क्रॉस पोलो में 1.2 लीटर डीजल इंजन का प्रयोग किया गया है, जो 74 बीएचपी की क्षमता रखता है. इसके साथ ही क्रॉस पोलो का पीक टॉर्क 180 न्यूटन मीटर की ताकत देता है. इसके अलावा, इसमें 3 सिलेंडर और 4 पॉट वर्जन का इस्तेमाल किया गया है. हाईवे पर क्रॉस पोलो एक कंफर्ट क्रूजर की तरह है. 80–100 किमी/घंटा की एक नियमित स्पीड पर कार एक लीटर में 18–20 किमी तक माइलेज देती है. शहर के भीतर यह 15.5 किमी/ली. का माइलेज देती है. इसके 1.2 टीडीआई वैरिएंट का दाम 7,75,700 रुपये है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

# सुजूकी की इनाजुमा

जानी–मानी बाइक कंपनी सुजूकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड ने भारतीय बाज़ार में 250 सीसी क्षमता वाली इनाजुमा लॉन्च की है. इस बाइक की क़ीमत लगभग 3 लाख रुपये है. इनुजमा की खूबियों में 248 सीसी का ट्विएन–सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 स्पीड गियरबॉक्स, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विथ कॉइल स्प्रिंग, स्विंग आर्म टाइप रियर सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक आदि शामिल हैं. इस बाइक का फ्यूल टैंक 13.3 लीटर का है. यह बाइक दो रंगों में होगी, कैंडी कार्डिनल रेड और पर्ल नेब्यूलर ब्लैक. ■

# कम क़ीमत में बेहतरीन बाइक

**कंपनी ने तेल की टंकी 12.7 लीटर की बनाई है, जो इसके माइलेज के अनुसार बहुत है. भारतीय बाइक के इतिहास में पहली बार सेंच्यूरो में रिमोट फ्लिप चाबी का इस्तेमाल किया गया है, जो एक प्लास्टिक कवर से ढकी हुई है.**

बाइक प्रेमियों के लिए महिंद्रा ने अपना नया सेगमेंट बाज़ार में उतारा है. पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान होकर यदि आप कोई ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं, जो अच्छा माइलेज दे, तो महिंद्रा की सेंच्यूरो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

**डिजाइनिंग:** स्टाइल और डिजाइनिंग की बात करें, तो महिंद्रा की सेंच्यूरो में सबसे पहली नज़र उसके सुनहरे गोल्ड फ्रेम पर जाती है. यह फ्रेम इसे एक अलग हैवी लुक देता है. इस बाइक का व्हील बेस काफी लार्ज है. इसकी लंबी आरामदायक सीट दो लोगों के लिए बेहतर है. कंपनी ने राइडर की पोजिशन का भी ध्यान रखा है. बाइक राइडर के लंबे सफर को आरामदायक बनाया गया है. इसकी हैंडलिंग बेहतर और स्मूथ है. इस बाइक का वजन 111 किलो है, जो शहरों के ट्रैफिक के अनुसार ठीक है. कंपनी ने तेल की टंकी 12.7 लीटर की बनाई है, जो इसके माइलेज के अनुसार बहुत है. भारतीय बाइक के इतिहास में पहली बार सेंच्यूरो में रिमोट फ्लिप चाबी का इस्तेमाल किया गया है, जो एक प्लास्टिक कवर से ढकी हुई है. इस प्लास्टिक कवर में छोटी एलईडी लाइट दी गई है, जो अंधेरे में खड़े होने पर बाइक के लॉक को देखने में मदद करती है. इसके अलावा, कंपनी ने इसमें अलार्म भी दिया है, जो सैकड़ों बाइक्स में आपकी बाइक ढूंढने में मदद करता है. इसका सबसे बढ़िया पार्ट इसका एंटी थेफ्ट सिस्टम है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक चोरी नहीं हो सकती.

**इंजन और परफॉर्मेंस:** बाइक में 106.7 सीसी इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इसका इंजन 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर, एयरकूल्ड है. कंपनी ने इसके इंजन में एमसीआई–5 तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो इसके पॉवर और माइलेज में एक बढ़िया सामंजस्य बैठाती है. इसका इंजन टॉप 7500 आरपीएम पर 8.5 एनएम का टार्क पॉवर देता है, जो 110 सीसी के लिए काफी है. सेंच्यूरो चार गेयर ट्रांसमिशन वाली बाइक है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 95 किमी प्रति घंटा है. यह 60 की रफ्तार पर आसानी से पहुंच जाती है. एक एंट्री लेवल बाइक के अनुरूप इसका स्टाइल और पॉवर बेहतर है.

इसकी मेंटेनेंस फ्री बैटरी चालक को टेंशन फ्री रखती है.

**माइलेज:** इसकी एमसीआई–5 तकनीक इसे शानदार माइलेज देती है. कंपनी का दावा है कि हाईवे पर इसका माइलेज 85 किमी प्रति लीटर से अधिक है, जबकि शहर में यह 60–70 किमी तक रफ्तार देती है.

**सेफ्टी फीचर्स:** बाइकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए कंपनी ने इसमें ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स दिए हैं. इसका रिमोट फ्लिप इसे चोरी होने के भय से मुक्त रखता है. इसमें एलईडी टॉर्च भी है, जो अंधेरे में आपको रास्ता दिखाएगी. बाइक का अलार्म आपको पार्किंग में बाइक खोजने में मदद करता है. चोरी होने पर चाबी से उसका इंजन आप बंद कर सकते हैं. कम दाम में फीचर्स के मामले में यह शानदार है.

**क्यों ले सेंच्यूरो:** पांच साल की वारंटी, कम क़ीमत, शानदार सेफ्टी फीचर्स, बढ़िया आरामदायक सफर और माइलेज इसके प्लस प्वाइंट हैं.

**कीमत:** इस बाइक की एक्स शोरूम क़ीमत मात्र 45 हज़ार रुपये है, जबकि इस सेगमेंट की बाइक की क़ीमत इससे ज़्यादा है. ■

# 7 खास ऐप

## 1 पावर ट्यून अप-ऐप

पावर ट्यून-अप: आप पावर ट्यून-अप ऐप का प्रयोग करके स्मार्ट फोन में ढेरों फंक्शन होने के कारण बैटरी की खपत की समस्या से निजात पा सकते हैं.

## 2 स्क्रीबल लाइट

यह एप्लिकेशन उन यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें लंबे ईमेल देखने या ईबुक रीडर पर कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए बार-बार क्लिक करके स्क्रीन लाइट ब्राइट करनी पड़ती है.

## 3 फोन वॉरियर

यूजर्स अनचाही कॉल्स और मैसेज से परेशान होते हैं और उनसे छुटकारा भी पाना चाहते हैं. फोन वॉरियर एप्लिकेशन अनचाही कॉल्स और मैसेज से छुटकारा दिलाता है. साथ ही यह कॉलर की पहचान भी यूजर को बता देता है.

## 4 सेवर प्लस ए

कुछ एप्लिकेशन ऐसे होते हैं, जिनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है और वही एप्लिकेशन यूजर्स की मोबाइल बैटरी को सबसे जल्दी ख़त्म कर देते हैं. इससे बचने के लिए आप सेवर प्लस ए से सभी एप्लिकेशंस की बैटरी खपत जान सकते हैं.

## 5 एडेप्टएक्सटी कीबोर्ड

यह एप्लिकेशन यूजर्स की लेखन शैली सीखने और उसके अनुसार खुद को ढालने में माहिर है. इसके माध्यम से कीबोर्ड का अधिक उपयोग किए बिना अधिक से अधिक लिखा जा सकता है. इसमें ऑटो करेक्शन होने से लेखन की गलतियां दूर हो जाती हैं.

## 6 कंट्रोल मी

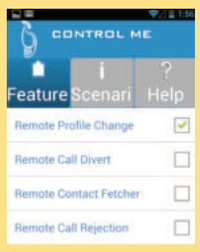


अगर आप अपना मोबाइल भूल जाते हैं, तो इस ऐप की मदद से आप उसमें सेव नंबर पा सकते हैं, कॉल डायवर्ट कर सकते हैं और खो जाने की हालत में इससे अपना डाटा एक एसएमएस भेजकर मिटा भी सकते हैं.

## 7 टोशल

टोशल के माध्यम से आप अपने खर्च का पूरा ब्योरा रख सकते हैं. यह एप्लिकेशन रोजाना होने वाले खर्च को भी दिखाता है, जिसे हर रोज भरने की आवश्यकता नहीं होती. वक्त और पैसे की बचत के साथ यह आपके एकाउंट को मैनेज करने में सहायक है.

# माइक्रोमैक्स का फैबलेट

देश की जानी-मानी मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स ने एक नया स्मार्ट फोन लॉन्च किया है. 6 इंच की स्क्रीन वाले इस फैबलेट का नाम है माइक्रोमैक्स कैनवॉस एक्सएल-119. इसकी खास बात इसका डुअल सिम है. इसके अलावा, 5 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा भी इसका एक जबरदस्त फीचर है. इसकी क़ीमत 13,990 रुपये है.

खास फीचर्स: 6 इंच की टीएफटी स्क्रीन
-1.3 जीएचजेड का क्वैड कोर प्रोसेसर.
-एंड्रॉयड का 4.2 जैली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम.
-1 जीबी की रैम.
-4 जीबी का इंटरनल स्टोरेज.
-माइक्रो एसडी कार्ड के साथ 32 जीबी तक स्टोरेज.
-8 मेगा पिक्सल का रियल कैमरा, एलईडी फ्लैश के साथ.
-5 मेगा पिक्सल का फ्रंट कैमरा.
-3 जी, वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ 2 डीपी सपोर्ट.
-3.5 एमएम का ऑडियो जैक, एफएम रेडियो भी.
-मोटाई 10.4 मिलीमीटर, वजन 180 ग्राम.
-2450 एएच क्षमता की बैटरी. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 2 जी पर 9 घंटे का टॉकटाइम देगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

यदि आपको किसी लोकप्रिय भारतीय एथलीट का नाम लेने को कहा जाए, तो आपके जेहन में सबसे पहले मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा का नाम आएगा. इन्होंने बेहद मुश्किलों का सामना करते हुए दुनिया भर में भारत का परचम लहराया था. हालांकि ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक पदक जीतने से महज कुछ दूरी पर रह गए.





## अंजू बॉबी जॉर्ज

# सर्वश्रेष्ठ भारतीय एथलीट

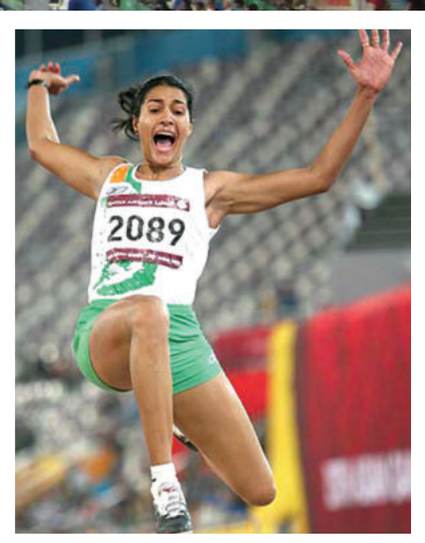



**भारत ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में हमेशा से पदकों के लिए तरसता रहा है. भारत के सर्वकालिक महान एथलीटों में शुमार फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उडन परी पी टी ऊषा जो नहीं कर पाए, वह कारनामा अंजू बॉबी जॉर्ज ने कर दिखाया है. क्या अंजू भारत की सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं?**

नवीन चौहान

बड़ी ख़ामोशी और प्रशंसकों की ग़ैर-मौजूदगी में वर्ष 2005 में मोनेको में वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल मुक़ाबले में अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला रजत पदक अब स्वर्ण में बदल गया है. इस तरह अंजू किसी विश्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गईं हैं. फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उड़न परी पी टी ऊषा जो नहीं कर पाए, दरअसल वह कारनामा अंजू बॉबी जॉर्ज ने कर दिखाया है. वर्ष 2005 में मोनेको में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रूसी खिलाड़ी तत्याना कुतोवा ने 6.83 मीटर लंबी छलांग लगाकर स्वर्ण पदक पर क़ब्ज़ा किया था. वहीं अंजू 6.75 मीटर लंबी छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर रहीं और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था. हालांकि, वह दौर अंजू के करियर का सर्वश्रेष्ठ दौर था. अंजू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहीं थीं. वर्ष 2003 में अंजू पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी. उसके बाद वर्ष 2004 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया था. अंजू उस दौर की एक अविवादित एथलीट थीं, जिनके करियर पर किसी भी तरह का दाग़ नहीं लगा था. कहते हैं भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं. जिस खेल भावना के साथ अंजू खेलीं, अंततः उसका सकारात्मक परिणाम निकला और आठ साल बाद अंजू का विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा हुआ. वैसे उनकी इस उपलब्धि के बाद यह बहस भी छिड़ गई कि भारत का सर्वकालिक एथलीट कौन है?

यदि आपको किसी लोकप्रिय भारतीय एथलीट का नाम लेने को कहा जाए, तो सबसे पहले आपके जेहन में मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा का नाम आता है. दोनों ने ही बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए दुनिया भर में भारत का परचम लहराया था. दोनों ही खिलाड़ी ओलंपिक पदक जीतने से महज कुछ दूरी पर रह गए. उड़न सिख के नाम से विख्यात मिल्खा सिंह वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे थे. तब उनका नाम पदक जीत सकने वालों की सूची में सबसे ऊपर था. हर किसी को आशा थी कि मिल्खा सिंह भारत के लिए पदक जीतेंगे, लेकिन वह चूक गए. वैसे मिल्खा सिंह ने अपने करियर में तीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया, लेकिन वह कोई पदक नहीं जीत सके. हालांकि, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में उनका दबदबा बना रहा. उन्होंने वर्ष 1958 में टोकियो में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था. मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में कुल चार स्वर्ण पदक जीते थे. कहा जाता है कि मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में कुल 80 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया और 77 मुक़ाबले में उन्हें जीत मिली थी.

भारत में उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी ऊषा ने भारत के लिए कई ख़िताब जीते, जिस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा. पीटी ऊषा पहली बार वर्ष 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा लिया था. मॉस्को ओलंपिक में वह पदक जीतने में भले ही सफल नहीं हुईं, लेकिन वह अपनी छाप छोड़ने में कामयाब ज़रूर हुई थीं. वर्ष 1982 के दिल्ली एशियाई खेलों में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की स्पर्धाओं में रजत पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि वह आने वाले समय में वह एक बड़ी खिलाड़ी बनेंगी. उसके बाद कतर में वर्ष 1983 में ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता में उन्होंने 400 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता. 1984 में लॉस एंजिल्स में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में उन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में पहला स्थान प्राप्त किया था. इसी के साथ वह ओलंपिक के फाइनल मुक़ाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं. हालांकि, फाइनल मुक़ाबले में वह कांस्य पदक जीतने से चूक गईं. इसके बाद भी ऊषा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी. वर्ष 1986 में सियोल एशियाई खेलों में पीटी ऊषा ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था. उन्हें एशियाई खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था. उन्होंने वर्ष 1984 से लेकर 1989 तक एशियाई ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण पदक जीते थे. वह 1984 से 1989 तक पांच बार सर्वश्रेष्ठ एशियाई खिलाड़ी और 1984 एवं 1985 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गईं थीं. हालांकि पीटी ऊषा ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीत सकीं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीत लिया.

वहीं अंजू बॉबी जॉर्ज अपने करियर की शुरूआत में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराना शुरू कर दिया था. अंजू ने वर्ष 2002 में मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी कूद का कांस्य पदक जीता था. इसके बाद वर्ष 2002 में हुए बुसान एशियाई खेलों में लंबी कूद का स्वर्ण पदक पर भी क़ब्ज़ा किया. बुसान के फॉर्म को अंजू ने आगे भी बरकरार रखते हुए वर्ष 2003 में पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया. ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय एथलीट बनीं. वर्ष 2005 में मोनेको में हुए वर्ल्ड एथलेटिकस फाइनल में उन्होंने अपना परचम लहराया और रजत पदक जीतने में कामयाब हुईं. इसी के साथ दुनिया भर में अंजू मशहूर खिलाड़ी बन गईं. वर्ष 2004 के एथेंस ओलंपिक में उन्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ. वैसे वह विश्व चैंपियनशिप में किए अपने कारनामे को दोहराने में असफल रहीं. उसके बाद कोरिया के इचोहेन में हुई एशियन चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन 2006 में दोहा एशियाई खेलों में उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा. अंजू इसके बाद किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पदक नहीं जीत पाईं.









### आइएएएफ के फ़ैसले से कोटोवा के अयोग्य घोषित होने के बाद के बाद नई रैंकिंग इस प्रकार हैं.

| | | |
|---|---|---|
| स्वर्ण पदक - | अंजू बॉबी जॉर्ज | (भारत , 6.75 मीटर) |
| रजत पदक - | अनुग्रह उपसा | (अमरीका, 6.67 मीटर) |
| कांस्य पदक - | ईयूनिस नाई | (फ्रांस , 6.51मीटर) |

### अंजू बॉबी जॉर्ज की उपलब्धियां

अंजू बॉबी जॉर्ज वर्ष 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी. उन्हें वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था.

वर्ष 2004 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया.

ग़ौरतलब है कि वर्ष 2007 के आईएएएफ रैंकिग में उन्हें चौथा स्थान मिला. विश्व रैंकिंग के टॉप फाइव में जगह पाने वाली वह पहली भारतीय एथलीट थीं. अंजू वर्ष 2001 से 2003 के अंतराल में विश्व रैंकिंग में 61 पायदान से 6 वें पायदान पर पहुंची थीं.

अंजू ने अपने पूरे करियर के दौरान कड़ी मेहनत की और उस मुकाम पर पहुंची, जहां हर कोई पहुंचना चाहता है. देर से ही सही पर उन्हें विश्व चैंपियन का ख़िताब हासिल हुआ. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 के ओलंपिक से लेकर अब तक के सैंपल की एक बार फिर से जांच करने का फ़ैसला आईएएएफ ने किया है. हो सकता है कि भविष्य में अंजू बॉबी जार्ज ओलंपिक पदक विजेता भी बन जाए. अगर वह ओलंपिक पदक जीतने में कामयाब नहीं होती हैं, तब भी उनका नाम भारत के सर्वकालिक महान एथलीटों में शामिल रहेगा. डोपिंग के जाल से बचकर अंजू बॉबी जार्ज ने बिना विचलित हुए जो कारनामा कर दिखाया है, वह क़ाबिल-ए-तारीफ़ है. मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा आज भी देश के उभरते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श हैं. देश भर में लोग उन्हें जानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं. तीनों की उपब्धियों पर देश को गर्व है. हालांकि, अंजू इन दोनों महान खिलाड़ियों से एक कदम आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि वह विश्व चैंपियन हैं. उन्होंने देश वासियों के लिए जो उपलब्धि हासिल की है, दरअसल वह अनमोल है. वैसे कोई भी खिलाड़ी एक-दूसरे से कमतर नहीं हैं. उन्होंने अपने-अपने समय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. किसी विवाद में फंसे बग़ैर अंजू ने देश का मान बढ़ाया. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

जन्मदिन पर विशेष

## ग़ज़ल सम्राट जगजीत सिंह

# कामयाब क़लाकार नायाब इंसान

**जगजीत सिंह उस शख्सियत का नाम है, जिसने ग़म में भी मुस्कराना सिखाया. वह एक मिशाल थे कि किस तरह जीवन को भरपूर ऊर्जा के साथ जिया जाता है, टूटे दिल और टूटे सपनों के साथ भी. उन्होंने टूटे दिलों को सहारा दिया. उनका खुद का जीवन दु:ख का सागर था, पर उनके चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कराहट रही. उनकी ग़ज़लें ही उनके लिए प्रेरणास्रोत थीं और जीवन जीने का हौसला भी.**

हरफन मौला ग़ज़ल सम्राट जगजीत सिंह को शायद अपनी मृत्यु का आभास हो गया था. अपनी मृत्यु से चार-पांच दिन पहले दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में उन्होंने अपनी आख़िरी लाइव परफॉर्मेंस दिया था, तो उन्होंने मजाक वश श्रोताओं से कहा था, ठुकराओ न, मुझको प्यार करो, मैं सत्तर का हूं.



**प्रियंका प्रियम तिवारी**

हरदिल अजीज ग़ज़ल सम्राट जगजीत सिंह तीन वर्ष पूर्व 10 अक्टूबर, 2011 को अपने लाखों-लाख प्रशंसकों को रोता-बिलखता छोड़ गए थे, लेकिन उनके द्वारा गाई ग़ज़लें और उनकी मखमली आवाज़, दोनों आज भी लोगों को राहत देती हैं. जगजीत काफ़ी समय से मस्तिष्काघात (ब्रेन हैमरेज) से पीड़ित थे. प्रख्यात शायर एवं गीतकार कैफ़ी आजमी की यह ग़ज़ल देखिए, जिसे जगजीत ने अपनी आवाज़ दी थी, जो आज भी लोगों की जुबान पर जब-तब आते हुए देखी जाती है:

*तुम इतना जो मुस्करा रहे हो,*
*क्या ग़म है, जिसको छुपा रहे हो.*
*आंखों में नमी, हंसी लबों पर,*
*क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो.*
*बन जाएंगे ज़हर पीते-पीते,*
*ये अश्क जो पीते जा रहे हो.*
*जिन जख्मों को वक्त भर चला है,*
*तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो.*
*रेखाओं का खेल है मुकद्दर,*
*रेखाओं से मात खा रहे हो.*

इस ग़ज़ल में जैसे उन्होंने अपना दिल खोलकर रख दिया. अपना दर्द, अपने आंसुओं एवं अपनी तन्हाई को स्वीकार कर लिया कि यह सब खेल रेखाओं का है.

ग़ज़ल को पहले पढ़ा-सुना जाता था, लेकिन उसे सुरों में पिरोने का काम जगजीत सिंह ने किया. हालांकि जगजीत सिंह से पहले मेहंदी हसन ने ग़ज़लों को सुर देने का काम किया था, लेकिन वह ग़ज़ल प्रेमियों की प्यास बढ़ाकर शुरुआती दौर में ही पाकिस्तान चले गए. इसके बाद आए जगजीत सिंह. जगजीत ने 150 से ज़्यादा एलबम बनाए.

जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी, 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था. उनके पिता का नाम सरदार अमर सिंह धमानी था और वह भारत सरकार के कर्मचारी थे. वह पंजाब के रोपड़ ज़िले के दल्ला गांव के निवासी थे. जगजीत के बचपन का नाम जीत था. उनकी शुरुआती शिक्षा गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में वह पढ़ने के लिए जालंधर आ गए. डीएवी कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली और उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. युवावस्था में अन्य लोगों की तरह उन्हें भी प्यार हुआ. अपने पहले प्यार को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि वह एक लड़की को चाहते थे. जालंधर में पढ़ाई के दौरान वह साइकिल से आते-जाते थे. लड़की के घर के सामने साइकिल की चेन टूटने या हवा निकलने का बहाना करके बैठ जाते और उसे देखा करते थे, पर उनका पहला प्यार नाकामयाब रहा. पढ़ाई में उनकी ख़ास दिलचस्पी नहीं थी. कुछ क्लासेज में तो उन्होंने दो-दो साल गुज़ारे. कॉलेज के दिनों में वह अधिकतर समय गर्ल्स कॉलेज के आसपास गुजारते थे. और तो और, पिता की इजाज़त के बग़ैर फ़िल्में देखने के लिए गेट कीपर को घूस तक देते थे. जगजीत सिंह को घुड़सवारी का भी शौक था.

संगीत उन्हें विरासत में मिला. पंडित छगन लाल शर्मा के सानिध्य में दो साल तक उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा. उन्होंने सैनिया घराने के उस्ताद जमाल ख़ान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां भी सीखीं. पिता की ख्वाहिश थी कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं, लेकिन जगजीत पर गायक बनने की धुन सवार थी. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान संगीत में उनकी दिलचस्पी देखकर कुलपति प्रोफेसर सूरजभान ने उन्हें काफ़ी उत्साहित किया और उन्हीं के परामर्श पर जगजीत 1965 में मुंबई आ गए. यहां उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया. पहले से स्थापित गायकों के रहते इंडस्ट्री में जगह बनाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था. शुरुआत में अपने ख़र्चे निकालने के लिए उन्होंने विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाने से लेकर शादी-समारोहों तक में गाने गाए. फिर उनका एलबम रिलीज हुआ-अनफॉरगेटेबल, जो कि हिट रहा. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

**मशहूर फिल्मी गीत**

जगजीत सिंह ने अर्थ, साथ-साथ एवं प्रेमगीत जैसी फिल्मों में गीत गाए. होठों से छू लो तुम...(प्रेमगीत), तुमको देखा तो ये ख्याल आया...(साथ साथ), झुकी-झुकी सी नज़र...(अर्थ), कोई ये कैसे बताये (अर्थ) होश वालों को ख़बर क्या...(सरफरोश) और बड़ी नाजुक है...(जॉगर्स पार्क) जैसी ग़ज़लों के माध्यम से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. हालांकि जीवन के अंतिम दिनों में वह निर्माताओं द्वारा पैसे को ज़्यादा तवज्जो देने के चलते फिल्मों में गायन से दूर हो गए थे. उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को अपनी आवाज़ दी और उनका संवेदना नामक एक एलबम भी निकाला.

**विवादों से नाता**

यह तो सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करती, लेकिन वहां टैलेंट की कद्र भी होती है. अपने संघर्ष के दिनों में जगजीत सिंह काफ़ी टूट गए थे. इस घुटन में उन्होंने स्थापित प्लेबैक सिंगरों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी. हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ. दूसरा विवाद उनके साथ जुड़ा भारत-पाक पर टिप्पणी को लेकर. उन्होंने करगिल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान से आ रहे गायकों पर ऐतराज किया. जगजीत सिंह का कहना था कि उनके आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. दरअसल, जगजीत को पाकिस्तान ने वीज़ा देने से इंकार कर दिया था. वह काफी सरल हृदय के थे. जब पाकिस्तान से बुलावा आया, तो जगजीत सिंह की नाराज़गी दूर हो गई. उन्होंने ग़ज़लों के शहंशाह मेहंदी हसन के इलाज के लिए तीन लाख रुपये की मदद भी की, जबकि मेहंदी हसन को पाकिस्तान सरकार तक ने नज़रअंदाज़ कर दिया था.

उन्होंने 1970 में चित्रा से शादी की. चित्रा की शादी जगजीत से पहले किसी अन्य से हो चुकी थी. पहले पति से उनकी एक बेटी मोनिका थी. जगजीत एवं चित्रा का एक बेटा विवेक था. उनकी ज़िंदगी खुशी से गुज़र रही थी, तभी अचानक उनके बेटे विवेक की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जबकि चित्रा की शादीशुदा बेटी मोनिका ने अपने अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली. चित्रा ने इन हादसों के बाद गाना बंद कर दिया. इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद जगजीत ने भी कुछ समय के लिए गाना बंद कर दिया, पर फिर उन्होंने गाना शुरू किया.

**कुछ चुनिंदा ग़ज़लें**

*जाना है जाना है चलते ही जाना है,*
*ना कोई अपना है, ना ही ठिकाना है.*
*सब रास्ते नाराज़ हैं,*
*मंजिल की आहटों से राही बेगाना है,*
*जाना है जाना है चलते ही जाना है.*
*क्या कभी साहिल भी तूफ़ान में बहते हैं,*
*सब यहां आसान है, हौसले कहते हैं.*
*शोलों पे, कांटों पे, हंस के चल सकते हैं,*
*अपनी तकदीर को हम बदल सकते हैं.*
*बिगड़े हालात में दिल को समझाना है,*
*जाना है जाना है चलते ही जाना है.*
*ख्वाबों की दुनिया में, यादों के रेले में,*
*आदमी तन्हा है, भीड़ में, मेले में.*
*ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है,*
*पांव रुक जाते हैं, वक्त थम जाता है.*
*ऐसे में तो मुश्किल आगे बढ़ पाना है,*
*जाना है जाना है चलते ही जाना है.*

**********

*परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता,*
*किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता.*
*बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना,*
*जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता.*
*तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज़ वाला है,*
*हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता.*
*मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है,*
*कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता.*

**********

*कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है,*
*दिल में पराया दर्द बसाना मेरी आदत है.*
*मेरा गला अगर कट जाए, तो मुझ पर क्या इल्जाम?*
*हर कातिल को गले लगाना मेरी आदत है.*
*जिनको दुनिया ने ठुकराया, जिनसे हैं सब दूर,*
*ऐसे लोगों को अपनाना मेरी आदत है.*
*सबकी बातें सुन लेता हूं मैं चुपचाप मगर,*
*अपने दिल की करते जाना मेरी आदत है.*

**********

*मुस्कुरा कर मिला करो हमसे.*
*कुछ कहा और सुना करो हमसे.*
*बात करने से बात बढ़ती है,*
*रोज बातें किया करो हमसे.*
*दुश्मनी से मिलेगा क्या तुमको?*
*दोस्त बनकर मिला करो हमसे.*
*देख लेते हैं सात पर्दों में,*
*यूं न पर्दा किया करो हमसे.*

**********

*तन्हा-तन्हा हम रो लेंगे, महफ़िल-महफ़िल गाएंगे,*
*जब तक आंसू साथ रहेंगे, तब तक गीत सुनाएंगे.*
*तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं,*
*देर न करना घर जाने में वरना घर खो जाएंगे.*
*बच्चों के छोटे हाथों को चांद-सितारे छूने दो,*
*चार किताबें पढ़कर वो भी, हम जैसे हो जाएंगे.*
*किन राहों से दूर है मंजिल, कौन सा रास्ता आसां है,*
*हम जब थककर रुक जाएंगे, औरों को समझाएंगे.*
*अच्छी सूरत वाले सारे, पत्थर दिल हों मुमकिन है,*
*हम तो उस दिन राय देंगे, जिस दिन धोखा खाएंगे.* ■

feedback@chauthiduniya.com

# अलगाव के लिए ऋतिक ख़ुद ज़िम्मेदार

ऋतिक रोशन और सुजैन के तलाक के पीछे दोनों के अलग-अलग अफेयर्स को वजह बताया जा रहा था, लेकिन अब ऋतिक ने स्वीकार कर लिया है कि उनका रिश्ता टूटने की वजह वह खुद हैं. उन्होंने हाल में गूगल हैंगआउट पर अपने प्रशंसकों से बातचीत के दौरान यह स्वीकार किया. ऋतिक ने यह भी स्वीकार किया कि सार्वजनिक तौर पर भी उन्हें पत्नी सुजैन से अलग होने की वजह से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. अलग होने का फ़ैसला सुजैन ने किया था, लेकिन उनके परिवार एवं दोस्तों ने भी उनकी खूब आलोचना की. उनके क़रीबी लोगों का कहना है कि ऋतिक सुजैन की भावनाओं की परवाह नहीं करते थे. कोई एक वजह नहीं, उन्होंने कई गलतियां कीं. वह खुद के फेवरेट थे और उन्हें लगता था कि वही सही हैं. ऐसे में सुजैन लगातार खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थीं.

ऋतिक और सुजैन की शादी 20 दिसंबर, 2000 को हुई थी. शादी से पहले चार सालों तक दोनों का अफेयर चला. उनके दो बेटे भी हैं. 7 वर्षीय रिहान और 5 वर्षीय रिदान. कहा जा रहा है कि दोनों के अलवाग की वजह किसी तीसरे शख्स की उनकी ज़िंदगी में एंट्री है. माना जा रहा था कि बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल की सुजैन से बढ़ती नज़दीकियां उनके तलाक की वजह थीं. पर अब यह बात साफ़ हो चुकी है कि वह क़रीबी दोस्त मात्र हैं. माना यह भी जा रहा है कि कटरीना से ऋतिक की नजदीकियों को लेकर भी काफी खफा थीं सुजैन. कटरीना और ऋतिक के बीच लव ऐंड हेट का खेल फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से चल रहा है. इन दिनों कटरीना के रणबीर कपूर से बेकअप की खबरे भी आ रही हैं. अब देखना यह है कि दोनों आने वाले समय में हमराह बनते हैं या यह खबर सिर्फ गॉसिप बन कर रह जाएगी. 2013 में ऋतिक रोशन की फिल्म कृष-3 कमाई के मामले में ब्लाकबस्टर रही. 2014 में भी उनकी फिल्म कृष्णा रिलीज होने वाली है. उम्मीद की जा रही है कि ऋतिक की यह फिल्म भी अच्छा प्रदर्शन करेगी. ■

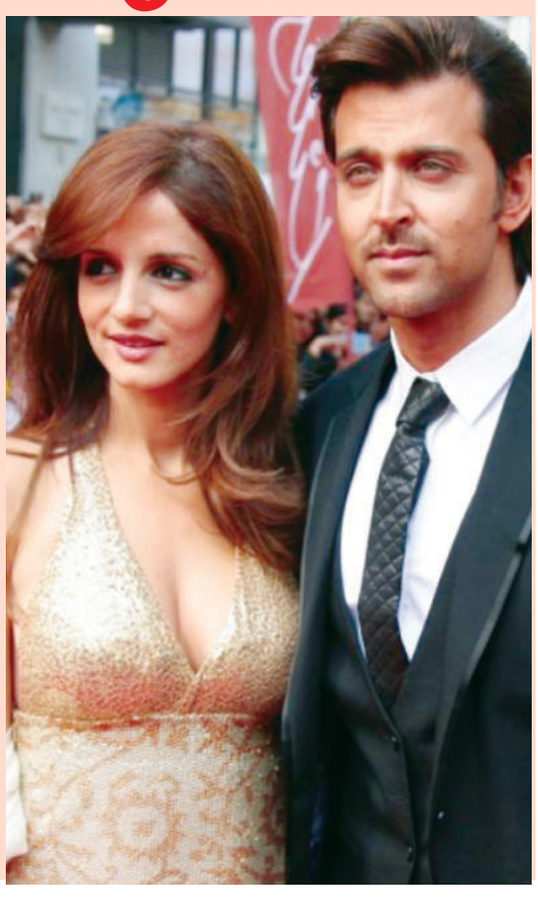

# दोस्त-दोस्त न रहा...

अमिताभ बच्चन और अमर सिंह की दोस्ती जगजाहिर थी, पर इस दोस्ती को बाद में ग्रहण लग गया. हाल में अमर सिंह और अमिताभ बच्चन का आमना-सामना हुआ फिल्म प्रोड्यूसर कुमार मंगत की बेटी अमृता पाठक और गायक राघव सच्चर की शादी के मौक़े पर. इस शादी में अमिताभ और अमर सिंह दोनों मौजूद थे. सामने पड़ने पर अमिताभ बच्चन ने सभी गिले-शिकवे भुलाकर अमर सिंह को गले लगा लिया. अभिषेक ने भी अमर सिंह के पैर छुए और अमर सिंह ने अभिषेक को गले लगाया. लेकिन बाद में इस बारे में अमर सिंह ने कुछ अलग ही कहानी बयान की. उन्होंने कहा कि उनके और अमिताभ के बीच किसी तरह का पैचअप नहीं हुआ. अगर वह वहां आ गए, तो मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है.

दरअसल, हुआ यह कि अमिताभ जब अभिषेक के साथ होटल पहुंचे, तो एंट्री करते ही उनकी नज़र अमर सिंह पर पड़ी, लेकिन वह आगे बढ़ गए. अमर सिंह ने भी यही किया. जब अमिताभ वर-वधू को आशीर्वाद देने स्टेज पर पहुंचे, तो आसपास कहीं अमर सिंह नहीं दिखे. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा, तो पता चला कि अमर सिंह अपने प्राइवेट रूम में हैं. अमिताभ अमर सिंह से मिलने उनके रूम तक जा पहुंचे. अमिताभ ने रूम के बाहर खड़े अमर सिंह को पीछे से गले लगा लिया. आश्चर्यचकित अमर सिंह ने अमिताभ को देखा, फिर दोनों गले लग गए. लेकिन बाद में अमर सिंह ने कहा, मेरी गलती थी कि मैं जया बच्चन को राज्यसभा तक ले गया. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे ख़िलाफ ही कुछ करेंगी. इसलिए अब मैं उनके साथ दोस्ती कैसे कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि किसी को इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए. हमारे बीच सिर्फ़ दो मिनट बातचीत हुई. अमिताभ ने मुझसे मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा. इससे ज़्यादा हमारे बीच कोई खास बात नहीं हुई. ■

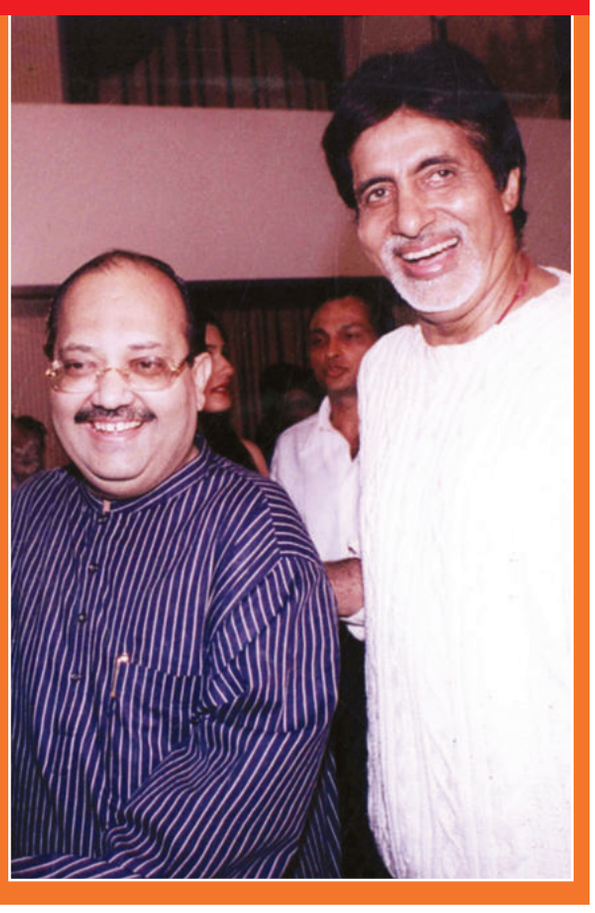

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

03 फरवरी –09 फरवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467


## बिहार – झारखंड

# बिहार में बिजली

# क्या है हकीकत, क्या है फसाना!

**बात की शुरुआत बिहार में बिजली के गुम हो जाने के खेल से करते हैं. कुछ महीने पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन के पास बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने 2011 का जो टैरिफ पेटिशन सौंपा है, उसके अनुसार 57 प्रतिशत से अधिक बिजली एयर ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉस हो जाती है. यानि 100 रूपये की बिजली है तो उसमें 57 रुपये बैताल खाते में जाता है. यह लॉस एक रिकॉर्ड की तरह है. देश के सभी राज्यों में यह लॉस होता है लेकिन बिहार में इस लॉस के खेल को समझेंगे तो लगेगा कि यह लॉस जितना होता नहीं, उससे ज्यादा सुनियोजित तरीके से कराया जाता है. बिजली के पेंच को समझने वाले जानकार बताते हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन के मुताबिक यह लॉस 29 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और एक्सेलेरेटेड पावर रिफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानदंड को मानें तो यह लॉस 15 प्रतिशत में सिमटकर रहना चाहिए था. लेकिन फिलहाल बिजली को लेकर भविष्य के तानेबाने बुनने में मगन महकमे में यह सवाल हाशिये पर है.**

शशि सागर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सप्ताह में बिजली पर दो बयान दिए. दोनों बयान गौर करने लायक हैं और इन बयानों में आए फर्क पर भी गौर करने की जरूरत है. इसी से बिजली, सियासत और चुनावी राजनीति के रिश्ते का गणित बहुत हद तक साफ हो जाएगा. मुजफ्फरपुर की एक सभा में गत 18 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगले चार साल में बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी. अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर पावर ग्रीड और पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है. साथ ही यह भी कहा कि अगले साल तक सूबे में चार हजार मेगावाट बिजली खपत करने का लक्ष्य है और मैं इसे लेकर प्रतिबद्ध हूं. इसके दो दिन बाद ही अपनी संकल्प रैली के दौरान गया में उन्होंने कहा कि बिजली की स्थिति नहीं सुधरी तो 2015 में वोट नहीं मांगूंगा. ये दोनों बयान तो हाल के दिनों के हैं. गत 18 नवंबर को मुजफ्फरपुर के कांटी में दिए गए उनके बयान को देखिए. इस दिन उन्होंने कहा था कि 2015 तक मेरा लक्ष्य हर गांव में बिजली पहुंचाना है. ऐसा ही एक अतिउत्साही बयान उन्होंने 15 अगस्त 2012 के दिन गांधी मैदान में दिया था. उस दिन भी उन्होंने कहा था कि मैंने वादा किया है कि बिजली की स्थिति को सुधारेंगे. आज वे इसी बात को दोहराते हैं कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाया तो 2015 में वोट नहीं मांगने जाऊंगा. बिजली पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगातार बदलते बयान बता रहे हैं कि आनेवाले दिनों में बिहार की सियासत और चुनावी मैदान में बिजली एक बैताल की तरह उनके कंधे पर लटक सकते हैं.

बिहार में बिजली को लेकर नीतीश कुमार के बयान अगर इस तरह बदल रहे हैं या वे बार-बार बिजली को लेकर बयान दे रहे हैं तो इसकी वजह भी है. उन्हें पता है कि बिहार में बिजली एक बड़ी चुनौती है और इससे पार पा लेना उससे भी बड़ी चुनौती. बिहार में बिजली को लेकर बवाल मचता रहा है. इसी जनवरी माह में बिजली के विभिन्न सवालों को लेकर वामदलों ने बिहार बंद किया था. यह बंद वितरण कंपनियों की मनमानी, शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि और उपभोक्ताओं की प्रताड़ना के खिलाफ था. इन्हीं सब सवालों को लेकर आगामी 18 फरवरी से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं लेकिन बिहार के अलग-अलग इलाकों में घूमते हुए बिजली से जुड़े कई तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं. हकीकत से सामना होता है. बिहार में बिजली की दशा सुधारने के लिए भविष्य का जो तानाबाना बुना गया है, वह कुछ सालों बाद यदि हकीकत में बदला तो बिहार की तस्वीर और तकदीर बहुत हद तक बदलेगी लेकिन यह बातें भविष्य की है. बिहार में अतीत के रास्ते अगर वर्तमान पर एक छोटी नजर डालें तो यह खेल पता चलेगा कि यहां बिजली को निगलनेवाले खिलाड़ियों की एक फौज है और इन खिलाड़ियों को विजेता बनाने वाले रेफरी भी मैदान में अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं.

बात की शुरुआत बिहार में बिजली के गुम हो जाने के खेल से करते हैं. कुछ महीने पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन के पास बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने 2011 का जो टैरिफ पेटिशन सौंपा है, उसके अनुसार 57 प्रतिशत से अधिक बिजली एयर ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉस हो जाती है. यानि 100 रूपये की बिजली है तो उसमें 57 रुपये बैताल खाते में जाता है. यह लॉस एक रिकॉर्ड की तरह है. देश के सभी राज्यों में यह लॉस होता है लेकिन बिहार में इस लॉस के खेल को समझेंगे तो लगेगा कि यह लॉस जितना होता नहीं, उससे ज्यादा सुनियोजित तरीके से कराया जाता है. बिजली के पेंच को समझने वाले जानकार बताते हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन के मुताबिक यह लॉस 29 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और एक्सेलेरेटेड पावर रिफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानदंड को मानें तो यह लॉस 15 प्रतिशत में सिमटकर रहना चाहिए था. लेकिन फिलहाल बिजली को लेकर भविष्य के तानेबाने बुनने में मगन महकमे में यह सवाल हाशिये पर है. वहीं बिजली विभाग के एक अधिकारी बताते हैं कि 18 प्रतिशत तो टेक्निकल लॉस होता है और वो होगा ही लेकिन बिहार में कुल लाइन लॉस 44 प्रतिशत है. इसका मतलब हुआ कि 26 प्रतिशत लॉस तो चोरी में चला जाता है. मतलब ये कि बिजली चोरी का भी मामला बिहार में गंभीर है और कहीं न कहीं यह सुनियोजित भी है. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्रवक्ता हरेराम पांडेय ने थोड़े दिन पहले कहा था कि यह 40 प्रतिशत के करीब ही होगा. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कई अधिकारियों से बात होती है लेकिन वे हमें लॉस के कारणों का सही-सही जवाब नहीं दे पाते हैं. नाम नहीं छापने के शर्त पर एक अधिकारी कहते हैं कि लॉस को समझना एक जाल की तरह है. हम इसी समस्या को दूर करने के लिए वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं. वे कहते हैं कि पटना में 400 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती है, हमें 90 करोड़ के करीब इससे राजस्व चाहिए लेकिन 60-70 करोड़ से ज्यादा राजस्व का संग्रहण कभी नहीं हो पाता. लॉस के झमेले को समझने के लिए थोड़ा अतीत में झांकने की आवश्यकता है. बात 2008 की है. विद्युत निगरानी कोषांग के महानिदेशक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आनंद शंकर हुआ करते थे. महानिदेशक के निर्देश पर बिजली के बड़े खिलाड़ियों पर छापेमारी शुरू हुई. कई केस दर्ज हुए, जिसमें एक केस 67/2008 भी था जो एक स्टील कंपनी के खिलाफ था. निगरानी कोषांग को पता चला कि बिजली बोर्ड ने कई प्रतिष्ठानों से ऐसी ही चोरी को लेकर टेंपर्ड मीटर जब्त किया था और बिजली चोरी के ठोस साक्ष्य भी मिले थे लेकिन बोर्ड की ओर से बिजली के इन चोरों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया जा सका था. जब दादीजी स्टील पर मामला दर्ज हुआ तो आनन-फानन में बिजली बोर्ड ने भी कईयों पर मामले दर्ज करा दिए लेकिन इतने दिन तक वह चुप्पी क्यों साधे रहा, इसे स्पष्ट नहीं किया जा सका. अलबत्ता यह जरूर हुआ कि तब के बिजली बोर्ड के अध्यक्ष स्वपन मुखर्जी ने एक रास्ता निकाला और यह घोषणा की कि जिन प्रतिष्ठानों या उपभोक्ताओं के मीटर टेंपर्ड हैं, वे स्वैच्छिक घोषणा करें. राज्य में उस समय करीब 28 लाख उपभोक्ता थे लेकिन 52 के करीब बड़े उपभोक्ताओं ने ही यह घोषणा की कि उनका मीटर टेंपर्ड है, बदला जाए. यहीं पर बड़ा खेला हुआ. जिन उपभोक्ताओं के टेंपर्ड मीटर जब्त किए गए थे, उन्होंने भी स्वैच्छिक घोषणा की, बहती गंगा में हाथ धोया और बोर्ड ने भी उन पर मेहरबानी की. जिस स्टील कंपनी के खिलाफ निगरानी कोषांग ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और जिसे तीन साल की सजा की संभावना के साथ 20 करोड़ के करीब जुर्माना भरना होता, उसने भी करीब दो माह बाद स्वैच्छिक घोषणा कर रास्ता निकाल लिया और मात्र एक करोड़ का जुर्माना भर मामले को रफा-दफा करवाने की कोशिश की लेकिन बात बड़ी थी. आनंद शंकर जैसे पुलिस अधिकारी सख्त छवि वाले थे, सो बात ऊपर तक पहुंची. महानिदेशक आनंद शंकर ने कई और बड़ी मछलियों को जाल में फांसना शुरू किया लेकिन तब तक उनका तबादला हो गया और इसके बाद 27 फरवरी 2009 को दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनोज नाथ को विद्युत निगरानी कोषांग का महानिदेशक बनाया गया. मनोज नाथ ने कमान संभालते ही स्वैच्छिक घोषणा की फाइलों की पड़ताल की और पाया कि बिजली बोर्ड के तब के अध्यक्ष स्वपन मुखर्जी ने स्वैच्छिक घोषणा की आखिरी तिथि पांच जुलाई 2008 की तय सीमा गुजर जाने के बाद भी स्वैच्छिक घोषणा को स्वीकारा है और बड़े खेल के रास्ते खोले हैं. साथ ही यह भी कि बिजली के जिन चोरों को चोरी के दौरान टेंपर्ड मीटर के साथ पकड़ा गया था, उन्हें भी स्वैच्छिक घोषणा का लाभ देकर राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ चोरों को खुली छुट भी दी गई. मनोज नाथ ने बोर्ड के अध्यक्ष पर केस किया. अध्यक्ष ने स्वीकारा भी कि दादीजी स्टील को स्वैच्छिक घोषणा का लाभ नहीं मिलना चाहिए था लेकिन इसी बीच 'आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास' वाला खेल हुआ. जिस रोज महानिदेशक मनोज नाथ ने केस दर्ज कराया, उसी रोज अध्यक्ष ने भी केस दर्ज करा दिया कि उनसे महानिदेशक मनोज नाथ ने बिजली बोर्ड परिसर में, जहां विद्युत निगरानी कोषांग महानिदेशक का कार्यालय है, सुसज्जित कार्यालय की मांग की और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया और फिर विद्वेषपूर्ण यह केस भी किया.

इससे मामले का रुख ही बदल गया. बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने बिजली चोरी के सार्वजनिक मामले को निजी दायरे में समेटने की कोशिश की. नतीजा यह हुआ कि पूर्व महानिदेशक आनंद शंकर द्वारा बिजली चोरी का मामला दर्ज करवाने और फिर बाद में महानिदेशक मनोज नाथ द्वारा स्वैच्छिक घोषणा के खेल से संबंधित मामला दर्ज करवाने का मामला अदालत में पहुंचा. पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 के तहत पुलिस को ऊर्जा चोरी से किया गया कदाचार दर्ज कराने का अधिकार ही नहीं है.

*– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर*

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया



# एक नज़र

## संकल्प यात्रा का स्वागत



आचार्य तुलसी जन्मशताब्दी के अवसर पर पूरे देश में निकली अणुव्रत संकल्प यात्रा पिछले दिनों फॉरबिसगंज पहुंची. यात्रा आचार्य महाश्रमण की शिष्या समणी निदेशिका ज्योतिप्रज्ञाजी एवं समणी मानसाप्रज्ञाजी के नेतृत्व में कोलकाता से पहुंची. इस संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत स्थानीय श्री हरिहरनाथ गौशाला परिसर के समीप जैन धर्मावलंबियों एवं शहर के सभी वर्गों के लोगों के द्वारा किया गया. समणी निदेशिका द्वय के साथ ब्रह्मकुमारी प्रजापिता ईश्वरीय पाठशाला की फॉरबिसगंज इकाई की संचालिका रुकमा दीदी ने पूरे शहरवासियों को इस शोभायात्रा के जरिए अहिंसा एवं नैतिकता का पालन करने का संदेश दिया. इस संकल्प यात्रा में आचार्य तुलसी एवं जैन धर्म से संबंधित वीडियो एवं ऑडियो से सुसज्जित रथ के जरिए लोगों को जागरूक किया गया. संकल्प यात्रा में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के सूरजमल घोषल, बछराज राखेचा, खेमचंद्र भंसाली, मूलचंद गोलछा, बच्छराज छाजेड़, महेन्द्र वैध, शांतिलाल चिंडालिया, निर्मल मरोठी, दीपक समदरिया, श्याम महेश्वरी, जयप्रकाश अग्रवाल, निवास गोयल, पप्पू डालमिया, विपुल छाजेड़, प्रदीप वैध, अशोक दुग्गड़, छोटू वैध, श्रीमती गुलाबचन्द सेठिया, सुखानी देवी, प्रभा सेठिया, विमला छाजेड़, इर्मिला जैन, प्रो. दिलीप अग्रवाल, बंटी राखेचा, जे.पी. घोड़ावत, जयकुमार अग्रवाल, सुशील अग्रवाल सहित हजारों की संख्या में महिलाएं एवं पुरूष शामिल थे. शोभा यात्रा का संचालन आलोक दुग्गड़ ने किया. समणी द्वय के द्वारा मिथिला पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें जीवन के गूढ़ महत्व को समझाया. विद्यालय के निदेशक विकास मिश्रा एवं विद्यालय के प्राचार्य पुतुल मिश्रा के नेतृत्व में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया.

*– अजातशत्रु अग्रवाल/संतोष झा*

## प्रतापपुर में मंत्री ने किया डैम का शिलान्यास



झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चतरा जिले का पहली बार दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रतापपुर प्रखंड में दो करोड़ की लागत से बनने वाले डैम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इस दौरान मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आमलोगों से रूबरू हुए. इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं विधायक हूं और हमारी पार्टी गरीबों, अल्पसंख्यकों, किसान और युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है. जनहित को देखते हुए ढुलकी और गोलाई जलाशय का जीर्णोद्धार अवश्य किया जाएगा. यह किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है. मैं किसान की बेटी हूं और हमें जल संसाधन विभाग का प्रभार मिला है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम अन्नपूर्णा है और मैं लोगों को अन्न अवश्य दूंगी. इस मौके पर हंटरगंज पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष शंभू यादव ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा. इस मौके पर मंत्री ने कहा कि एक दैनिक मजदूर से भी कम वेतन एक पारा शिक्षक को मिलता है जो कहीं से उचित नहीं है. मैं पारा शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव बना रही हूं. इस मौके पर आयोजित सभा को चतरा के विधायक जर्नादन पासवान, कृष्णा यादव, चंद्रदेव यादव, प्रो. जैनेन्द्र कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया. ■

*– अमरेन्द्र प्रताप सिंह*

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

जाड़े में सावधानी आवश्यक
ariskon Pharma Pvt.Ltd
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo - XT
AREX
ACOBA CAP/SYP/INJ
Carbo - XT
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma
[illegible]

पृष्ठ 17 का शेष

## बिहार में बिजली: क्या है हकीकत, क्या है फसाना!

हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, बिजली बोर्ड इसे सिर आंखों पर लेकर लौट गया और तब से बिजली चोरी के मामले में 1992 से बिहार में स्थापित विद्युत निगरानी कोषांग नख-दंतविहीन संस्था बनकर रह गई है. यह सवाल हाईकोर्ट के फैसले भर का नहीं था. जानकार बताते हैं कि न्यायालय को जो सबूत और साक्ष्य उपलब्ध कराए गये थे, उनके आधार पर फैसला सही है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार सरकार के ही नोटिफिकेशन से दो दशक पहले जिस विद्युत निगरानी कोषांग का संचालन शुरू हुआ था और जिसने दो दशकों में कई मामलों में केस किए, कई मामलों को उजागर किया और कई केसों को इसके जरिए एक अंजाम तक पहुंचाया जाना था, उसे अचानक से अधिकारविहीन करने के फैसले को सरकार ने स्वीकार कैसे कर लिया? राज्य सरकार और बिजली बोर्ड ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया?



जानकारों से जब इसकी तफ्तीश की गई तो यह जानकारी मिली कि इस फैसले से स्टील कंपनी के 20 करोड़ रुपये के जुर्माने वाला मामला तो ठंडे बस्ते में गया ही, जिन 52 उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक घोषणा का लाभ उठाया था तो उसमें दस ऐसे भी थे, जो आदतन बिजली चोर रहे थे और उनसे मोटा राजस्व वसूला जाना था. दो और [illegible]

करेंगी. इस सवाल को लेकर भागलपुर में बुनकर संगठित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में अपने साथ हुई वादाखिलाफी का हिसाब सरकार से चुकता करने के मूड में हैं. अरुण कहते हैं कि बिजली बिहार के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगी. यह बड़ी समस्या है और यह नवउदारवादी नीतियों का दुष्परिणाम है. यह समस्या निजीकरण से और गहरी होगी और कृषि व छोटे उद्योगों को सबसे अधिक प्रभावित करेगी. फिलहाल बिहार को 1800 मेगावाट बिजली केंद्रिय सेक्टर से मिलती है और 100 मेगावाट का उत्पादन मुजफ्फरपुर के कांटी से होता है. साथ ही 300 मेगावाट ये खरीदती है. सीपीएम नेता अरुण मिश्र कहते हैं कि काम तो हुआ है लेकिन ये जितना दावा कर रहे हैं उतना नहीं हुआ है. वे कहते हैं कि अगले पांच साल में पांच हजार मेगावाट का कंजप्शन आएगा और इनके पास जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक दोगुना करना होगा, जो संभव नहीं है. लेकिन बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव मुख्यमंत्री की ही बातों को दोहराते हैं. वे कहते हैं मुख्यमंत्री के किए गए वादे को 2015 तक पूरा कर दिया जाएगा. इस दिशा में पहला कदम बढ़ गया है और साल के अंत तक सभी जिले के मुख्यालय को अबाधित बिजली मिल जाएगी और गांवों को भी दस से बारह घंटे बिजली मिलने लगेगी. बिजेंद्र कहते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस पिछले साल जहां 53.9 प्रतिशत था वहीं इस साल यह 42 प्रतिशत हो गया है. वे उम्मीद जताते हैं कि दो बिजली आपूर्ती कंपनियां फिलहाल 2,314 मेगावाट बिजली दे रही है. जून तक यह आंकड़ा तीन हजार मेगावाट का हो जाएगा. बताते चलें कि रीडिंग और बिलिंग का मामला बिहार में फ्रेंचाइजी के हाथों [illegible]

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
[illegible]
विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें
9304291051
किसी भी रोग संबंधी निदान के लिए Dr. Advice पुस्तिका (होमियोपैथिक) निकटतम स्टॉकिस्ट से मुफ्त प्राप्त करें!
REPL द्वारा जनहित में प्रकाशित

## लोकसभा में युवा ही होंगे तारणहार

मनेंद्र कुमार/नंदकिशोर शर्मा



मुल्कराज आनंद
मनोहर कुमार यादव
चन्द्रमुखी देवी
डॉ. विवेकानन्द

लोकसभा चुनाव को लेकर जिले की राजनीति में रोज नए जोड़-घटाव शुरू हो गए हैं. कई नए दलों का जन्म हो गया है तो कई नए चेहरे टिकट पाने की फिराक में लगे हुए हैं. इन दिनों जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि क्या पार्टियां पुराने दिग्गजों पर ही भरोसा करेंगी या फिर नए लोगों को भी मौका दे पाएंगी. इसी बीच में पार्टियां खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का आधार सहरसा जिले के सिमरीबख्तियारपुर एवं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा के मतदाताओं की नब्ज को भी टटोलने में लगी हुई हैं. वहीं कई नए चेहरे अपनी-अपनी पार्टी से टिकट झटकने के प्रयास में हैं.

गौरतलब है कि खगड़िया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें जिले के अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता हैं. यहां यादवों की अच्छी खासी संख्या है. लेकिन यदि माय समीकरण इस बार कारगर सिद्ध होता है तो राजद की नैया पार हो सकती है. लेकिन यदि किसी पार्टी ने मुस्लिम को प्रत्याशी बना दिया तो तीसरे नए प्रत्याशी का भी उदय हो सकता है. वैसे नदियों का मायका कहा जाने वाले खगड़िया में अति पिछड़े समुदायों के लोगों की भी संख्या प्रभावी है. वहीं उक्त समुदायों के लोगों के बीच किसी भी दल के द्वारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण खासी नाराजगी देखी जा रही है. जानकारों का मानना है कि आखिर में इस समुदाय के लोगों का रुझान जिस दल की ओर होगा, उसी की जीत सुनिश्चित है. बीते चुनाव में जदयू के दिनेश चंद्र यादव यहां से सांसद चुने गए. यादव राजग गठबंधन के उम्मीदवार थे लेकिन अलगाव के बाद से यह माना जा रहा है कि अब इस सीट को निकाल पाना जदयू के लिए आसान नहीं है. वजह यह है कि इनदिनों जिला जदयू आंतरिक कलह से जूझ रहा है. सत्ताधारी जदयू के निशाने पर जहां साथ रही भाजपा है, वहीं राजद, कांग्रेस, लोजपा के निशाने पर सूबे की सरकार है. इतना ही नहीं राजनीतिक तीरंदाजी के बीच सभी दल प्रदेश नेतृत्व के फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं कि कौन पार्टी किसके साथ मिलकर चुनावी अखाड़े में ताल ठोकेगी. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी के द्वारा कुशवाहा समुदाय से उम्मीदवार बनाने की चर्चा राजनीतिक गलियारे में की जा रही है.

यदि इस पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा गया तो कई दलों का समीकरण बिगड़ जाएगा. इस पार्टी के सांस्कृतिक कला मंच के प्रदेश अध्यक्ष मुल्कराज आनंद के नाम की भी चर्चा है. उनके समर्थकों का कहना है कि यदि लोकसभा का उम्मीदवार वे होते हैं तो किसी भी प्रत्याशी के लिये परेशानी खड़ी हो जाएगी. आनंद हाल के वर्षों में क्षेत्र के सरोकार को लेकर काफी संघर्षरत रहे हैं. वहीं जिले के कांग्रेसियों का भी कहना है कि इस बार युवा को ही मौका मिलने जा रहा है. नगर सभापति मनोहर कुमार यादव को यदि कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो क्षेत्र में उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए लोकसभा चुनाव काफी संघर्षमय होगा. नगर परिषद के सभापति के रूप में किए गए उनके कार्यों की सराहना आज भी होती है. यह भी माना जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में महबूब अली कैसर की वजह से ही राजद के उम्मीदवार की जीत नहीं हो सकी थी. कहा जाता है कि कैसर की अपनी बिरादरी पर अच्छी पकड़ है. फिलहाल तो मनोहर यादव के द्वारा दावेदारी प्रस्तुत करने से बड़े-बड़े धनबली-बाहुबली के होश उड़ने प्रारंभ हो गए हैं.

भाजपा की बात की जाए तो उसके पास उम्मीदवारों की लंबी फेहरिस्त है. नरेंद्र मोदी की लहर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में भी हावी है. नमो की लहर में दमदार उम्मीदवार दिए जाने की चर्चा है. भाजपा किसको टिकट देकर भाग्य चमकाने का मौका देती है यह तो अन्तिम समय में तय होगा. वैसे खगड़िया विधानसभा की पूर्व विधायक चन्द्रमुखी देवी भी अन्दर ही अन्दर टिकट के प्रयास में लगी हुई हैं. वहीं जातीय समीकरण की बात की जाए तो चन्द्रमुखी देवी वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और खगड़िया लोकसभा में वैश्य मतदाता 3 लाख से भी अधिक हैं. यही वजह है कि उनकी दावेदारी अबतक प्रबल मानी जा रही है. वहीं स्वर्ण लोगों का कहना है कि यदि वैश्य समाज से सुयोग्य व कर्मठ उम्मीदवार होता है तो हम लोग भी उन्हीं को मदद करेंगे. खगड़िया जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने वाले तथा शहीद प्रभु नारायण मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पीटल के निदेशक डा.विवेकानन्द ने आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी पेश की है. उन्होंने दावेदारी पेश करते हुए कहा है कि मैंने अपना आवेदन पार्टी मुख्यालय को भेज दिया है जिसमें आवेदन के साथ-साथ आम जनता का हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव संलग्न है. पार्टी के प्रावधान के तहत 14 जनवरी से हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर दिया गया है और 15 फरवरी तक करीब एक लाख लोगों का हस्ताक्षर पार्टी मुख्यालय को भेज दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ अपनी सम्पत्ति का भी ब्यौरा भेज दिया है. वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं. कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सभी दलों ने अपने-अपने मजबूत चुनावी खेवनहार के जरिए खगड़िया लोकसभा सीट पर अपना-अपना कब्जा जमाने के लिए एड़ी-चोटी एक कर दिया है. बावजूद इसके सभी दल के जिलास्तरीय नेता अपने-अपने आकाओं के निर्देश पर जिले से पंचायत स्तर पर कमर कसकर तैयारी में जुट गए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

## दलित-अल्पसंख्यक छात्रों के हितों की अनदेखी

इन्तेजारुल हक

चम्पारण के बदहाल व जर्जर छात्रावासों के मुद्दे पर प्रशासनिक पदाधिकारी व राज-नेता खामोश क्यों हैं और इसे ठीक करने की चिंता किसी को क्यों नहीं होती? क्या चम्पारण के छात्रों को अब छात्रावास की जरूरत नहीं है या सरकार व विभाग की कोई और मजबूरी है? इस मुद्दे पर इन दिनों लम्बी बहस होने लगी है. साथ ही सरकार व विभागीय अधिकारियों के इस उदासीन रवैये पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

छात्रों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने व उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से चम्पारण के विभिन्न प्रखंडों में वर्षों पूर्व एक दर्जन अनुसूचित जाति के युवकों के लिए छात्रावास और अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाए गए थे. आज ये सारे छात्रावास अपनी बदहाली पर रो रहे हैं. इन छात्रावासों को देखकर लगता है कि ये कभी भी अपना वजूद खो सकते हैं. उक्त छात्रावासों के जर्जर भवन व उनकी बदहाली की चिंता न तो सरकार को है और न ही विभागीय अधिकारियों को. ऐसा कहा जाने लगा है कि सुशासन की सरकार अनुसूचित जाति को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है और शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाती है किन्तु उक्त छात्रावासों की बेहतरी के लिए आजतक कोई कदम नहीं उठाया गया है. जानकार बताते हैं कि पूर्वी चम्पारण जिले में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 13 छात्रावास हैं, लेकिन मात्र दो ही चालू हैं. 11 छात्रावासों के भवन करीब दस वर्षों से जर्जर हैं. इस कारण वे बंद है और वहां छात्र नहीं रहते. मोतिहारी नगर के चांदमारी मुहल्ले में स्थित दो छात्रावासों में ही छात्र रहते हैं किन्तु वहां भी संसाधनों का घोर अभाव है और उक्त दोनों छात्रावासों में रह कर अपनी पढ़ाई करने वाले छात्रों को अनेक तरह की समस्याओं से प्रतिदिन जूझना पड़ता है.

पूर्वी चम्पारण के अरेराज में स्थित सोमेश्वरनाथ हाई स्कूल, आदापुर मध्य विद्यालय, रामगढ़वा मध्य विद्यालय, घोड़ासहन में स्थित जेएलएनएस कालेज, मेहसी में स्थित तिरहुत उच्च विद्यालय, ढाका में स्थित उच्च विद्यालय, पकड़ीदयाल के चैता में स्थित जयमंगल हाई स्कूल, पताही में स्थित सिंघेश्वर हाई स्कूल, चिरैया में स्थित महादेव साह हाई स्कूल, चकिया में स्थित एसआरएपी कालेज व जहीरंगा में स्थित विद्यालय में अनुसूचित जाति छात्रावास वर्षों पूर्व बनाए गए थे जो आज सरकार की उपेक्षा के कारण दम तोड़ चुके हैं. इन छात्रावासों में 25-25 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी. जानकार बताते हैं कि उक्त छात्रावासों का भवन जर्जर होता चला गया और भवन के ध्वस्त होने के बाद उक्त छात्रावासों के जीर्णोद्धार कराने की दिशा में विभागीय स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. सरकार व विभाग नए छात्रावासों के निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति तो दे रही है और नए-नए छात्रावास बन रहे हैं किन्तु इन बदहाल छात्रावासों की चिंता नहीं कर रही है. स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी शिकायतें समय-



जर्जर छात्रावास

समय पर की जाती रहीं किन्तु नतीजा शून्य रहा. बताते चलें कि पूर्वी चम्पारण के ग्यारह प्रखण्डों में अनुसूचित जाति के लोगों में शिक्षा की अलख जगाने व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उक्त छात्रावास बनाए गए थे. यही स्थिति जिला मुख्यालय के एनएच 28 पर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास की है. यहां रह कर अपनी पढ़ाई करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है. यहां भी संसाधनों का घोर अभाव है और अधिकारी सबकुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं. कहने के लिए यहां विशाल भवन तो है किन्तु इसकी देखभाल नहीं हो रही है. इधर राजद के प्रदेश महसचिव डा. शमीम अहमद, जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, राजद महिला सेल की जिलाध्यक्ष नसीमा खातुन व पूर्व विधान पार्षद रामजी शर्मा आदि लोगों ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया. इनलोगों का कहना है कि एक साजिश के तहत अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

# सीतामढ़ी : महिला शिक्षा पर लग रहा ग्रहण

**सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा में महिला शिक्षा के विकास को लेकर तकरीबन साढ़े चार दशक पूर्व राम सेवक सिंह महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई. बिहार विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई के रूप में कॉलेज में शिक्षण कार्य शुरू हुआ. स्थापना के समय में जहां कुल 15 विषयों में पढ़ाई को लेकर 26 प्राध्यापकों का पद सृजित किया गया. वहीं वर्तमान में उक्त कॉलेज में प्राचार्य समेत महज आधा दर्जन प्राध्यापक ही रह गए हैं. ऐसे में राज्य सरकार की महिला शिक्षा के प्रति सजगता महज एक छलावा साबित होकर रह गई है...**

वाल्मीकि कुमार

सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति समेत अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए सूबे की सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है. शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरूकता लाने के लिहाज से सरकार ने मुख्यमंत्री साइकिल व पोशाक समेत अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन कराने में लगी है लेकिन महिलाओं के लिए उक्त योजना महज चंद कदमों की हम सफर ही साबित हो रही है. इसका कारण है कि इंटर से लेकर स्नातक व



छात्रावास में संचालित कार्यालय

उससे ऊपर की शिक्षा भगवान भरोसे ही है. वैसे तो लंबे अरसे से कॉलेजों में प्राध्यापकों की बहाली नहीं किए जाने के कारण अधिकांश पद रिक्त पड़े है लेकिन जो बचे भी हैं, उनका कॉलेज नौकरी से सेवा निवृत्त होने के समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. ऐसे हालात में अन्य कॉलेजों के समान महिला कॉलेज में भी फॉर्म भर कर परीक्षा में शामिल होने एवं प्रमाण पत्र लेने भर से ही मतलब रह गया है. अगर हालात ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में सीतामढ़ी की किसी भी महिला को कहीं भी समुचित शैक्षणिक सम्मान शायद ही मिल पाएगा. राज्य सरकार भले ही वोट की राजनीति की खातिर चाहे जितनी भी आरक्षण व सीट सुरक्षित कर दे, लेकिन इस बात में तनिक भी संकोच नहीं है कि महिला पर लगा अनपढ़ का कलंक उसकी जान नहीं छोड़ेगा. वर्ष 1968 में सीतामढ़ी के डुमरा में स्थापित राम सेवक सिंह महिला कॉलेज इस तथ्य का जीवंत उदाहरण बना है. करीब डेढ़ दशक पूर्व तक छात्राओं की चहल कदमी से गुलजार रहने वाले कॉलेज परिसर में अब अजीब सी वीरानी छायी रहती है. छात्राओं के लिए निर्मित जानकी छात्रावास का कमरा भी अब कॉलेज के कार्यालय संबंधी कार्य में उपयोग किया जाने लगा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज में पढ़ाई के लिए 15 विषयों की स्वीकृति प्रदान की गई थी. इनमें हिंदी में 3, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र व जीवविज्ञान में 2-2, अर्थशास्त्र, तर्क शास्त्र, संस्कृत, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित व वनस्पति विषय में 1-1 प्राध्यापक का पद स्वीकृत किया गया था. इसके अलावा मनोविज्ञान व गृह विज्ञान में भी 4-4 प्राध्यापकों की स्वीकृति मिली थी. लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, संस्कृत, रसायन शास्त्र, गृह विज्ञान व मनोविज्ञान में वर्षों से एक भी प्राध्यापक नहीं है. शेष प्राध्यापकों की संख्या का यह हाल है कि इतिहास, अर्थ शास्त्र, भौतिकी, गणित, जीवविज्ञान व वनस्पति में महज 1-1 प्राध्यापक बच गए हैं. इनमें वनस्पति की प्राचार्य भी शामिल हैं. दूसरी ओर गैर शिक्षण कार्य करने वाले कर्मियों का हाल भी बेहाल है. मजे की बात तो यह है कि कॉलेज में ढाई दर्जन ऐसे कर्मी भी कार्यरत हैं जो पिछले 32 साल से सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद में है. अब तक इन कर्मियों को नियमित भी नहीं किया जा सका है. कुल मिलाकर सीतामढ़ी जिले में महिलाओं के उच्च शिक्षा का एक मात्र केंद्र राम सेवक सिंह महिला कॉलेज का यही हाल है. सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि विभिन्न योजनाओं के तहत कॉलेज परिसर में भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. लेकिन पूर्व से निर्मित भवनों का रंग रोगन व मरम्मत वर्षों से नहीं हो रहा है. जनप्रतिनिधियों की सजगता का आलम है कि निर्माण कार्यों में भागीदारी देकर स्थानीय मीडिया की सुर्खियों में तो आते हैं, लेकिन कॉलेज में शिक्षण कार्य को गति दिलाने को लेकर कोई पहल करने से परहेज करते रहे हैं. नतीजा है कि अब महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र महज एक दिखावा बन कर रह गया है. अन्य कॉलेजों की तरह इस कॉलेज की छात्राओं का नेतृत्व कोई करने वाला संगठन नहीं है. कुछ संगठनों की नींव डालने की कवायद हाल के सालों में की गई थी जो केवल अखबारों की सुर्खियों तक ही सिमटा रहा. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव का समय आने के साथ ही एक बार फिर शहर व गांव की गलियों तक में शिक्षा के सर्वांगीण विकास की घोषणाएं गूंजने लगी हैं. लेकिन वह साइकिल व पोशाक राशि के वितरण से ऊपर भी उठेगा अथवा नहीं. इसका जवाब शायद ही कोई दे सके. फिलहाल जिले में महिलाओं को कॉलेज की पढ़ाई में हो रही परेशानी चर्चा का विषय बनी हुई है. महिला शिक्षा के विकास पर लग रहा ग्रहण छट पाएगा, इसकी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है. जहां तक जनप्रतिनिधियों की सजगता का सवाल है तो सभी के लिए पार्टी का मिशन 2014 ही सर्वोपरि बना है. जनता की परेशानी उनके मिशन में अभी भी अपना स्थान नहीं बना पा रही है. वैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी वोट मांगने वालों को शहर से लेकर गांव की गलियों तक कॉलेज की दुर्गति का जवाब मांगने को छात्र-छात्राएं तैयार होने लगे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई
फर्नीचर का संसार
WOODLAND ग्रुप
स्टील फाईवर एवं लकड़ी फर्नीचर का अनोखा संगम
नोट : गिट्टी, बालू, छड़, सिमेंट, नीलकमल ब्राण्डेड फर्नीचर के आपूर्तिकर्त्ता एवं विक्रेता
गोशाला रोड, खगड़िया
Ph.: 06244-222522, 9431231703, 9431010123

गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं
निवेदक
डॉ. विद्यानंद दास
अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला परिषद
सह सचिव, आर्य कन्या उच्च विद्यालय, खगड़िया

चौथी दुनिया के पाठकों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
रजनीश कुमार (मुन्ना सर्राफ)
जनता दल युनाइटेड, विपिन बिहारी वर्मा मार्ग, नरकटियागंज, प.चम्पारण पिन कोड 845455

समस्त झारखंडवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
दीपा भारती — प्रमुख, हंटरगंज चतरा
एस. सोरेन — रेंजर, उत्तरी वन प्रमंडल, हंटरगंज, चतरा
किशोर कुमार — प्रधानाध्यापक, उ.म.वि., अकौना-हंटरगंज
उमेश तिवारी — प्रधानाध्यापक, उ.उच्च.विद्यालय धरधारा हंटरगंज
महादेव उरांव — सांख्यिकी पदाधिकारी-हंटरगंज
रेणु देवी मुखिया — पंचायत, पाण्डेयपुरा खुर्द-हंटरगंज
विनोद कुमार सिन्हा पंचायत सचिव, करमा पंचायत हंटरगंज, चतरा
भोला प्रसाद (प्रतिनिधि) पूर्व विधायक प्रतापपुर-चतरा
रीना देवी मुखिया — प्रतापपुर पंचायत, चतरा
मो. जमील अंसारी मुखिया — मीरपुर पंचायत, हंटरगंज (चतरा)
कालो देवी मुखिया — पंचायत-पनारी नावाडीह, हंटरगंज (चतरा)
सहेन्द्र राम — चतरा विधानसभा-कांग्रेस प्रत्याशी
विपिन कुमार सिंह अध्यक्ष — शिक्षक संघ, हंटरगंज-चतरा
शंभु यादव अध्यक्ष — पारा टीचर संघ हंटरगंज-चतरा
चन्द्रदेव यादव मुखिया — पंचायत-डाहा-हंटरगंज, चतरा

समस्त झारखण्ड-बिहारवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई
केवल कृष्ण अग्रवाल — बी.डी.ओ. सह सी.ओ. हंटरगंज (चतरा)
अरुण कुमार सिंह — उप प्रमुख हंटरगंज चतरा
डॉ. सत्येन्द्र प्रसाद सिंह — सिविल सर्जन चतरा
सनोज सिंह — समाजसेवी हंटरगंज चतरा
मुकेश कुमार सिन्हा — जिला शिक्षा पदाधिकारी चतरा
इंदू देवी — प्रमुख- प्रतापपुर, प्रखंड-चतरा
ममता देवी — अध्यक्षा जिला परिषद चतरा
देवनन्दन साहु — जिला परिषद उपाध्यक्ष, चतरा
दुर्गा शंकर सिंह — लोकसभा उम्मीदवार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता
सतीश चन्द्रा — अनुमंडलाधिकारी चतरा
बहाजुल हक — उपाध्यक्ष नगर पार्षद, चतरा
यमुना साव — अध्यक्ष नगर पार्षद, चतरा
जहूर आलम — बी.डी.ओ- प्रतापपुर चतरा
श्यामाकान्त सिंह — वरिष्ठ भाजपा नेता हंटरगंज, चतरा

# झाविमो ने चलाया धनसंग्रह अभियान

मंगलानंद मिश्र

झारखंड के ईमानदार नेताओं में से एक पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व वाली झारखंड विकास मोर्चा पार्टी धन की कमी से जूझ रही है. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धन संग्रह के साथ जनमत का भी संग्रह कर रहे हैं. रांची के रातू रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की. इस मौके पर मरांडी ने कहा कि मिशन 2014 में 14 सीटों पर पार्टी को विजयी बनाना है. आम लोगों के सहयोग से पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी. वे भय दिखाकर या कॉरपोरेट घरानों से पैसे लेकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वे जनता के सहयोग से इस मिशन को पूर करना चाहते हैं. श्री मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी काफी मजबूत है और पंचायत स्तर तक उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं. पार्टी में तीन तरह से लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं. एक वो जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, दूसरा पार्टी समर्थक और तीसरे सहयोगी. पार्टी में सभी वर्गों के लोग जुड़े हैं और इतने बड़े समूह के साथ बड़ा लक्ष्य उन्हें हासिल करना है. उन्होंने कहा कि राज्य में जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस, आजसू आदि सभी दलों ने शासन किया. जनता ने सबको देखा अब एक बार उनकी पार्टी के शासन को भी देख लें. बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य की रेल परियोजना के लिए वे तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से फंड मांगने गए थे, यशवंत सिन्हा ने इसमें आनाकानी दिखाई थी. राज्य में पीजीआइसीएल सहित दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसके दम पर वो कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है. कार्यक्रम में पार्टी महासचिव व लोकसभा प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद, लोकसभा प्रभारी अजय नाथ शाहदेव, महानगर अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा, उत्तम यादव, सुनिल बरियार, सुनिल गुप्ता, जीतेंद्र वर्मा, इंदू भूषण गुप्ता, दिलीप गुप्ता, संजय चौधरी, मंतोष सिंह, कमलेश यादव, आशीष गोप, अब्दुल कादिर, संतोष जायसवाल, नदीम इकबाल, कन्हैया महतो, संजय पांडे, मुन्ना आलम, गोविंदा पासवान, राजू वर्मा, आनंद भगत, मुकेश अग्रवाल, मुन्ना सिंह, नंदकिशोर सिंह, आकाश सिंह, नौशाद अंसारी, अमित सिंह, राजू साव, गुक्कू यादव, अंकित साव सहित कई लोग मौजूद थे. इधर, पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी खुद इस अभियान के लिए निकले. रातू रोड में चलाए गए इस अभियान में केवल व्यवसायी संघ ने 11 हजार रुपये, युवा मोर्चा के केंद्रीय सचिव उज्जवल शाहदेव व सिद्धेश्वर सिंह ने 5 हजार, सुबोध प्रसाद, दिनकर शहदेव ने एक-एक हजार व पूर्व डीएसपी व एथलीट बुधवा उरांव ने भी एक हजार रुपये का सहयोग पार्टी को दिया. बाबूलाल मरांडी ने बातचीत में बताया कि वे पिछले दिनों देवघर व दुमका के कार्यक्रम में शामिल होकर आए हैं. देवघर में 100 रिक्शा चालकों ने सहयोग दिया है. कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है और बढ़ चढ़ कर लोग सहयोग कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

03 फरवरी–09 फरवरी 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

## उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

### यूपी में फ्रंट पर दिखेंगे राहुल

# प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति का भी बने हिस्सा

**राहुल गांधी के 'मिशन 2014' में यूपी की कमान संभालने से यहां हालात काफी बदल सकते हैं. बड़े कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों की कार्यशैली से आम कार्यकर्ता नाराज चल रहा है. इस पर राहुल की पैनी नजर रहेगी. उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा खींची है, उसके दायरे में पार्टी के कई बड़े नेता आ सकते हैं. पिछले पांच वर्षों में यूपी में कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हुई है. ऐसे में लोकसभा चुनाव–2014 में यूपी में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए राहुल फ्रंट पर मोर्चा संभालेंगे.**

अजय कुमार

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी टीम ने ऐन मौके पर भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते–करते 2014 लोकसभा चुनाव प्रभारी बना कर ही छोड़ दिया. ठीक वैसे ही जैसे की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते–करते कांग्रेस रुक गई थी, जबकि यूपी चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. कांग्रेस के इस निर्णय के पीछे उत्तर प्रदेश को बड़ी वजह बताया जा रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो राहुल गांधी को 2014 लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाने के सवाल पर यहां तक कह दिया कि यह अंतिम फैसला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं. कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी का यहां से वर्षों पुराना नाता है. सोनिया लखनऊ मंडल के जिले रायबरेली से तो फैजाबाद मंडल के जिला अमेठी से राहुल सांसद हैं, लेकिन न तो सूबे की तमाम सरकारें और न ही यूपी कांग्रेस कभी इस बात का फायदा उठा पाई. इसकी तमाम वजहें हैं. इसके अलावा सच्चाई यह भी है कि चुनावी मौकों को छोड़कर कांग्रेस के दोनों ही रहनुमाओं ने अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर निकलने की कभी कोई गंभीर कोशिश नहीं की, जबकि कई मौकों पर देखने में यह आया कि सपा–बसपा की जातिवादी और भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति से आजिज आ चुकी यूपी की जनता उन्हें हाथों–हाथ लेना चाहती थी. इस बात का एहसास 2009 में जनता ने कांग्रेस को करा भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अपनी

तस्वीर और तकदीर नहीं बदल पाई. 2009 के लोकसभा चुनाव पर अगर एक नजर डाली जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में ठीक–ठाक (22) सीटें हासिल की थी. यूपी की 22 सीटों के बदौलत ही कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने की हैसियत में आ पाई थी. इस 'चमत्कार' का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया था. चमत्कार शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस समय भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज की तरह ही मरणासन्न स्थिति में थी. कांग्रेस के युवराज ने पार्टी को अपने बल पर जीत तो दिला दी थी, लेकिन तब भी वह संगठन में कोई जान नहीं फूंक पाए थे और अब भी यही स्थिति बरकरार है. इसके अलावा कांग्रेस के साथ कुछ और बुरा हुआ तो वह था 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिरना. उत्तर प्रदेश में 2009 में राहुल अपने भावुक 'फेस' और बातों के सहारे कांग्रेस की नैया पार करा ले गए थे, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश यादव ने उनको ऐसी पटकनी दी कि उनकी राजनीति की धारा ही बदल गई. राहुल अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों को ही नहीं बचा पाए, पूरा प्रदेश जीतना तो दूर की बात थी. बात तुलनात्मक तौर पर की जाए तो 2009 के लोकसभा चुनाव मे उत्तर प्रदेश की 80 में से 22 सीटें जीतने वाली कांग्रेस की सफलता 26 प्रतिशत रही थी, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों में से मात्र 29 सीटें यानी सात फीसद सीटें ही जीत सकी थी. 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 22 सीटें तब जीती थीं, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में इसे 403 सीटों में से मात्र 21 सीटें ही मिली थीं. 2009 और 2012 में राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे. 2012 के विधानसभा चुनाव में राहुल की नाकामयाबी का प्रभाव न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश पर पड़ा. उनके ऊपर तमाम तोहमतें लगने लगीं. कोई कहता कि वह (राहुल) अच्छे वक्ता नहीं हैं? किसी को लगता कि राहुल को राजनीति से लगाव ही नहीं है? लोग उन्हें इस बात पर घेरते हैं कि वह मीडिया से बचते हैं? संसद में उनकी उपस्थिति कम रहती है? बहस में वह हिस्सा नहीं लेते हैं? खास मौकों पर वह गायब हो जाते हैं? जैसा की उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के दौरान देखने को मिला. जनता यहां त्राहिमाम कर रही थी और वह विदेश भ्रमण कर रहे थे. जब काफी हायतौबा मची तो उनको वापस आना पड़ा.

खैर, बात उत्तर प्रदेश की ही आगे बढ़ाई जाए तो पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और ज्यादा कमजोर हुई है. राहुल का सिक्का चल नहीं रहा है. इसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हीं पर विश्वास जताते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव समिति की कमान सौंपी है. हाल में ही लोकसभा चुनाव 2014 के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर की चुनाव समितियों का गठन किया, मगर अपने राज्य (यूपी) की कमान राहुल ने खुद अपने पास रखी. वह खुद प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति में शामिल हुए हैं. 17 जनवरी, 2014 को उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव मधुसूदन मिस्त्री की ओर से जारी चुनाव समिति में राहुल का नाम सबसे ऊपर था. राहुल ने अपना नाम इसलिए आगे किया है, क्योंकि वह प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी दूर करने के साथ ही टिकट बांटने में भी पारदर्शिता लाना चाहते हैं. कांग्रेस कैसे यूपी की चुनौती से निपटती है, यह यक्ष प्रश्न होगा. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने पहले ही यूपी में कांग्रेस के खिलाफ धूम मचा रखी थी. रही–सही कसर आम आदमी पार्टी (आप) जैसे नये–नवेले राजनीतिक दल ने पूरी कर दी है. इसके प्रतिनिधि उनको (राहुल) उनके ही संसदीय क्षेत्र में चुनावी चुनौती देने पहुंच गए हैं. मुश्किल राजनीतिक हालातों के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी 'सदमे' में हैं. कहा तो यहां तक जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस की कमजोर स्थिति के कारण राहुल को प्रत्यक्ष रूप से फ्रंट पर नहीं किया गया है. राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं पेश किए जाने को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता यूपी का हवाला खुलेआम दे रहे हैं.

कांग्रेस के भीतरखाने में चर्चा है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी आज की तरह ही काफी सक्रिय हुए थे. इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं था. कुछ उत्साही कांग्रेसी चाहते थे कि कोई विकल्प नहीं होने के कारण राहुल गांधी को भावी सीएम के रूप में पेश किया जाए. राहुल ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के माध्यम से जो समां बांधा था, उससे लगता भी था कि 2009 के लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी राहुल का जलवा कायम रहेगा. तब उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने का दावा करने वाले तर्क दे रहे थे कि राहुल गांधी यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उन्हें प्रशासनिक अनुभव तो मिलेगा ही, स्वाभाविक रूप से 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो जाएंगे, लेकिन आलाकमान इससे बचता रहा. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी के थिंक टैंक ने अपनी पीठ थपथपाई और ऊपरवाले का शुक्रिया अदा किया कि समय रहते उनको सद्बुद्धि आ गई, वर्ना सारा खेल बिगड़ जाता.

बहरहाल, बात राहुल गांधी के 'मिशन 2014' कि की जाए तो उनके यूपी की कमान संभालने से यहां हालात काफी बदल सकते हैं. बड़े कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों की कार्यशैली से आम कार्यकर्ता नाराज चल रहा है. इस पर राहुल की पैनी नजर रहेगी. उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा खींची है, उसके दायरे में पार्टी के कई बड़े नेता आ सकते हैं. सभी मौजूदा सांसदों को आलाकमान को तथ्यों के साथ इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि उनकी जीत में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी. पार्टी पहले ही यह तय कर चुकी है कि दो बार चुनाव हार चुके नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा. कुछ बाहरी जिताऊ नेता भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं. सपा सांसद जयाप्रदा का कांग्रेस के टिकट से रामपुर का प्रत्याशी बनना तय माना जा रहा है. रामपुर से पिछले दो लोकसभा चुनाव हार चुकीं पूर्व सांसद बेगम नूरबानों को इस बार रामपुर की जगह मुरादाबाद से चुनाव लड़ाया जा सकता है. मुरादाबाद के मौजूदा कांग्रेस सांसद और क्रिकेटर अजहरूद्दीन इस बार मुंबई से मैदान में कूद सकते हैं. अजहरूद्दीन से मुरादाबाद की जनता नाखुश चल रही है. महाराजगंज भी कांग्रेसी सांसद हर्षवर्धन सिंह के लिए इस बार राह आसान नहीं लग रही है. पिछले पांच वर्षों में जनता का इस पर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है. यही समस्या बहराइच के सांसद कमल किशोर कमांडो के साथ है. वह बांसगांव से इस बार मैदान में उतरना चाहते हैं. ■


feedback@chauthiduniya.com


# वि.वि. में स्वायत्तता कड़ाई से लागू हो : राज्यपाल

रवि प्रकाश

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी.एल. जोशी ने राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार परीक्षा सम्पन्न कराने एवं परिणाम घोषित करने पर बल दिया है. विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता की दृष्टि से विभिन्न प्रशासनिक, एकेडमिक, और वित्तीय कार्यों के लिए समितियों की जो व्यवस्था है, उसे कड़ाई से लागू रखने एवं नियमित रूप से संचालित करने पर बल दिया. उन्होंने यह चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि हालांकि पहले से सुधार हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल समय से घोषित हों, बच्चों को डिग्रियां मिलें, यह विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की आधारभूत जिम्मेदारियां हैं. विश्वविद्यालयों में यदि कोई कमियां प्रकाश में आती हैं तो इस दृष्टि से कार्रवाई करके वित्तीय एवं एकेडमिक, प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखा जाए.

राज्यपाल लखनऊ के योजना भवन में दो दिवसीय राज्य विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अपने विचार रख रहे थे. श्री जोशी ने कहा कि सम्मेलन में विचार–विमर्श के उपरान्त कई सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, जिन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए उनके स्तर से भी गम्भीरता से प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को मूल्यांकन के सम्बन्ध में गम्भीरता से काम करने का निर्देश दिया, क्योंकि मूल्यांकन के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालयों को कई प्रकार के अनुदान प्राप्त होते हैं. उन्होंने रैगिंग को कड़ाई से रोकने और शोध के स्तर को बढ़ाने पर भी बल दिया.

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या में नौजवानों की संख्या अधिक है. यह खुशी की बात है. इतनी बड़ी युवा शक्ति के समुचित उपयोग की योजना बनानी चाहिए. इस युवा जनशक्ति के सभी वर्गों को उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि यही सच्चा समाजवाद है, जिसे आजकल की भाषा में समग्र विकास कहा जाता है.

श्री यादव ने प्रदेश में एक डिजाइन विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाएं प्रदेश के विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं. उन्होंने दुग्ध विकास के क्षेत्र में राज्य की योजनाओं की लोकप्रियता की चर्चा करते हुए यह अपेक्षा की कि इस क्षेत्र में दक्ष शिक्षित युवक विकास की गति को और तेज करने में सहभागी बनेंगे. उन्होंने विभिन्न जिलों के स्थानीय उद्योगों, शिल्पों, हस्तकलाओं और उद्योगों को चिन्हित करते हुए उन्हें सुदृढ़ करने के लिए सम्यक दृष्टि से आवश्यक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में चलाए जाने पर बल दिया.

सम्मेलन में विभिन्न कुलपतियों द्वारा कुलसचिवों, वित्त अधिकारियों एवं परीक्षा नियंत्रकों की व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय में किए जाने तथा कुलसचिवों के कैडर को रिव्यू करके इसे सुदृढ़ किए जाने पर आम सहमति हुई. विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय, एकेडमिक तथा सम्बद्धता संबंधी कार्यों को करने के लिए ई–इनीशिएटिव लेते हुए पारदर्शी एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था लागू करने पर भी सहमति व्यक्त की गई तथा शासन स्तर से समन्वय करने का अनुरोध किया गया.

सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि एकेडमिक सुधार की दृष्टि से पाठ्यक्रमों को प्रत्येक वर्ष परिवर्धित किया जाए. शोध की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सॉट स्किल्स व अन्य रोजगारपरक विषयों को सम्मिलित किया जाए, जिसके लिए विश्वविद्यालयों की एकेडमिक काउंसिल विचार करके फैसला लेगी. इससे पूर्व राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा क्रमशः विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं से अवगत कराया गया. इस मौके पर प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) नीरज कुमार गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से काम किया जा रहा है. शिक्षकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा आयोग के गठन की कार्रवाई की जा रही है. इसी प्रकार राज्य स्तर पर विश्वविद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए उच्च शिक्षा समिति का गठन भी किया जाएगा. ■


चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

गणतन्त्र दिवस एवं महाशिवरात्रि की गोरखपुरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

भूपेन्द्र कुमार सिंह 'सोनू'
युवा नेता
संपर्क-09453646099
बहुजन समाज पार्टी, गोरखपुर

BSNL Connecting India
गणतन्त्र दिवस एवं महाशिवरात्रि की गोरखपुरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

इंद्रेश्वर पासी
संपर्क-09451741245
प्रो. इंद्रेश्वर पासी, गोरखपुर
फ्रेंचायजी-भारत संचार निगम लि.

# बिजली दरों में कमी से इंकार

एक तरफ पूरे देश में बिजली दरों में कमी के लिए बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की जनता को बिजली दरों में किसी भी तरह की राहत से इंकार कर रही है. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि प्रदेश में बिजली दरों के मामलों में राज्य सरकार के मंत्री व मुख्यमंत्री विरोधाभाषी बयान दे रहे हैं. पिछले दिनों सपा प्रवक्ता व प्रदेश सरकार के मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने उपभोक्ता परिषद के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि प्रदेश में बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी. वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली दरों में कमी का अधिकार नियामक आयोग को है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने भी मुख्यमंत्री के बयान को सही बताया है. उन्होंने कहा कि बिजली दर वृद्धि का जो प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है, वह प्रदेश सरकार के इशारे पर ही भेजा गया है. श्री वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता परिषद बिजली दरों में कमी करने के लिए अन्य प्रदेशों की तरह प्रदेश सरकार से खैरात या सब्सिडी नहीं मांग रहा है, बल्कि बिजली दरों में कमी करने के लिए अनेक उपाय बता रहा है, जिसे लागू करना और कराना राज्य सरकार का नैतिक दायित्व है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने सवाल उठाया है कि पिछले दिनों जब प्रदेश में टैरिफ फिक्सिंग के आधार पर बिजली दरें बढ़ाईं गईं तो राज्य सरकार कहां थी और अब जबकि उपभोक्ता परिषद द्वारा राज्य सरकार के सामने बिजली दर कम करने के अनेक सुझाव पेश किए जा रहे हैं तो राज्य सरकार पूरा मामला नियामक आयोग पर डाल रही है. उन्होंने कहा कि अगर बिजली दरों में बदलाव का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है तो पिछले दिनों प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया, जिससे प्रदेश की जनता को बिजली दरों से राहत की उम्मीद जगी. उन्होंने कहा कि बिजली दरों में बदलाव का अधिकार नियामक आयोग को है, लेकिन बिजली दरों में वृद्धि व कमी करने का प्रस्ताव राज्य सरकार व बिजली कम्पनियों का है. ऐसे में सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती. वर्मा ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से पिछले दो वर्षों में आम जनता की बिजली दरो में वृद्धि की है, वह पूरी तरह गलत है और जब देश में बिजली दरों में कमी के लिए बहस चल रही है तो राज्य सरकार जनता को इससे राहत देने से बच रही है, यह कहीं से भी उचित नहीं है. ■

राजेश चौरसिया
feedback@chauthiduniya.com

64वें गणतन्त्र दिवस पर पीलीभीत जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनायें


सुनील कुमार
"ड्रग इंस्पेक्टर"
जनपद पीलीभीत

कार्यालय नगर पंचायत चन्दौली, जनपद-चन्दौली

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2014) के पावन पर्व पर नगर पंचायत, चन्दौली अपने नागरिकों का हार्दिक अभिनन्दन करती है.

- नगर के सर्वांगीण विकास हेतु करों का भुगतान समय से करें.
- अपने भवन निर्माण के पूर्व मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं, बिना मानचित्र स्वीकृत करवाए भवन निर्माण करना अपराध है.
- कूड़ा-करकट नगर पंचायत द्वारा रखे गए कूड़ादान में फेंके. कूड़ा उठ जाने के पश्चात सड़क एवं नालियों में कूड़ा न फेंके.
- यह नगर आपका है. इसे स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में सहयोग करें.
- जल ही जीवन है. पेयजल का दुरुपयोग न करें. खुली टोटियों को बंद रखें.
- पथ प्रकाश स्तंभों एवं उपकरणों को क्षति न पहुंचाएं.
- जन्म-मृत्यु का पंजीयन समय से कराएं.


मीनाक्षी देवी
अध्यक्ष
नगर पंचायत
चन्दौली

राजेन्द्र प्रसाद
अधिशासी
अधिकारी
नगर पंचायत
चन्दौली

सभासद गण- श्रीमती मंजू देवी, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री रमेश यादव, श्रीमती रेखा देवी, श्री दरोगा प्रसाद, श्री बंशी प्रसाद, श्री सुनील सिंह, श्री अलगू प्रसाद, श्री मु. यासीन, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती पद्मावती देवी, श्री नरायन दास, श्रीमती जरीना बेगम, श्री विजय जायसवाल, श्री राजीव कुमार.
नामित सदस्य गण- श्री शाहिद अहमद खां, श्री रोहित यादव, श्रीमती इशरतजहां.
संख्या- मेमो / न.प.च./ 2013-14/दिनांक 24 जनवरी, 2014


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, संतकबीर नगर द्वारा संचालित योजनाएं

1. छात्रवृत्ति योजना
2. मिनी आई0टी0 योजना
3. हमारी बेटी इसका कल योजना
4. मदरसा आधुनिकीकरण योजना
5. मदरसों की मान्यता प्रदान किया जाना
6. मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाना
7. अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाना
8. शादी अनुदान योजना
9. दशमोत्तर कक्षाओं में शुल्क प्रतिपूर्ति योजना
10. भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना
11. मेरिट कम-मीन्स योजना
12. वक्फ संपत्तियों का भू-अभिलेख अमल दरामद
13. वक्फ संपत्तियों पर अवैध कैंजो का हटाया जाना
14. मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेन्ट प्लान (MSDP)
15. कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों के चहारदीवारी का निर्माण


अजय कुमार यादव
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संत कबीर नगर

एस एन तिवारी
मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर

डॉ. इन्द्रवीर सिंह यादव
जिलाधिकारी, संत कबीर नगर

गणतन्त्र दिवस एवं महाशिवरात्रि की गोरखपुरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

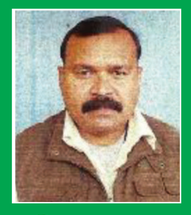

विजय यादव
सपा नेता
संपर्क-08858914177
यादव कॉम्प्लेक्स, नौसढ़ (गोरखपुर)

शिक्षा के क्षेत्र में जनपद में अग्रणीय बाल शिक्षा निकेतन उत्तरोत्तर विकास के पथ पर
64वें गणतन्त्र दिवस की बहराइचवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं


अध्यक्ष | प्रबन्धक
प्रबन्ध समिति, बाल शिक्षा निकेतन, बहराइच

64वें गणतन्त्र दिवस पर पीलीभीत जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनायें

HP
प्रो0 पुनीत गोयल
दादू गैस एजेन्सी जनपद पीलीभीत

64वें गणतन्त्र दिवस पर तहसील पूरनपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनायें

जाकिर अली
शाहिद अली
बरकाती मेडिकल स्टोर
शेरपुर रोड, तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत






अरुण कुमार, सम्भावित प्रत्याशी, बहराइच (सु.) लोकसभा क्षेत्र
64वें गणतन्त्र दिवस की बहराइचवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक :- समस्त जनपदवासी एवं भाजपा कार्यकर्तागण, बहराइच

कार्यालय नगरपालिका परिषद, बस्ती

यह शहर आपका अपना है. इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हमें सहयोग प्रदान करें

नगरपालिका बस्ती निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहते हुए 63वें गणतंत्र दिवस 2014 के अवसर पर नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन के साथ अनुरोध करता है :
1-गृह कर/जल कर/जल मूल्य एवं अन्य देयों का समय से भुगतान कर नगर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें.
2-जन्म/मृत्यु का पंजीयन अपने निकटतम सीएफसी सेंटर के द्वारा समय से ऑनलाइन कराएं.
3-जल ही जीवन है. पानी की टोटी को खुला न छोड़ें. प्रयोग के बाद तुरंत बंद कर दें.
4-नाला/नाली/सड़क, पटरी, चौराहे पर अतिक्रमण न करें. यह संज्ञेय अपराध है.
5-मार्ग प्रकाश बिंदुओं को क्षतिग्रस्त न करें.
6-सड़े-गले खाद्य पदार्थ का प्रयोग न करें.
7-अपने पालतू जानवरों को खुला न छोड़े.
8-नगर के चौराहे पर स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर आदि न चिपकाएं.
9-कूड़ा-करकट इधर-उधर न फेके, अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों के सामने कूड़ा पात्र रखकर उसी में कूड़ा डालकर पालिका के सफाई कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें.
10-20 माइकान से कम के पॉलीथीन का प्रयोग न करें और न ही नालियों में पालीथीन फेकें .

(डा.आर.पी.श्रीवास्तव)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद बस्ती

(अशोक कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद बस्ती

मा. सदस्य गण-श्रीमती विमला देवी, श्री मती सुभावती, श्री सर्वेश यादव उर्फ विक्की, श्री अरशद मसूद, श्रीमती इंद्रावती, श्रीमती पिंकी, श्री महेंद्र कुमार, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री हसन शादाब, श्रीमती पूनम देवी, श्रीमती दीपा सिंह, श्री मो.जावेद, श्रीमती आमिना खातून, श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती गीता शुक्ला, श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव, श्री मो. इद्रीश, श्री कमरूलहुदा, श्रीमती शकुंतला देवी, श्रीअययूब, श्रीमती सरला शुक्ला, श्री दीप आनंद, श्री सदानंद शर्मा, श्रीमती सरोज एवं श्री जगदीप श्रीवास्तव जिला योजना, श्री संत प्रकाश त्रिपाठी, श्री अब्दुल रजा उर्फ ईदू, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री सुमेश्वर प्रसाद यादव, श्री रियाज अहमद.

64वें गणतन्त्र दिवस पर पीलीभीत जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनायें


प्रमोद कुमार श्रीवास्तव
"ब्यूरो चीफ चौथी दुनिया"
जनपद पीलीभीत (बरेली मण्डल) उ.प्र.

64वें गणतन्त्र दिवस पर पीलीभीत जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनायें


राजकुमार मौर्या
"स्वतंत्र पत्रकार"
ग्राम बिहारीपुर इटौरिया, थाना-गजरौला, पीलीभीत


मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

निर्मल भारत अभियान

बहू-बेटियां दूर न जाएं। शौचालय घर में बनवाएं ॥


पंचायती राज मंत्री, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

- ग्राम पंचायत स्तर पर घर-घर जाकर गहन संपर्क अभियान चलाया जाना.
- निर्मल भारत अभियान अंतर्गत बेस लाइन सर्वे कराकर व्यक्तिगत शौचालय से अनाच्छादित परिवारों को जनपद स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करना.
- खुले में शौच मुक्त ग्राम बनाने हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक में चर्चा.
- व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय हेतु मांग का सृजन करना.
- स्वच्छता रैली में महिलाओं एवं स्कूली बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित कराना.
- उत्तम गुणवत्ता के शौचालय निर्माण हेतु राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण.
- नुक्कड़ नाटक/डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शन के द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाना.
- ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षक-अभिभावक संघ, स्कूल स्वच्छता क्लब, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, एएनएम एवं ग्राम प्रेरक की उपस्थिति में ग्राम सभा की खुली बैठक का आयोजन कर निर्मल ग्राम पुरस्कार पर चर्चा.
- वर्ष 2013-14 में 26202 व्यक्तिगत शौचालयों के लक्ष्य को पूर्ण कराना.
- सामुदायिक महिला शौचालयों के प्रयोग पर बल दिया जाना.
- अभियान काल में जनपद के जे.ई./ए.ई.एस. प्रभावित गांवों के साथ-साथ समस्त गांव की साफ-सफाई हेतु विशेष सफाई कार्यक्रम एवं फॉगिंग कराया जाना.
- शौचालय निर्माण हेतु नई संशोधित दर मु. 10000/- की दर से (केंद्राश मु. 3200/-,राज्यांश मु. 1400/-,मनरेगा से मु. 4500 /- एवं लाभार्थी अंश मु.900/-) 17920 ए.पी.एल. एवं 8282 बी.पी.एल. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कराया जाना.

जिस घर में शौचालय नहीं। वह घर अधूरा है ॥


आनंद प्रकाश त्रिपाठी
जिला पंचायत राज अधिकारी, संत कबीर नगर

एस एन तिवारी
मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर


(डॉ. इन्द्रवीर सिंह यादव)
जिलाधिकारी, संत कबीर नगर